सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — सोमवार, तिथि 16 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 27 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्व0 रामविलास पासवान जी को, आपके आर॰जे॰डी॰ के विधायक के द्वारा गलत टिप्पणी की गई है । मैं यह मांग करता हूँ कि ये लोग माफी मांगे । ये लोग दलित विरोधी हैं, हुजूर । ये लोग दलित विरोधी हैं, हमारे संस्थापक का ये लोग विरोध किये, ये लोग गलत बयानबाजी किये हैं । हम चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर माफी मांगे । हुजूर, एकदम, ये लोग हमेशा हमारे नेता के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं । हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमलोग दिल से, ये हमारे संस्थापक के प्रति...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । कृपया शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान जारी)

अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री श्याम रजक ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री श्याम रजक । माननीय सदस्यगण, शांति–शांति । प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

शून्यकाल में आयेगा । प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, आपकी बात आ गई है, कृपया बैठ जाएं । अभी प्रश्नकाल है । तख्ती हटा दें । माननीय सदस्यगण, अपने–अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया शांति बनाये रखें । अभी प्रश्न काल चल रहा है, सदन चलाने में सहयोग करें ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, शांति–शांति ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी, विषय आ गया है, कृपया आप बैठ जाइये । प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

राजू तिवारी जी, प्लीज बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री श्याम रजक । माननीय मंत्री, उद्योग विभाग । डॉ॰ दिलीप जायसवाल जी ।

(व्यवधान जारी)

सभी लोग बैठ जाएं । प्लीज बैठिये । माननीय मंत्री, उद्योग विभाग । डॉ॰ दिलीप जायसवाल जी ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, सभी लोग बैठ जाइये । प्लीज बैठ जाइये, अभी प्रश्न काल है । शांति–शांति । राजू तिवारी जी, बैठ जाइये, प्लीज बैठ जाइये । आपने अपना प्रोटेस्ट कर दिया ।

(व्यवधान जारी)

<u>प्रश्नोत्तर काल</u>

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–33, श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या–188, फुलवारी (अ॰जा॰))</u>

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयों का भारत सरकार के साथ एम॰ओ॰यू॰ अंतर्गत 35 करोड़ 28 लाख लीटर, 1060 किलोलीटर/दिन एनुअल ऑप्टेक क्वांटिटी निर्धारित किया गया था ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम समय देंगे । अभी आप बैठ जाइये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, इस संबंध में बिहार में डेडिकेटेड इथेनॉल इकाइयों द्वारा 1602 कि॰ली॰/दिन के उत्पादन...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी, बैठ जाइये । आपको मौका देंगे । आपलोग भी बैठिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, क्षमता का संयंत्र लगाया गया है । इथेनॉल उत्पादन करने वाले इकाइयों तथा....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपलोग भी बैठिये ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, तेल विपणन कंपनियों के बीच हुए समझौता से यह स्पष्ट किया गया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित ऑप्टेक क्वांटिटी के अनुरूप इथेनॉल की खरीद की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया आपलोग बैठ जाएं ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन तेल कंपनी, विपणन कंपनियों....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मार्शल, तख्तियां हटा दें ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, और संभावित इथेनॉल उत्पादकों के बीच हस्ताक्षरित तेल समझौतों में 10 वर्ष की अवधि के लिए 100 परसेंट इथेनॉल उत्पादन के खरीद का आश्वासन दिया गया था और इस तरह जो है माननीय सदस्य बिहार विधान....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । राजू तिवारी जी, कृपया आप बैठ जाएं । हम जीरो ऑवर में आपको मौका देंगे, कृपया अभी बैठ जाइये । अभी माननीय मंत्री जी का जवाब हो रहा है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है कि अभी माननीय मंत्री जी का जवाब हो रहा है ।

(व्यवधान जारी)

राजू तिवारी जी, आपकी बात आ गयी है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी, पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

राजू तिवारी जी, आपकी बात आ गयी है । प्लीज बैठ जाइये । कृपया क्वेशचन ऑवर में सहयोग करें ।

(व्यवधान जारी)

राजू तिवारी जी, आपकी बात आ गयी है । बैठ जाइये, प्लीज बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अब क्वेश्चन ऑवर को चलने दीजिये । माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, इनका जो जवाब आया है लेकिन मेरा यह कहना है कि भारत सरकार ने इथेनॉल खरीद पर बिहार का कोटा आधा कर दिया है जबकि पूरे देश में 88 इथेनॉल प्लांट हैं । सरकार अन्य राज्यों में कटौती

नहीं की है । महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत लिया जाता है, मध्य प्रदेश में 53 प्रतिशत, झारखंड में 57 प्रतिशत, कर्नाटक में 58 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 62 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 65 प्रतिशत, पंजाब में 67 प्रतिशत, हरियाणा में 70 प्रतिशत, उड़ीसा में 73 प्रतिशत, जम्मू–काश्मीर में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । महोदय, जब वहां पर इतना ज्यादा स्तर पर इथेनॉल खरीदा जा रहा है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अभी 08 दिसंबर को बक्सर गये थे और उप मुख्यमंत्री जी भी बक्सर गये थे। नवानगर में भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया था और वहां उन्होंने आदेश दिया था, 100 प्रतिशत इथेनॉल खरीद का आश्वासन भी दिये थे लेकिन इसके बावजूद यहां आधा कटौती हो गया जिसके कारण 60 प्रतिशत इथेनॉल कंपनियां बंद हो गई हैं, 700 से ज्यादा मजदूर जो काम करते थे सब बेकार हो गए हैं जबकि हमारे सरकार की नीति है कि हम रोजगार देंगे, 700 लोगों का रोजगार छिन गया है और...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री श्याम रजक : महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करेगी कि आधा जो हमारा कटौती किया गया है, वह कटौती को खत्म करे और पेट्रोल कंपनियों के साथ जो समझौता हुआ है कि 15 प्रतिशत वह लेगा लेकिन उसमें भी वे नहीं ले रहे हैं तो इन शर्तों पर पेट्रोल कंपनियों के साथ वार्ता कर, इस बिहार की 22 इथेनॉल कंपनियां जो बंद पड़ रही हैं उसको फिर से चालू कर और यहां के किसानों का, जो मक्का के किसान हैं उनको और 700 मजदूरों को जिनका रोजगार छिन रहा है, उसको करने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो डेडिकेटेड इथेनॉल इकाई भारत सरकार के साथ एम॰ओ॰यू॰ हुआ था, उस एम॰ओ॰यू॰ में था कि 1060 कि॰ली॰/दिन यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर इथेनॉल, इनका एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार की तेल कंपनी खरीदेगी लेकिन इन लोगों के द्वारा उत्पादन जो है 1060 कि॰ली॰/दिन के विरुद्ध में 1602 कि॰ली॰/दिन उत्पादन क्षमता का संयंत्र इनके पास है लेकिन एग्रीमेंट जो हुआ था, भारत सरकार ने जो कोटा एलॉट किया था वह 1060 कि॰ली॰/दिन का ही कोटा एलॉट किया था लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार को, चूंकि तेल की जरूरत जब ज्यादा रहती है और तेल कंपनी अगर उससे ज्यादा, एलॉटमेंट से ज्यादा बनाती है तो भारत सरकार उस तेल को परचेज कर लेती थी लेकिन इस बीच में तेल का जो वेयरहाउस लॉजिस्टिक जहां था वहां पर तेल की मात्रा बढ़ गयी तो उन लोगों ने, जो परचेज कर रहे थे उसका

उन्होंने कोटा घटा दिया है । हमलोगों ने बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार को लिखा है कि आप हमारा कोटा बढ़ाइये क्योंकि इथेनॉल का जो हमारे यहां फैक्ट्री है, उनकी 1602 कि॰ली॰/दिन की क्षमता के उत्पादन की शक्ति है तो सभी इथेनॉल उनसे परचेज किया जाय । हालांकि वे 1060 कि॰ली॰ के एग्रीमेंट के तहत ही लेने के लिए बाध्य हैं लेकिन फिर भी हमलोगों ने एक पत्र लिखा है और हमको लगता है कि जल्द इस पर कोई निदान निकल जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू जी, आपको पूछना है तो पहले आप पूछ लीजिये ।

टर्न–2/अंजली/16.02.2026

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है, लेकिन उस पर गंभीरता के साथ, उनके साथ वार्ता करके उसको चालू कराना चाहते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : सरकार गंभीर है ।

श्री श्याम रजक : नहीं, सरकार गंभीर नहीं लग रही है ।

अध्यक्ष : जवाब नहीं देखे हैं ?

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एकदम निश्चित । मैंने दो बातें कही हैं । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि 1060 किलो लीटर यानी 35 करोड़ 28 लाख लीटर इथेनॉल परचेज करने का एग्रीमेंट का एलॉटमेंट हुआ था, लेकिन ये लोग इथेनॉल बना रहे हैं 1602 किलो लीटर पर डे, इनकी क्षमता है । उसके बाद भी हमने पत्र लिखा है और बहुत गंभीरता के साथ हम प्रयासरत हैं कि इथेनॉल कंपनी में, जो इथेनॉल की फैक्ट्री है, वे जितना तेल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, हम उनको परचेज करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किए हैं और बहुत गंभीरता के साथ हम इसको जल्द ही कोटा भरवाने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : रजनीश जी, आप बोलिए ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जब इथेनॉल फैक्ट्री लगने की बात हुई, तो बहुत बड़ी उम्मीद मक्का किसानों के मन में जगी, बिहार में मक्का का उत्पादन बहुत अधिक होता है और शायद एशिया में मक्का उत्पादन में अपना बिहार आगे है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ।

श्री रजनीश कुमार : और जब यह बंद हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने अभी स्वीकार किया कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण उसका असर पड़ा है । अभी इसके कारण मक्का का जो उत्पादन हुआ इस उम्मीद पर कि इथेनॉल फैक्ट्री में खरीद लिया

जाएगा, लेकिन अब नहीं खरीदा जा रहा है, इसके कारण किसानों को मक्के का मूल्य का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और मक्का का किसान त्राहिमाम कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या किसानों की जो उम्मीद थी और जो उत्पादन हुआ और आज जो मक्का उसका रखा हुआ है, उसका जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : श्री कुमार सर्वजीत जी, आप भी प्रश्न पूछ लीजिए । एक ही बार जवाब दीजिएगा । एक–एक करके पहले सब पूछ लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने....

अध्यक्ष : पूरक पूछिएगा पूरक । कहां–कहीं पर मत जाइएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने मक्के का उत्पादन बढ़ाया । आप लगभग बिहार में 12 ऐसे इथेनॉल की इंडस्ट्री चालू कराए हैं, भारत सरकार नहीं ले रही है, इंडस्ट्री का जो मालिक है, वह बैंककरप्ट हो रहा है, उसके पास पैसा इंट्रेस्ट देने के लिए नहीं है और बैंक उसको नोटिस कर रही है, उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, अगर इस परिस्थिति में जो 22 इथेनॉल फैक्ट्री बनाने के लिए जो आपने एम0ओ0यू0 साइन किया, अब तो वह इंडस्ट्री नहीं आएगी महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री कुमार सर्वजीत : और इंडस्ट्री के मालिक कह रहे हैं कि हम बैंककरप्ट हो गए, अब हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली है, तो जब आप जान रहे थे कि भारत सरकार नहीं खरीद सकती है, तो मक्के का उत्पादन किसान को परेशान करने लिए आपने क्यों बढ़वाया ।

अध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : भारत सरकार अगर जब नहीं खरीद सकती है तो फिर आप बिहार के लोगों को XXX आश्वासन देकर इंडस्ट्री क्यों लगवाया ।

अध्यक्ष : XXX शब्द को हटा दिया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत : क्या बैंक जो क्रप्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री के मालिक, जब तक उसका इथेनॉल नहीं खरीदा जाता है, क्या आप उसके बैंक का सूद माफ करने के लिए सरकार विचार करती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : बैठिये । जिवेश जी, अंतिम आप हैं । पूरक प्रश्न पूछ लीजिए । कोई नई बात हो तो बताइएगा ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, आज नई बात ही बता रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, केवल भारत सरकार तेल कंपनियों के माध्यम से इथेनॉल खरीदे, एक यह व्यवस्था है, इससे अलग भी व्यवस्था है कि पूरे देश में इथाइल अल्कोहल का कंजप्शन भारी मात्रा में है । होम्योपैथी मेडिसीन के अंदर इसका उपयोग होता है । साथ–ही–साथ बिहार में शराबबंदी है, बिहार के बाहर बड़े पैमाने पर इथाइल अल्कोहल का

कंजप्शन है फैक्ट्रियों में । क्या सरकार उन कंपनियों के माध्यम से यहां जो एक्सेस इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है 1060 किलो लीटर से अधिक 1602 किलो लीटर, शेष 602 किलो लीटर इथेनॉल का कंजप्शन वहां कराने का विचार रखती है ? मार्केटिंग की भी व्यवस्था करे न सरकार ।

अध्यक्ष : जी बिल्कुल । बैठ जाइए । बैठ जाइए, सुन लीजिए । जवाब बहुत अच्छा रहा। दुबारा जवाब बता दीजिए माननीय मंत्री जी ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, मैं तीन बातें बताना चाहूंगा, पहला तो यह कि भारत सरकार ने 1060 किलो लीटर पर डे यानी 35 करोड़ 28 लाख ही हमको कोटा दिया था लीटर बनाने के लिए, लेकिन जो हमारा प्लांट लगा वह 1602 किलो लीटर यानी 50 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का वह उत्पादन कर रही है, तो कोटा तो भारत सरकार का पहले से 1060 किलो लीटर पर डे ही था, लेकिन...

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : बैठे–बैठे मत बोलिए । जवाब को सुनना चाहिए ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : लेकिन भारत सरकार को इथेनॉल लेने में अगर कोई दिक्कत नहीं था, तो सब इथेनॉल परचेज कर लेती थी, लेकिन कोटा निर्धारित है 1060 किलो लीटर ही पहली बात । दूसरी बात यह कि इस तरह का मीडिया में भ्रामक प्रचार भी दिया जा रहा है, इथेनॉल फैक्ट्री बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, तीन बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आ रही हैं । मैं बताना चाहूंगा कि हम इंसेंटिव देते हैं किसी भी फैक्ट्री को, तो हमारी रिपोर्ट में जो उन्होंने, चूंकि हमसे करोड़ों–करोड़ रुपया फैक्ट्री वाले इंसेंटिव भी लेते हैं पूरे बिहार में, 1700 करोड़ रुपए का अभी मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी को धन्यवाद दूंगा कि इंसेंटिव उन्होंने एलॉट किया है और मेरी रिपोर्ट में जो आया है जिसमें उन्होंने इंसेंटिव क्लेम किया है कि दिनांक–23.12.2025 से 25.12.2025 तक यानी दो दिन के लिए फैक्ट्री बंद रही है और दिनांक–28.12.2025 से लेकर 31.12.2025 तक चूंकि दिसंबर का रिपोर्ट उन्होंने जनवरी में भेजा कि बंद कितना दिन रहा, तो कुल सात दिनों तक यह फैक्ट्री उन्होंने बंद की और 2026 में, जनवरी का रिपोर्ट अभी वे लोग भेजेंगे, तो आधा हो गया, फैक्ट्री बंद हो गयी, मजदूर बेरोजगार हो गए, तो भाई जब इंसेंटिव आप क्लेम कर रहे हैं, आप इसमें लिखते हैं कि दो दिन ही फैक्ट्री बंद है, ये उन्हीं की रिपोर्ट है और मैं हाउस में बोल रहा हूं । सही बात है कि जो भी फैक्ट्री खुलती है, उसके साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता है, जितना उनकी कमाई हो तो अच्छा है, कोई भी बिजनेस मैन फैक्ट्री लेकर आता है तो उसकी जिसकी कमाई हो निश्चित रूप से हम सभी सदन के सदस्य हैं और हम सब लोग चाहेंगे कि फैक्ट्री वाले

आएं तो फले–फूलें । हमलोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि ये और फल–फूलें, ये और कमाई करें, क्योंकि बिजनेस में आए हैं, प्रोफेशन में आए हैं, तो हमें उनकी चिंता है, तो हमलोग कोटा बढ़ाने के लिए बहुत ही गंभीरता से और अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा भी रहे हैं और हम चाहेंगे तो वहां बात भी करवाएंगे, तो हमलोग कोटा बढ़वाएंगे । लेकिन सच्चाई यही है कि कोई 6 महीना बंद नहीं है, रिपोर्ट में आ गया है कि मात्र दो दिन बंद है, तो यह कागजी रिपोर्ट है हमारा, फिर भी हम भारत सरकार से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह कोटा बढ़ जाए, और भी फैक्ट्री खुले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यही मैं बताना चाहूंगा ।

अध्यक्ष : श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता ।

(व्यवधान)

सब बात आ गई, सारी बातें आ गईं, सरकार प्रयासरत है, सरकार गंभीर है । बैठिए । बैठ जाइए । समय खत्म हुआ । आई0पी0 गुप्ता जी, खड़े हो जाइए । माननीय सदस्य, श्री आई0पी0 गुप्ता जी ।

(व्यवधान)

सब बात आ गई है । सारी बात सरकार ने रख दी है, आप जाकर के सुन लीजिए । सरकार प्रयासरत है । बैठिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इथेनॉल के ऋण की क्या स्थिति है उसका भी आकलन कर लिया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है, आकलन कर लिया जाएगा । माननीय सदस्य, श्री आई0पी0 गुप्ता जी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं॰–34 श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं॰–75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में ड्रग्स माफिया के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है । वर्ष 2025 में पूरे राज्य अन्तर्गत बिहार पुलिस द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 2161 कांड दर्ज किये गये हैं, जिसमें 3520 प्राथमिकी अभियुक्तों में से 2958 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । इन कांडों में गांजा–27884.06 कि०ग्रा०, चरस–352.661 कि०ग्रा०, हेरोईन+स्मैक+ब्राउन शुगर–138.202, कोकीन–0.03 कि०ग्रा०, डोडा–2377.91 कि०ग्रा०, अफीम–71.946 कि०ग्रा० बरामद किया गया है । इसके अतिरिक्त नशीली दवाओं के तहत 325093 बोतल कोडिन बेस्ड कफ सिरप, टैबलेट 342678 पीस एवं इंजेक्शन–23422 पीस जप्त किया गया है ।

2. मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एक स्वतंत्र इकाई मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन दिनांक–17.09.2025 को राज्य सरकार द्वारा किया गया है ।

3. दिनांक–21.01.2026 से राज्य के जिलों में पूर्व से गठित अनुमंडलवार Anti Liquor Task Force (ALTF) अब मद्यनिषेध कार्यों के अतिरिक्त Anti Narcotics Task Force (ANTF) के रूप में भी कार्य कर रही है ।

4. राज्य में वर्ष–2024–25 में अफीम की कुल–1041.006 एकड़ अवैध खेती को विनष्ट किया गया है । वर्ष–2025–26 में विनष्टीकरण की कार्रवाई जारी है ।

5. मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु NCORD (Narco Coordination Centre) Mechanism के तहत राज्य स्तरीय समिति की बैठक मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है । साथ ही इस कार्य में संलग्न केन्द्रीय एजेंसियों एवं राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय हेतु नियमित रूप से बैठक होती है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं जो क्वेश्चन उठाया था, यहां सदन में मौजूद एक–एक माननीय सदस्यगण इस क्वेश्चन से इत्तेफाक रखेंगे और मुझे लगता है कि...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न । उत्तर मिला है न आपको ?

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जी महोदय, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, थोड़ा–सा इस पर बहस करने का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष : बहस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑवर है । आप पूरक प्रश्न पूछिये । आपको अधिकार है पूरक प्रश्न पूछने का । सीधे प्रश्न पूछिये माननीय मंत्री जी से ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : हुजूर–हुजूर । जवाब मिला है और मेरा सवाल था कि क्या यह सही है कि गांव और शहर के यह जो ड्राई ड्रग्स है अपने कब्जे में ले रहा है, सरकार ने जवाब दिया है और 5 प्वाइंट में जवाब दिया है, बड़ा लंबा जवाब है और जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि यह रूटीन वर्क है । जैसे–कितने एफ0आई0आर0 हुए, कितने अरेस्ट हुए, आप देखेंगे कि पूरे साल में...

अध्यक्ष : आप सीधे पूरक पूछिये । तीन पूरक पूछने का अधिकार है, पूरक प्रश्न पूछ लीजिए आप । जवाब हो जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, सुना जाए । यह जो इंटेनसिटी है इसका, सारे जो जवाब आए हैं, सर्टेन सरकार काम कर रही है, लेकिन एक सर्टेन टारगेट ग्रुप्स के लिए काम कर रही थी, अब टारगेट ग्रुप्स बदल गए हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस बदल गया है, यह जो टारगेट ग्रुप पहले थे बड़ों के लिए ऐसा लगता है कि सारे चीजें हैं लेकिन अब जो टारगेट ग्रुप है यह 14 से 25 वर्ष के बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स आज...

अध्यक्ष : क्वेश्चन में आ गया है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : और इसी से रिलेटेड चीजें हैं, सरकार अगर टारगेट ग्रुप्स को देखकर ये चीजें ऐक्शन में आती हैं, तो यह जो रिपोर्ट आई है, जो जवाब है उसका तरीका बदल जाता है । मैं सहरसा से आता हूं, सहरसा के शाम 7.00 बजे के बाद आप किसी भी चाय की दुकान पर चले जाएं...

अध्यक्ष : ठीक है । आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए न ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : पूरे बिहार में है ।

अध्यक्ष : जवाब में पांच आया है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : कॉलेज में, नवोदय विद्यालय में, आई0टी0आई0 स्कूल में छोटे–छोटे बच्चे ले रहैं, मैं कहता हूं, सरकार से मेरा यह निवेदन है कि ये जितने भी कानून बनें, सिर्फ एक कानून अभी नया आया है कि वह मद्यनिषेध सरकार ने बनाई है ।

अध्यक्ष : अब जवाब...

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं वहीं आ रहा हूं ।

अध्यक्ष : अब पूरक पर आ जाइए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं वहीं पर आ रहा हूं । जब आप टारगेट ग्रुप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो तरीका है वह बदल जाएगा । जिस तरह से शराब नीति स्पेशिफिक लाया और बंद गया है, उसी तरह इन बच्चों को जो 14 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, 25 वर्ष के बच्चे हैं, कॉलेज में, नवोदय विद्यालय सहरसा के चलने लायक नहीं है ।

अध्यक्ष : सारी बातें क्वेश्चन में आपकी आ गयी है । सरकार से सीधी बात कीजिए आप। पूरक पूछिये एक लाइन में ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सुना जाए महोदय । अभी पटना के ढेर सारे अखबार में आया कि एच0आई0वी बच्चों में बढ़ रहा हैं लेकिन ये बच्चे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह जगह डिबेट करने का नहीं है, क्वेश्चन ऑवर है, और भी मेम्बर का क्वेश्चन है ।

(व्यवधान)

---

xxx- आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, मैं पूरक प्रश्न पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार । अब हम आगे बढ़ गए ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखें । आप जल्दी पूरक पूछिये । समय नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, क्या सरकार....

(व्यवधान)

सर, इन्हीं लोगों को अध्यक्ष की तरफ बैठा दिया जाए इससे ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : क्या सरकार इस न्यू टारगेट ग्रुप से जो बच्चे सूखे नशे जैसे सुलेशन, व्हाइटनर पी रहे हैं, उसको लेकर कोई स्पेसिफिक नीति लेकर आएगी? यह मेरा पहला पूरक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । अच्छा तीनों पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : यह जो सिडेटिव ड्रग्स हैं, जिसके वजह से एच0आई0वी0 और जो रिलेटेड बीमारियां हो रही है, क्या कोई स्पेसिफिक ऐसा होगा जो यह पता कर सके जो एच0आई0वी0 हुआ है, यह ड्रग्स से हुआ हैं, ड्राई ड्रग्स से हुआ हैं या कैसे हुआ हैं ?

अध्यक्ष : अब तीसरा पूरक पूछिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : क्या इन दो चीज पर सरकार काम करेगी ।

अध्यक्ष : अच्छा, तीसरा पूरक हो गया है ? अब बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब में दिया गया है कि सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की है । चाहे वह हेरोइन हो, स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो या कोकीन हो, अफीम हो, सब के खिलाफ विस्तार से कितनी एफ0आई0आर0 हुई, कितनी कार्रवाई की गयी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने इसके लिए एक यूनिट भी खड़ी कर दी है । नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बनाया है जो पूरी तरह इस पर कार्रवाई कर रहा है । किस बॉर्डर के किस इलाके में, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं सहरसा, वह जो पूरा बॉर्डर का इलाका है, उसको हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरी जांच करा रहे हैं । अब तो यूनिट भी हम बना रहे हैं । बॉर्डर पर भी अलग से एक डी0आई0जी0 को प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। नारकोटिक्स के लिए अलग से यूनिट स्थापित कर रहे हैं । सूखे नशे पर सरकार हर हालत में कार्रवाई करेगी । जहां भी सूचना देंगे, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार । पूछिये ।

(व्यवधान)

इन्द्रजीत जी बैठिए । सब बात क्लियर है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–35, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग । उत्तर पढ़ दिया जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो हमने बता दिया है कि जो पत्रकारों को पेंशन के लिए अनुमान्यता है, वह सिर्फ अपने बिहार में ही नहीं है। जहां कहीं भी पेंशन मिल रही है, वहां भी अनुमान्यता की शर्तें जितनी बिहार में है, कहीं उससे अधिक है । इसलिए यह तो मिनिमम है, 20 वर्ष की उनकी सेवा होनी चाहिए और यह टी0डी0एस0 वगैरह जो काटने की बात कह रहे हैं पी0एफ0 वगैरह, यह तो 20 वर्ष वह सर्विस में रहे हैं, इसके प्रमाण के रूप में लिया जाता है । शर्त तो एक है कि 20 वर्ष की उनकी सेवा अवधि होनी चाहिए और 20 वर्ष की सेवा अवधि है, यह तो जो उनके एंप्लॉयर हैं या जिस भी मीडिया समूह के साथ वह कार्यरत हैं, वह उनको वहां से सैलरी दिए होंगे, पी0एफ0 काटे होंगे, जो भी रिकॉर्ड होगा, उससे वेरीफाई कराने के लिए यह सब मांगा जाता है । यह सब कोई अलग से शर्त नहीं है और जहां तक पेंशन की बात है, महोदय, मेरे पास अन्य कई राज्यों के बारे में सूचना है कि जितनी पेंशन बिहार सरकार दे रही है, उतनी किसी दूसरे राज्य में नहीं दी जाती है। महोदय, फैमिली पेंशन भी जो एक बार मतलब जो पत्रकार हैं, उनकी असामयिक दुखद मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के रूप में भी जो अनुमान्यता है, वह जो बिहार में है वह किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है । इसलिए और कहीं भी कोई इस तरह का पेंशन या कुछ भी दिया जाता है, तो मिनिमम सेवा शर्त तो रहती ही है अजय जी । इसलिए यह एक ही साथ जो पत्रकार मान लीजिए आज हो गए, सर्विस में भी बिहार सरकार के यहां भी एक पेंशनेबल मिनिमम सर्विस करने की अवधि होती है । इसलिए महोदय यह उचित है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह से है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मो0 कमरूल होदा ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक इतना ही है कि जो जे0पी0 सेनानी है उनके लिए एक शर्त रखी है कि अगर उसे कोई सबूत नहीं मिलता है, और कोई सेनानी उसकी पुष्टि करता है तो उसको पेंशन मिलेगी । क्या सरकार कोई पत्रकार की एक कमेटी बनाकर के उसको यह जिम्मेदारी देकर के उन पत्रकार को पेंशन देना चाहती है या नहीं ? क्योंकि पत्रकारों की संख्या जो अभी तक मेरे पास है कि सिर्फ 75 पत्रकार को ही उस हिसाब से पेंशन मिल रही है । महोदय, बिहार में सिर्फ 75 पत्रकार नहीं हैं । पत्रकार जो है वह पूरी जिंदगी चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हुए अपने जीवन को होम कर देता है ।

अध्यक्ष : अब पूरक पूछ लीजिए ?

श्री अजय कुमार : इसीलिए मेरा कहना है कि जो पी0एफ0 और दूसरी टी0डी0एस0 कटौती के आधार पर जो शर्त रखी गयी है, वह कंपनी उसको काटती है । अब पत्रकार का कंपनी भी जो है वह शोषण करती है । इसीलिए मैं यह सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जे0पी0 सेनानी की तरह कोई एक पत्रकारों की कमेटी, आइदर विधानसभा के अंदर कोई कमेटी बनाकर के उसकी पुष्टि करवा कर के, और जितने पत्रकारों की पुष्टि हो, उसको पेंशन सरकार देना चाहती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जे0पी0 सेनानियों को और पत्रकारों को पेंशन देने की योजना की शर्तें अलग–अलग इसीलिए हैं कि यह दोनों एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं । जे0पी0 सेनानी का तो बाद में सोच के दिया गया है न, लेकिन पत्रकार तो लगातार हैं । अब जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जेपी सेनानी थे, यह तो जिस वक्त महोदय आंदोलन चला उस वक्त तक की बात थी । लेकिन यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और दूसरी बात है, आप संख्या जो कह रहे हैं, सरकार ने कोई संख्या पर सीमा नहीं लगाई है कि हम आठ ही को देंगे, दस ही को देंगे, बारह को देंगे । महोदय, हमने कहा कि कम से कम सेवा अवधि की जो अनुमान्यता है, वह बिहार में ही नहीं है, जहां कहीं भी जिस दूसरे प्रदेश में यह मिल रहा है, वहां भी इसी तरह की अनुमान्यता की शर्तें हैं । हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं और दूसरे कम लोगों को मिल रहा है, तो यह सरकार, हम लोगों ने कोई सीमा नहीं लगाई है । सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है, इसीलिए यह पेंशन योजना शुरू की है और हमको बताते हुए महोदय प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने पेंशन की राशि निर्धारित की है, वह किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है, इतना हम लोग सम्मान देते हैं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ....

अध्यक्ष : हो गया, सब बात आ गयी । माननीय सदस्य मो0 कमरूल होदा ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पत्रकार के सवाल को आपके माध्यम से उठा रहा हूं । महोदय, पत्रकार का जान लीजिए, विपक्ष की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है । बावजूद इसको मैं पत्रकार के बारे में, बिहार के अंदर जितने पत्रकार हैं, उनके पेंशन की मांग मैं यह कर रहा हूं । मैं उस सवाल को उठा रहा हूं।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, पत्रकार विपक्ष की बात को नहीं रखते हैं । माननीय सदस्य पत्रकार पर आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री अजय कुमार : और इसीलिए मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय सदस्य पत्रकार पर आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री अजय कुमार : आप पूछिएगा, आपको जब मौका मिलेगा, पूछ लीजिएगा । आप सब जानते हैं गोदी मीडिया क्या कर रही है आपको पता है। सबको पता है।

अध्यक्ष : जिवेश जी, बैठ जाइये ।

श्री अजय कुमार : इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से पूरक है कि क्या बिहार के अंदर सभी पत्रकार जो हैं, उनको पेंशन देने के लिए कुछ अगर नियमों में कुछ शिथिलता लाना है, तो वह लाकर के देना चाहती है कि नहीं ? मुझे तो इतना ही सिर्फ कहना है ।

अध्यक्ष : ठीक है, सरकार विचार करेगी ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–36, मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र सं0–54, किशनगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : 1–इस विभाग से संबंधित नहीं है ।

2 एवं 3– भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है ।

श्री मो0 कमरूल होदा : अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछता हूं । बिहार राज्य के 18 प्रतिशत मुस्लिम आबादी का एक बड़ा मामला है । सरकार की बेहतर व्यवस्था नहीं देने की वजह से अहम फरीजा हज की अदायगी नहीं कर पाते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए, क्या चाहते हैं ?

श्री मो0 कमरूल होदा : वही पूरक ही पूछ रहे हैं । महोदय, बिहार के हाजियों के लिए मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एयरपोर्ट में इनकी व्यवस्था की गई है । महोदय...

अध्यक्ष : यह मामला जो है भारत सरकार से संबंधित है ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, महोदय जब गया एयरपोर्ट से 2012–18 में हाजी यात्रा हज के लिए जाते थे, 6000 से 7000 हाजी जाते थे । अब महोदय, 2025 में 12,000 से अधिक हाजियों का मक्का जाने के लिए लक्ष्य था ।

अध्यक्ष : आप पटना एयरपोर्ट से चाह रहे हैं ।

श्री मो0 कमरूल होदा : मात्र, 2378 का ही है ।

अध्यक्ष : आपका आग्रह पटना के जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट से है ।

टर्न–4 / हेमन्त / 16.02.2026

मो0 कमरूल होदा : महोदय, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बगल में हमारा एयरपोर्ट पटना है, पटना एयरपोर्ट से इसकी व्यवस्था की जाय ताकि ज्यादा–से–ज्यादा से हाजी हज को जा सकें।

अध्यक्ष : विषय आ गया।

मो0 कमरूल होदा : और देश और बिहार राज्य की शांति की दुआ मांग सकें।

अध्यक्ष : आपका विषय आ गया है, जवाब सुन लीजिए।

मो0 कमरूल होदा : बिहार के विकास की दुआ मांग सकें। महोदय, पटना एयरपोर्ट से इनकी व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

मो0 कमरूल होदा : बगल में पटना एयरपोर्ट है। महोदय, हज भवन के बगल में एयरपोर्ट है। इसकी व्यवस्था यहां से की जाय।

अध्यक्ष : सुन लीजिए अब। आपने अपनी बात रख दी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो–तीन बातें हैं। पहली कि कौन हज यात्री कहां से जाएंगे? यह सब का निर्धारण यहां जो हज कमेटी है, वह हज कमेटी ही करती है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के ही मानिंद लोग सदस्य होते हैं और वही तय करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन हज यात्री कहां से विमान की सुविधा चाहते हैं, यह भी अपना ऑप्शन या पसंद वही देते हैं, महोदय। गया या कहीं दूसरी जगह का, बिहार की दूसरी जगह का पसंद इसलिए भी नहीं देते हैं, अभी तो अंतरराष्ट्रीय अड्डा गया में बना ही है, क्योंकि यहां से जाने का खर्चा अधिक लगता है। हम लोगों ने कोई रोक नहीं लगाई है। पिछली दफा भी किशनगंज से विशेष व्यवस्था करके, हम लोगों की सरकार ने उनको हज यात्रा पर भेजने की व्यवस्था की थी और आगे भी अगर हज यात्री कोई विशेष सुविधा चाहते हैं, तो सरकार इस बारे में पूरी संवेदनशीलता से विचार करती है। करीब दो साल पहले वहां से ज्यादा लोग थे, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई, क्योंकि कोलकाता से या दिल्ली से जाने में उन्हीं लोगों को सुविधा होती है। महोदय, सरकार को कोई एतराज क्यों होगा? केवल यहां से, फिर अतिरिक्त विमान भेजने में खर्चा उन लोगों को अधिक लगता है। इसलिए सामान्य पसंद में वही लोग दूसरी जगह को चुनते हैं।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे। श्री चन्द्रशेखर जी।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1042, श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र सं॰–73, मधेपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत परमानंदपुर थाना भवन (G+3 Structure), आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य हेतु 9,93,27,800 (नौ करोड़ तिरानवे लाख सताईस हजार आठ सौ रुपया) की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें सिपाहियों के आवासन हेतु महिला एवं पुरुष सिपाही बैरक का भी प्रावधान किया गया है तथा थाना भवन के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त की जा चुकी है । उक्त थाना भवन का निर्माण कार्य जून, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

मठाही ओ०पी० नहीं बल्कि शिविर है, जो मधेपुरा सदर थाना का ही एक भाग है। सरकार द्वारा अधिसूचित थानों के ही भवन निर्माण की स्वीकृति

दी जाती है। गैर अधिसूचित थाना/ओ०पी० के भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, जवाब आया है। 15 साल से वह शिविर है और एफआईआर की अनुशंसा होती है मिठाही में। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शिविर को ओपी में परिवर्तित कर और स्वतंत्र भवन पुलिस पदाधिकारियों, महिला कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल के लिए बनाने का विचार रखते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने जवाब में दिया है कि जो शिविर हैं, वहां चलाए जाते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ओपी के निर्माण जब होते हैं, तो उसके लिए हम परमानेंट बिल्डिंग नहीं बनाते। वह हमारा टेंपरेरी कंस्ट्रक्शन है। हम इसको दिखवा लेते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं, तो इसको हम दिखवा लेते हैं, जांच करा लेते हैं। आवश्यकता पड़ेगी, तो थाना बनाने की बात सोची जा सकती है।

तारांकित प्रश्न सं०–1043, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं०–138, विभूतिपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मो० जमा खान, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । इसके अधीन एक अल्पसंख्यक बालक छात्रावास समस्तीपुर जिला मुख्यालय में चल रहा है । वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, पूछता हूं और जवाब भी मिला है। मैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो जा चुका है, लेकिन हम सदन को बताना चाहते हैं कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। इसके अधीन एक अल्पसंख्यक बालक छात्रावास समस्तीपुर जिला मुख्यालय में चल रहा है। वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : जब प्रावधान ही नहीं है। सुने नहीं ? जिला स्तर पर चल रहा है।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रावधान लाने के लिए ही तो मैं क्वेश्चन लाया। क्या इस आधार पर जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है, जिन ब्लॉकों में, उसको

चिन्हित करके क्या वहां आप अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक छात्रों की आवश्यकता एवं शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण किया जाता है। उसको हम दिखवा लेते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या–1044, मो0 आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या–49, अररिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1045, श्री संतोष कुमार निराला (क्षेत्र संख्या–202, राजपुर (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि, इटाढ़ी थाना से कुकुढ़ा गाँव की दूरी करीब 09 किलोमीटर है। उक्त थाना से आवागमन का साधन पक्की सड़क है। उक्त क्षेत्र में विगत 05 वर्षों का आपराधिक आंकड़ा शून्य है।

अतएव कुकुढ़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

3. उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री संतोष कुमार निराला : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है और उत्तर में पुलिस चौकी के निर्माण में कोई सकारात्मक सरकार का उत्तर नहीं है। हम बताना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि इटाढ़ी थाना का अंतिम छोर है, धनसोई थाना का भी अंतिम छोर है और राजपुर का मध्य भाग है, आए दिन वहां छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं और वहां कई दुकानें हैं, बाजार लगता है और 10+2 का स्कूल भी है। मेरा जो गृह है, वह 5 किलोमीटर के रेडियस में है। ऐसे पुलिस की गाड़ी बराबर लगी रहती है और घटनाएँ होती हैं। तो मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, पुलिस चौकी का कुकुढ़ा में निर्माण कराएं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले 5 वर्षों में आपराधिक आंकड़ा शून्य है। लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस इलाके की और समीक्षा की जाए। समीक्षा कराकर, यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो जरूर करूंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–1046, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार, मंत्री : 1–उत्तर स्वीकारात्मक है।

2–उत्तर स्वीकारात्मक है।

3– राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार अन्तर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा राज्य में नयी चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति–निर्धारण/कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

इसी क्रम में सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से चीनी मिलों की संभाव्यता के बिन्दु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि0 की सेवा लिये जाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए दर की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने हेतु अपेक्षित सभी कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी निवेशक से नई चीनी मिल अथवा गन्ना आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो सरकार उन्हें नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी।

राज्य में नयी चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी चीनी मिलों के पुनरूद्धार हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर, गयाजी, सीवान, रोहतास, मोतिहारी, बेतिया, पटना, पूर्णिया, शिवहर, सारण, वैशाली, नवादा, मधुबनी, दरभंगा, भोजपुर (आरा), बक्सर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, नालंदा, बांका एवं मधेपुरा को स्थापना संबंधित प्रतिवेदन/प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

श्री अरूण सिंह : महोदय, सरकार का उत्तर आया है।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए।

श्री अरूण सिंह : मेरा उद्योग विभाग से संबंधित प्रश्न था। सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि पुराने चीनी मिलों को, जहां हैं, उसको हम चालू करेंगे। हम इतना ही जानना चाह रहे थे कि रोहतास जिला में दो चीनी मिल थे, डालमिया नगर में और विक्रमगंज में, क्या उस चीनी मिल को चालू करने का विचार सरकार रखती है ? उत्तर में जो बात आयी है, तो सरकार क्या निर्णय ले रही है, नहीं ले रही है, उस संबंध में मैं इतना जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि डेहरी और विक्रमगंज में खोलने के विचार रखती है कि नहीं रखती है ? ये बात सुनने के लिए हम थोड़े ही क्वेश्चन किए हैं कि आपका सहकारिता विभाग क्या कर रहा है, जिला क्या कर रहा है। हम इतना ही जानना चाहते हैं विक्रमगंज में और डालमियानगर में चीनी उद्योग मिल खोलने का विचार रखती है कि नहीं रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अंतर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना एवं पुरानी बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति–निर्धारण/कार्य योजना तैयार की जा रही है। महोदय, हम लोगों ने करीब 25 जिलों से डी0एम0 को पत्र लिखकर जमीन उपलब्धता की मांग की है और जैसे ही निवेशक हम लोगों को मिलेंगे, हम लोग चीनी मिल चालू करने का प्रयास करेंगे।

श्री अरूण सिंह : महोदय, निवेशक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह सरकार का काम है। हम यह चाहते हैं कि डिहरी में और विक्रमगंज में जो पुराने चीनी मिल हैं, उस जगह को चयनित करेगी सरकार कि नहीं करेगी ? यह बात हम पूछना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष : रिपोर्ट मांगी गयी है न। रिपोर्ट तो मांगी गयी है।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसकी फिजीबिलिटी रिपोर्ट करा रहे हैं। सरकार उसको देखेगी, समीक्षा के उपरांत यदि उस लायक होगा तो जरूर करेंगे। इसमें कहां दो मत हैं।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1047, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या–56, अमौर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत अमौर थाना की चहारदीवारी के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को दिया गया है।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री ने कहा है कि प्राक्कलन तकनीकी मंजूरी के बाद हम वह मंगवा रहे हैं, करवा लेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं कि मां सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन बीमार बच्चे से अधिक प्यार करती है। सीमांचल में सारा काम पीछे होगा, सर। सब जगह थाने की चहारदीवारी हो गई, सर। वहां चारागाह बना हुआ है, सर। मैं माननीय मंत्री से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, कि कब तक बना देंगे?

अध्यक्ष : एस्टीमेट बन रहा है।

श्री अखतरूल ईमान : कब तक, समय दे दें। क्या इस वित्तीय वर्ष में ? सर, बता दीजिए।

अध्यक्ष : एस्टीमेट बनने के बाद।

श्री अखतरूल ईमान : सर, वह कहना चाह रहे हैं। सर, जवाब दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या–1048, श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या–77, महिषी)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1– वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत चंद्रायण चौक से सहरसा तक विनोवा भावे पथ, तीन थानों के क्षेत्र में पडता है, जो नवहट्टा थाना से 05 किलोमीटर, बिहरा थाना से 10 किलोमीटर एवं सदर थाना से 05 किलोमीटर पर है। पैतृक थाना से संपर्क पथ एवं आवागमन के लिए पक्की सड़क है।

2– विगत पांच वर्षों में उक्त मार्ग पर पड़ने वाले नवहट्टा थाना एवं बिहरा थाना पर कोई भी सम्पति मूलक अपराध की घटना घटित नहीं हुई है। सदर थाना के अंतर्गत वर्ष 2021 से 2025 तक छिनतई के 03 एवं चोरी के 02 मामले प्रतिवेदित हुए हैं।

उक्त मार्ग पर थाना स्तर से गश्ती दल भ्रमणशील रहता है तथा स्थानीय महाल चौकीदार को समय–समय पर आसूचना संकलन एवं विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निदेशित किया जाता है।

अतएव चंद्रायण चौक से सहरसा तक नये थाना या पुलिस चौकी स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

3– उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री गौतम कृष्ण : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री गौतम कृष्ण : जी, उत्तर मिला है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री गौतम कृष्ण : मैंने माननीय मंत्री जी से एक ओ0पी0 निर्माण की मांग की थी, जो चंद्रायन चौक से सहरसा, 21 कि.मी. की दूरी पड़ती है। एक तरफ पूरी घनी आबादी है और दूसरी तरफ यह चौर का इलाका है, मतलब पानी जमा हुआ इलाका है और इस 21 कि.मी. की दूरी में एक भी पुलिस चौकी न रहने की वजह से...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री गौतम कृष्ण : जी, पूरक ही पूछ रहा हूं। आपराधिक घटना होती है, नशा कारोबार वाला लगा रहता है, मार पीट है, छिनतई है। माननीय मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया है, उसमें कहा गया है, अधिकारी लोग बड़े XXX लोग होते हैं, जो उत्तर बना कर देते हैं सरकार को...

अध्यक्ष : यह शब्द मत बोलिये। XXX शब्द को हटा दीजिए।

श्री गौतम कृष्ण : वह पूरा गोल–मटोल होता है। अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, सरकार को सही बात से अवगत नहीं कराते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारे माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से ध्यान देंगे। जब सही वस्तुस्थिति पता होगी, तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे, हम इतना विश्वास करते हैं।

(क्रमशः)

———————————————————————————————————

XXX- इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

———————————————————————————————————

टर्न–5 / संगीता / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री गौतम कृष्ण : जिसमें कहा गया है इस 21 किलोमीटर, इधर से नवहट्आ थाना का शुरूआती प्वायंट ले लिया 05 किलोमीटर, इधर से बिहरा थाना का शुरूआती प्वायंट ले लिया 05 किलोमीटर और इधर से बिहरा थाना का...

अध्यक्ष : सारी बात आपकी आ गई । आप आग्रह कर लें ।

श्री गौतम कृष्ण : मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी बीच में अगर एक चौकी का निर्माण हो जाए तो 21 किलोमीटर सुरक्षित होगा । उसके बाद इसमें पूरक पूछना चाहता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी जो उत्तर दिए हैं कि इसमें मात्र 2 घटना हुई है एक छिनतई की घटना हुई है और चोरी की घटना 2 हुई है पिछले 5 साल में । हकीकत यह है कि लोग अपना सामान तो छिनवा ही लेते हैं छिना जाता है, लेकिन वे थाना जाने से बचते हैं क्योंकि हजार–दो हजार, पांच हजार की अगर होती है तो उनको लगता है इससे ज्यादा तो मुझे चढ़ावा चढ़ाना पड़ जाएगा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आग्रह कर दीजिए ।

श्री गौतम कृष्ण : हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री महोदय जी से कि सही रिपोर्ट नहीं है इसलिए मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं , मेरा घर मधेपुरा है...

अध्यक्ष : पुलिस चौकी निर्माण का आपका...

श्री गौतम कृष्ण : एक मिनट सर, सिर्फ एक मिनट अध्यक्ष महोदय । शेखर बाबू और मेरा घर जस्ट बगल में है पूछ लीजिए हमारे घर और मधेपुरा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और छिनतई आदि की घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन लोग दर्ज नहीं करते हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब है कि पिछले 5 वर्षों में 5 घटनाएं, मात्र 3 छिनतई और 2 चोरी की घटनाएं । इसमें कहीं दो मत नहीं है सरकार सुशासन के साथ चलाना चाहती है आदरणीय

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और 5 साल में 5 घटना हुआ तो ओ0पी0 कैसे खुलेगा एक, लेकिन माननीय सदस्य तो अभी कुछ दिनों से काम कर रहे हैं उस इलाके में, मैं 27 साल से उसी इलाके में काम कर रहा हूं...

श्री गौतम कृष्ण : मंत्री जी, मैं 12 साल से काम कर रहा हूं ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : ठीक है, ठीक है लेकिन मैं जरूर यह कहता हूं मैं इसकी जांच करा लेता हूं यदि संभव होगा तो जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : श्री बशिष्ठ सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0 –1049, श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या–209, करगहर)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–क –स्वीकारात्मक ।

खंड–ख –स्वीकारात्मक ।

खंड–ग –वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड के नौवा, नखर एवं चितांव पंचायत के गांवों को कोचस थाना से जाड़ने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, रोहतास द्वारा मंतव्य/प्रस्ताव की मांग की गयी है । मंतव्य/प्रस्ताव प्राप्त होने पर आकलन कर निर्णय लिया जाएगा ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एंसर तो मिला हुआ है मुझे लेकिन माननीय उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं चूंकि मेरी जो समस्या है वह बहुत ही जटिल है । कोचस प्रखंड अंतर्गत, नौवा पंचायत, नरवर पंचायत और चितांव पंचायत के लगभग 28 से 30 गांव ब्लॉक का काम कोचस से होता है, अचंल का काम कोचस अंचल से होता है और पुलिस का काम दिनारा से होता है, थाना से होता है जबकि ये पंचायत 2 से 5 किलोमीटर के नजदीक में कोचस थाना पड़ता है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री बशिष्ठ सिंह : और 25 किलोमीटर जाना पड़ता है दिनारा थाना पर और जब अनुमंडल पुलिस का काम होता है अनुमंडल का काम सब होता है सासाराम से और पुलिस अनुमंडल का काम होता है विक्रमगंज से जो 45 किलोमीटर जाना पड़ता है माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपका आया है कि एस0पी0 से प्रस्ताव, हम चाहेंगे कि कब तक प्रस्ताव मंगाकर और शीघ्र इसको करा दिया जाय चूंकि आप तो दयालु आदमी हैं जल्दी से कर देते हैं । यह बहुत ही जटिल समस्या है मेरे क्षेत्र का ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार का स्पष्ट जवाब है पुलिस अधीक्षक से तुरंत रिपोर्ट मंगाकर, एक महीने के अदंर रिपोर्ट मंगाकर इसका निर्णय माननीय विधायक की सहमति से तुरंत करूंगा ।

अध्यक्ष : श्री श्याम रजक जी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1050, श्री श्याम रजक (क्षेत्र सं0–188, फुलवारी (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

जिलों द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है तथा उनकी घेराबन्दी हेतु क्रमबद्ध ढंग से योजनाएं ली जाती हैं।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री श्याम रजक : सर, जवाब मिला है लेकिन जवाब में इन्होंने लिखा है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । मेरा यह कहना है कि जब इन्होंने कहा है कि प्राथमिकता सूची में नहीं है तो उसी कब्रिस्तान को आधा घेराबंदी 2012 और 15 में, 2009 और 10 में किया गया आधी क्योंकि वहां पर काफी घटनाएं होती थीं और आधा बचा हुआ है । जब आधा में काम हुआ है तो फिर प्राथमिकता सूची में नहीं होना, संवेदनशील नहीं होना ये किस बात का जवाब है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य वरिष्ठ साथी हैं इन्होंने जो सूचना दिया है मैं इसको ग्रहण करता हूं, इसको शीघ्र यदि आधा काम हुआ है तो पूरा काम भी सरकार करायेगी ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार सिंह यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0–1051, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र सं0–203, रामगढ़)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 –उप महाप्रबंधक, कृषि व्यवसाय इकाई, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के पत्रांक–569, दिनांक–02.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कैमूर जिलान्तर्गत नुआंव प्रखंड के नुआंव बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नहीं है । परन्तु, उक्त केन्द्र एवं केन्द्र से 05 किलोमीटर के दायरे में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को बैंकिंग शाखाएं, 21 ग्राहक सेवा केन्द्र एवं 02 ए0टी0एम0 उपलब्ध है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है –

उक्त केन्द्र एवं 05 किलोमीटर के अंदर स्थित बैंकिंग बुनियादी ढांचा ...

	बैंक का नाम	शाखा का नाम	ग्राहक सेवा केन्द्रों सं0	एटीएम
कैमूर जिलान्तर्गत नुआंव प्रखंड के नुआंव बाजार	पंजाब नेशनल बैंक	नुआंव	11	01
	बिहार ग्रामीण बैंक	नुआंव	08	...
	भारतीय स्टेट बैंक	...	01	...
	आई.पी0पी0बी0	...	01	...
	इंडिया वन	...	...	01

खंड–2– नुआंव बाजार एवं आसपास के ग्रामीण निवासियों को उपरोक्त बुनियादी बैंकिंग ढांचा द्वारा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध की जा रही है ।

खंड–3– बैंक शाखा खेलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार हैं । मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न है कि कैमूर जिला के नुआंव प्रखंड में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने का, महोदय, जवाब मिला है माननीय मंत्री जी से कि 2 बैंक है वहां नुआंव में पूरे प्रखंड में लेकिन भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, एक पंजाब नेशनल बैंक है और एक बिहार ग्रामीण बैंक है । पंजाब नेशनल बैंक स्थिति यह है कि उसमें लगभग 51 हजार खाताधारक हैं, और बिहार ग्रामीण बैंक में लगभग 40 हजार खाता धारक हैं और जितने भी रिटायर्ड सैनिक होते हैं या रिटायर्ड शिक्षक होते हैं उनलोगो की पेंशन...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : भारतीय स्टेट बैंक में आती है तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करके बुजुर्ग लोगों को पेंशन के लिए जाना पड़ता है तो मेरा सवाल है कि मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नुआंव प्रखंड में एक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोली जाए । महोदय, अभिभावक हैं हमलोगों के, हमलोग नए आए हैं, कुछ सीखने को मिलता है, वहां स्टेट बैंक का खुल जाए तो बढ़िया रहेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ठीक है प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : श्रीमती बिनिता मेहता ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1052, श्रीमती बिनिता मेहता (क्षेत्र सं0–238, गोविन्दपुर)</u>

श्रीमती बिनिता मेहता : मैं पूछती हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न माननीय सदस्या ।

श्रीमती बिनिता मेहता : नहीं, उत्तर नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी, पढ़ दीजिए । बता दीजिए, अभी नई सदस्या हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अपलोड तो है ही ।

अध्यक्ष : बैंक शाखा खोलने का है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उप–महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के पत्रांक–578, दिनांक–07.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नवादा जिला के गोविन्दपुर विधान सभा अंतर्गत रोहत प्रखंड से पांच किलोमीटर के दायरे में 3 बैंक शाखाएं, 24 ग्राहक सेवा केन्द्र एवं 2 एटीएम के माध्यम से नवादा जिला के गोविंदपुर विधान सभा अंतर्गत रोह प्रखंड के निवासियों को नगदी आहरण सहित अन्य आवश्यक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैः

क्रम सं0	बैंक का नाम	शाखा का नाम	बैंक से जुड़े ग्राहक सेवा केंद्र की संख्या	एटीएम की संख्या	रोह बाजार के अनुमानित दूरी (कि0मी0)
1	पंजाब नेशनल बैंक	नजरदिह	02	–	05
2	बिहार ग्रामीण बैंक	अनैला	03	–	05
3	बिहार ग्रामीण बैंक	रोह	05	–	0
4	ग्राहक सेवा केंद्र भारतीय स्टेट बैंक	–	01	–	0
5	आईबीबीपी	–	13	–	0
6	इंडसइंड बैंक	–	–	01	0
7	वन इंडिया	–	–	01	0

बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक ही सक्षम प्राधिकार हैं । मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

अध्यक्ष : श्री रितुराज कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1053, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या–217, घोसी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री विष्णु देव पासवान ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1054, श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या–107, दरौली (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1– वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिला के दरौली प्रखंड अन्तर्गत दरौली थाना में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, जिससे दरौली प्रखंड अन्तर्गत अग्निशमन का कार्य किया जाता है ।

सिवान जिला गुठनी प्रखंड में नजदीकी थाना मैरवा में प्रतिनियुक्त मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन से अग्निशमन का कार्य किया जाता है । इसके अतिरिक्त अग्नि प्रवण काल में यहां एक अदद अतिरिक्त बड़ी अग्निशामक वाहन की प्रतिनियुक्ति की जाती है ।

खंड–2– उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री विष्णु देव पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है, उत्तर से संतुष्ट हूं लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सिवान जिला के दरौली विधान सभा में सभी प्रखंडों में पंचायतों की संख्या अधिक और क्षेत्र बड़ा होने के कारण वर्तमान में अग्निशामन वाहन की संख्या कम है, सभी प्रखंडों में अग्निशामन वाहनों की संख्या बढ़ायी जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि दरौली थाना में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है लेकिन माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर किया है उसको जिलाधिकारी के साथ एक बैठक कराकर उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्नों के उत्तर आपकी सीट के सामने लगे टैब में रहता है उसे बस देखें, अगर कोई दिक्कत हो तो सचिवालय आपकी मदद करेगा । श्री नीतीश मिश्रा जी के प्रश्न के लिए श्री कुमार शैलेन्द्र जी को प्राधिकृत किया गया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1055, श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या–38, झंझारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1– वस्तुस्थिति यह है कि, मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड/थाना के प्रश्न वर्णित गाँव मधेपुरा थाना से लगभग 11 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जहॉ पहुँचने में थाना के गश्ती दल को लगभग 25 मिनट का समय लगता है। ये गाँव कमला नदीं के किनारे एवं दरभंगा जिला की सीमा से सटे हैं। इस क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों में हत्या के 05, गृह भेदन के 01 एवं चोरी के 06 कांड प्रतिवेदित हैं। थाना स्तर से नियमित गश्ती एवं निगरानी रखी जाती है, जिससे विधि–व्यवस्था सामान्य है।

खंड–2– मधेपुर प्रखंड के कई गाँव दोनों तटबंधों के बीच बसे हैं, जहाँ बरसात के मौसम में जाने में कठिनाई होती है। सूचना प्राप्त होने पर

थाना स्तर से कार्रवाई की जाती है और लगातार निगरानी तथा विधि–व्यवस्था नियंत्रित रखी जाती है।

खंड–3– उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री कुमार शलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है और मैं संतुष्ट से संतुष्ट भी हूं । मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह आग्रह कर रहा हूं कि चूंकि पहले जो पुलिस चौकी थी वहां पर, पहले भी टी0ओ0पी0 चलता था और हाल–फिलहाल में अभी एयरपोर्ट भी खुला है, धमदाहा और पूर्णिया के बीच में ट्रैफिक भी ज्यादा है । माननीय मंत्री महोदय से केवल यह आग्रह करता हूं कि यदि भविष्य में कोई वैसा विचार हो तो एक टी0ओ0पी0 जरूर खोला जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर थाना है लेकिन मैं समीक्षा करा लेता हूं, एक रिपोर्ट मांगता हूं उसके आधार पर विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : श्री पुरन लाल टुडू ।

टर्न–6 / यानपति / 16.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–1057, श्री पूरन लाल टुडू (क्षेत्र सं0–162, कटोरिया (अ0ज0जा0))

श्री पूरन लाल टुडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा...

अध्यक्ष : आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्तर मिला है न आपको ।

श्री पूरल लाल टुडू : अध्यक्ष महोदय, नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये, उत्तर सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी, उत्तर दे दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपलोड किया गया है लेकिन...

अध्यक्ष : उत्तर सुन लीजिए, पूरक पूछिएगा, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसमें बात इतनी ही है कि माननीय सदस्य का कहना सही है कि 2003 में संविधान में संशोधन करके संथाली भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर दिया गया । उसके अनुरूप भारत सरकार ने नोटिफिकेशन 2004 में निकाल दिया । निकाल दिया तो वह स्वतः पूरे देश में लागू हो जाता है, फिर अलग से बिहार में नोटिफिकेशन करने की क्या बात । माननीय सदस्य कह नहीं रहे हैं, अगर वह स्पष्टता से कह दें या एक पत्र लिख दें तो हम अलग से इसको दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1058, श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र सं0–07, चनपटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड मझौलिया के सरिसवा बाजार क्षेत्र से मझौलिया थाना की दूरी–12 किलोमीटर है। उक्त क्षेत्र के लिए आवागमन के सुगम साधन हैं। मझौलिया थाना के द्वारा सरिसवा बाजार में निरंतर गश्ती एवं निगरानी रखी जाती है।

वर्तमान में विधि–व्यवस्था संधारण में कोई समस्या नहीं होने के कारण मझौलिया के सरिसवा बाजार में पुलिस ओ0पी0 स्थापित करने का औचित्य नहीं है।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, जवाब जो मिला है उससे हम असंतुष्ट ही नहीं बल्कि हैरान भी हैं, कानून व्यवस्था को मापने का कि0मी0 से जो मानदंड तय किया गया है यह हैरानी वाली बात है । मझौलिया थाना के अंतर्गत 29 पंचायतें आती हैं और लगभग 50 से 60 कि0मी0 का जो क्षेत्र है, मझौलिया थाने के अंतर्गत आता है, क्राइम का डाटा देखा जाय तो मझौलिया थाना में यह प्रतिमाह पिछले माह सौ से अधिक एफ0आई0आर0 दर्ज हुए हैं, पिछले महीने जनवरी के माह में चार से पांच अन–आइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिली थीं और पूरे जिला में 200 जो चोरी होती है उसमें से 20 से ज्यादा चोरी मझौलिया थाना में रिपोर्ट की जाती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अभिषेक रंजन : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं । सरिसवा बाजार जो है वह साधारण बाजार नहीं है और वह इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर रहा है, नेपाल का जो बॉर्डर है उससे सटा हुआ बॉर्डर है तो महोदय मेरा पूरक ये है कि क्या 29 पंचायत और 50 से 60 कि0मी0 क्षेत्र एक ही थाना से नियंत्रित करना व्यावहारिक है, क्या सरकार किसी जन सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, सरिसवा बाजार में अविलंब अस्थाई पुलिस ओ0पी0 की स्थापना की हमारी मांग है और अगर इसे कंसीडर किया जाय तो हम काफी धन्यवाद देंगे।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और आरक्षी अधीक्षक दोनों की एक संयुक्त बैठक करके पूरे इलाके की समीक्षा करके एक रिपोर्ट आया था उसके आधार पर निर्णय ले लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1059, श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र सं0–225, गुरूआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक । सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–18727/2017 दिनांक–28.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–4862, दिनांक–29.04.2025 निर्गत है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–4862, दिनांक–29.04.2025 द्वारा जिन कर्मियों को बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली,

1958 के नियम–157(3)(J) के द्वारा विहित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है, उन्हें उक्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य किया जाना है । यदि अन्य कोई निरर्हता नहीं हो, तो सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय उन्नयन हेतु प्रत्यायोजित शक्ति के तहत प्रशासी विभागों/कार्यालयों के सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, सरकार का जवाब आया भी है और जो हमने प्रश्न किया है उसका क्लॉज सही है लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए कि बिना लेखा परीक्षा पास किए ही ए0सी0पी0 का लाभ देना है, 28.06.2024 को ही यह आदेश पारित है और आजतक उसको लागू नहीं किया गया है, क्या यह पर्याप्त समय नहीं है लागू करने के लिए । बस इतना ही सरकार से जानना चाहते हैं कि कब तक सरकार इसको लागू करेगी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है उत्तर में, जिससे वह संतुष्ट भी हैं कि सरकार लागू किए हुए है, चाहे हाईकोर्ट का मामला हो या हमारे यहां, इस तरह के मामलों में निदेश सभी विभागों को वित्त विभाग देता है, उसने भी निदेश दिया है तो कोर्ट के आदेश और वित्त विभाग के निदेश इन दोनों के आलोक में सभी विभाग और हमारे क्षेत्रीय कार्यालय भी उसका अनुपालन कर रहे हैं अगर कोई मामला विशेष हो जहां पर कोई अधिकारी किसी क्षेत्रीय कार्यालय में या सचिवालय में अगर यह लागू नहीं हो रहा है तो सदस्य अलग से सूचना देंगे तो हमलोग जरूर दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज यादव ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, पटना जिला का ही है ।

अध्यक्ष : लिखकर के दे दीजिए आप ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1060, श्री मनोज यादव (क्षेत्र सं0–163, बेलहर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1061, श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र सं0–44, त्रिवेणीगंज (अ0जा0))

श्रीमती सोनम रानी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के अंतर्गत, वैसे उत्तर अपलोड किया हुआ है, कोई पूरक प्रश्न हो तो, या उत्तर नहीं पढ़े हैं तो हम उत्तर पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उत्तर पढ़ ली हैं ?

श्रीमती सोनम रानी : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : अच्छा बता दीजिए, नये सदस्य हैं, दिक्कत हो रही है, हो जायेगा ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के अन्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी, मक्का तथा आलू की खेती के लिए उपयुक्त है।

उद्योग विभाग द्वारा किसानों एवं निवेशकों के हित में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है और निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित एवं आकर्षित करने हेतु औद्योगिक नीति और विभिन्न सुविधाएँ, वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र जो माननीय सदस्या का सवाल है में 476 इकाईयाँ कार्यरत है और जिसमें लगभग 5039 करोड़ रूपये का निवेश हुआ है। सुपौल जिला में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से कुल चार इकाईयाँ कार्यरत हैं और 11 निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage–1) प्रदान की गई है ।

राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उत्पादो का शेल्फ लाईफ बढाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरपुर में कुल 58.15 करोड़ रुपये की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का Irradiation Centre Cum Pack House विकसित किया गया है और आने वाले समय में माननीय सदस्या का जो प्रश्न है उसमें भी यदि कोई और खाद्य प्रसंस्करण के निवेशक आयेंगे तो उनको वहां पर जो है प्राथमिकता देने का काम सरकार करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1062, श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र सं0–34, बाबूबरही)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि, मदनेश्वर स्थान के पश्चिम में लगभग 08 किलोमीटर की दूरी पर अधंराठाढ़ी थाना, दक्षिण में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर झंझारपुर थाना तथा उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर बाबूबरही थाना है। आवामगन के लिए पक्की सड़क है। पूर्व में दो समुदायों के बीच दंगा सदृश स्थिति उत्पन्न हुई थी परन्तु कोई दंगा नहीं हुआ है। पिछले पाँच वर्षों में हत्या के 02 तथा सामान्य अपहरण के 03 मामले प्रतिवेदित है।

अतएव, उपर्युक्त के आलोक में B.O.P. स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, उत्तर प्राप्त है, ये है मदनेश्वर स्थान में, जो बी0ओ0पी0 की हमने मांग की है तो मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि ये बाबूबरही प्रखंड 20 पंचायत का है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनगणना करवाई उस जनगणना के आधार पर वहां पर 2 लाख 75 हजार जनसंख्या है । तो इस आधार पर वहां पर कोई भी घटना होती है तो थाना में फोन करने के बाद कभी–कभार बहुत देर के बाद, पहुंचने में भी दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा लग जाता है, बहुत सारी ऐसी बड़ी जनसंख्या के चलते ये सामना करना पड़ता है वहां पर । तो हम चाहेंगे कि अब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे मंत्री जी को कि इसपर थोड़ा विचार करें वह अपने स्तर से ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 8 कि0मी0 पर अंधराठाढ़ी थाना है और इसके बावजूद माननीय सदस्या जैसा बता रही हैं, इसको मैं वहां पर आरक्षी अधीक्षक से रिपोर्ट मंगाकर देखता हूं कि आवश्यकता है या नहीं है, माननीय सदस्या से भी विचार के उपरांत उसपर निर्णय लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1063, श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र सं0–15, केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार, मंत्री : **(1)** उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीज की उपलब्धता हेतु त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर तथा आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज का उत्पादन चीनी मिल/प्रगतिशील कृषकों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत उन्नत एवं नवीन किस्म के चयनित 16 प्रभेद के आधार/प्रमाणित गन्ना बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली चीनी मिल द्वारा योजनांतर्गत ईच्छुक किसानों को Co-0118, CoLK-14201, CoLK-15023, Co-98014, CoLK-12209 के आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल भौतिक लक्ष्य 521 (पाँच सौ इक्कीस) एकड़ के विरूद्ध शरदकालीन बुआई हेतु 40 (चालीस) एकड़ के लिए 1000 (एक हजार) क्वींटल प्रमाणित गन्ना बीज वितरित किया जा चुका है तथा वसंतकालीन बुआई हेतु शेष बीज वितरण का कार्य प्रगति पर है।

पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र के राजपुर एवं हुसैनी कृषि फार्म गन्ना उद्योग विभाग के अधीन नहीं है।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पांच जगहों से गन्ना के बीज का वितरण किया जाता है । ईख अनुसंधान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान, लखनऊ, मोतीपुर और प्रमाणित कृषकों के द्वारा और चीनी मिल के द्वारा । मैं यह जानना चाहती हूं, मुख्यमंत्री गन्ना विस्तार योजना 2025–26 की रिपोर्ट देख रही थी और उसमें जो लक्ष्य है प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम, मैं सदन के लिए पढ़ना चाहती हूं, तीन चार लक्ष्य जो इंपॉर्टेंट हैं । प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम जिसमें लक्ष्य 70 हजार भौतिक लक्ष्य है और जो 7 लाख भौतिक लक्ष्य है और जो उपलब्धि है वह सिर्फ 88673 है जो सिर्फ 12 परसेंट है । सिमिलरली वित्तीय लक्ष्य 350 लाख का है जिसमें उपलब्धि 5.56 लाख है जो सिर्फ डेढ़ परसेंट है इसी तरह से प्रमाणित बीज क्रय का लक्ष्य भी 28 हजार के अगेन्स्ट...

अध्यक्ष : अब पूरक पूछ लीजिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : 3517 है जो साढ़े 12 परसेंट है और वित्तीय लक्ष्य 2 परसेंट ही उपलब्धि है । आधार बीज प्रोत्साहन योजना महोदय तो आश्चर्य की बात है कि जीरो उपलब्धि है । कुछ भी नहीं है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि लक्ष्य के विरुद्ध जो जीरो और 5 परसेंट, 12 परसेंट और 1 परसेंट की जो उपलब्धि हो रही है, क्यों नहीं किसानों की उपलब्धि की जा रही है बीजों की, प्रमाणित बीजों की, क्यों नहीं किसानों को मिल रहा है इसका क्या औचित्य है । क्यों गन्ना विभाग हर क्षेत्र में पीछे चल रहा है, उपलब्धि में ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न–7 / अभिनीत / 16.02.2026

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,

(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीज की उपलब्धता हेतु त्रिस्तरीय गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर तथा आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज का उत्पादन चीनी मिल / प्रगतिशील कृषकों द्वारा किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत उन्नत एवं नवीन किस्म के चयनित 16 प्रभेद के आधार / प्रमाणित गन्ना बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली चीनी मिल द्वारा योजनांतर्गत ईच्छुक किसानों को Co-0118, CoLK-14201, CoLK-15023, Co-98014, CoLK-12209 के आधार एवं प्रमाणित गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल भौतिक लक्ष्य 521 (पाँच सौ इक्कीस) एकड़ के विरूद्ध शरदकालीन बुआई हेतु 40 (चालीस) एकड़ के लिए 1000 (एक हजार) क्वींटल प्रमाणित गन्ना बीज वितरित किया जा चुका है तथा वसंतकालीन बुआई हेतु शेष बीज वितरण का कार्य प्रगति पर है।

पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र के राजपुर एवं हुसैनी कृषि फार्म गन्ना उद्योग विभाग के अधीन नहीं है।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने सिर्फ उत्तर जो आया है उसी को पढ़ा है । मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि ये रिपोर्ट मैं उनको साझा कर देती हूं 2025–26 का जो गन्ना का रिपोर्ट है भोतिक लक्ष्य और उपलब्धि का, तो क्या माननीय मंत्रीजी उस रिपोर्ट को देखकर जांच बैठाना चाहेंगे कि गन्ना किसानों को बीज क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं लक्ष्य के अगेन्स्ट ? माननीय

मंत्रीजी से पूछना भी चाहती हूं और आग्रह भी करना चाहती हूं कि एक जांच कमेटी बैठा दें, मैं रिपोर्ट भी शेयर करती हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया उसका मैं बैठे–बैठे अध्ययन कर रहा था । इन्होंने एक बात का जिक्र अपने जवाब में किया कि गन्ना बीज जो उपलब्ध करायी जा रही है, कुल भौतिक लक्ष्य 521 एकड़ के विरूद्ध मात्र 40 एकड़ में एक हजार क्वींटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है । महोदय, जब मंत्री ने यह स्वीकार किया कि 521 एकड़ के एवज में मात्र 40 एकड़ में ही बीज गन्ना का उपलब्ध कराया गया तो माननीय मंत्री को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि इतना कम प्रमाणित बीज गन्ना किसानों को क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य जी, आप अगर उपलब्ध करा दें तो मैं इसको दिखवा लेता हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये तो इनके प्रतिवेदन में है.....

अध्यक्ष : सरकार दिखवा लेगी ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं । प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक– 16 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री अजय कुमार (138), स0वि0स0, श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0...

(व्यवधान)

मौका देंगे आपको । मैं आपको मौका दूंगा बैठ जाइये । श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री राहुल कुमार, स0वि0स0, श्री अजय कुमार (231), स0वि0स0, श्री गौतम कृष्ण, स0वि0स0, श्रीमती सावित्री देवी, स0वि0स0, श्री अभिषेक रंजन, स0वि0स0, श्रीमती अनीता, स0वि0स0 ।

आज दिनांक–16 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कार्यस्थगन हम लाना चाहते हैं । महोदय, बिहार भूमि सुधार आयोग (डी. बंधोपाध्याय समिति) ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के लगभग 6.5 लाख भूमिहीनों को चिनिहत किया था । वर्तमान में यह संख्या बढ़कर लगभग 8 लाख तक पहुंच गयी है । 17वीं विधान सभा के चलते सत्र में सरकार द्वारा भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गयी बावजूद इसका अनुपालन नहीं हुआ है । इसके विपरीत प्रशासन द्वारा जो भूमिहीन सरकार की जमीन पर झोपड़ी बनाकर वर्षों से रहते आ रहे हैं को अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है । पटना, गया, हसनपुर और मुजफ्फरपुर में भीषण ठंड के दौरान हजारों परिवार बेघर हुए हैं, जिस पर पटना उच्च न्यायालय ने भी तल्ख टिप्पणी की है । सरकार भी भूमिहीनों को जबतक नई जगह पॉजिशन नहीं दिया जाता तब तक नहीं उजाड़ने की घोषणा की थी ।

अतः दिनांक–16.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर गरीबों की बेदखली पर रोक लगाने और भूमिहीनों को वास–भूमि का मालिकाना हक सुनिश्चित करने एवं सभी भूमिहीनों का चास–वास के लिए घोषणा अनुसार 5 डिसमिल जमीन देने हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक सूचना है कि गया नहीं गया जी । माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में जो फैसला लिया गया था, गया नहीं गया जी कर दिया गया है, तो आगे उच्चारण में गया के बदले गया जी कहेंगे ।

माननीय सदस्य राजू तिवारी जी ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष, जो उनके दल आरजेडी के विधायक हैं वे हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है । मैं मांग करूंगा इस सदन में जैसे हमारे माननीय नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग कैरियर रहा । महोदय, छः–छः प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है और ये आरजेडी वाले लोग, किनकी संस्कृति क्या रही है यह बताने की आवश्यकता नहीं है । ये जंगलराज की उपज हैं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं महोदय । अभी कल ये बेचारे–बेचारे कर रहे थे और आज मूर्ति की मांग करते हैं । ये प्रायश्चित करने वाले लोग नहीं हैं । देखिए इस सदन की खूबसूरती, मुख्यमंत्री हमारे पूरे कैबिनेट के साथ रहते हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष का पता नहीं है । नेता

प्रतिपक्ष जो हैं, ये गंदे लोग हैं । महोदय, मैं मांग करता हूं कि आकर माफी मांगे तेजस्वी यादव...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री राजू तिवारी : तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए....

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय सदस्या श्रीमती अनीता ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, कृपया शोरगुल न करें । बैठ जायें । आपकी बात तिवारी जी आ गयी है । आपको मौका दिया गया था, बैठ जाइये । श्रीमती अनीता । बैठ जाइये । जीरो ऑवर है । आपने अपनी बातों को राजू बाबू रख दिए हैं । बैठ जाइये । श्रीमती अनीता । बैठ जाइये । प्लीज बैठ जाइये । आपनी बातों को आपने रख दिया । आपने क्वेश्चन ऑवर में बात को रखा था । आपको मौका दिया गया है । आपने बातों को रख दिया, कृपया बैठ जाइये । शून्यकाल लिए जायेंगे । श्रीमती अनीता ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये । शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण है । शून्यकाल लिये जायेंगे और ध्यानाकर्षण आप सबों का है । मेरा आग्रह है राजू तिवारी जी, आपने अपनी बातों को रख दिया है । एक ही बात दस बार रखा जायेगा ? आपको दो–दो बार मौका दिया गया है । क्वेश्चन ऑवर के समय भी आपको मौका दिया गया था और अब शून्यकाल में मौका दिया है । अपनी बातों को आपने रख दिया है कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–8 / मुकुल / 16.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी – 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड – 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल – 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) – 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस – 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा – 04 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰ – 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा – 03 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)(एल॰) – 01 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰) – 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी – 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी – 01 मिनट

.....

कुल – 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 21270,40,73,000/– (इक्कीस हजार दो सौ सत्तर करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो॰ कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार जी का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बेड और जनसंख्या अनुपात डब्ल्यू0एच0ओ0 के मानक के अनुरूप नहीं रहने के कारण जिला अस्पताल में वेंटिलेटर, ब्लड बैंक जैसी महत्वपूर्ण सुविधा नहीं रहने के कारण और बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपए से घटाई जाए ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया आपका आभार और महोदय मोरवा की महान जनता को भी हम बहुत आभार जताना चाहते हैं, जिन्होंने दूसरी बार मुझे आशीर्वाद देकर सदन में भेजने का काम किया, मैं आभार जताना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को और माननीय नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि उन्होंने मुझे इस सदन में आने का मौका दिया और मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं । महोदय, जिस विषय पर आज मुझे बोलने के लिए कहा गया है वह है स्वास्थ्य, हेल्थ । महोदय, अंग्रेजी में कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन महोदय स्थिति क्या है । महोदय, बिहार की स्थिति भयावह है, आज लगातार स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्था है और महोदय, हम कहना चाहते हैं कि डब्ल्यू0एच0ओ0 का जो मानक है उसके अनुसार महोदय, 1 हजार की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए लेकिन सी0ए0जी0 क्या कह रहा है, सी0ए0जी0 कह रहा है कि 22 हजार पर मात्र 1 डॉक्टर इस बिहार में है । महोदय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की जो स्थिति है वह बद से बदतर है, पूरे बिहार में ए0एन0एम0 हो, कर्मी हो कहीं पर भी अपनी ड्यूटी निभाते नहीं हैं, वह 11 बजे लेट नहीं और 1 बजे भेंट नहीं, यह कहावत उनके साथ चरितार्थ होती है । महोदय, लगातार बिहार में जो स्थिति है, खासकर बेड के बारे में महोदय, यह इतनी भयावह स्थिति है कि कोई मरीज किसी गांव में, कहीं रोड एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार का ब्रेन हैमरेज होता है, हार्ट–अटैक आता है तो महोदय, वह गांव के गरीब लोगों से बात करता हूं कि हमें पटना जाना है और महोदय, इस प्रकार का उसके साथ शोषण होता है कि पूरी तौर पर एम्बुलेंस के माध्यम से वह पटना के लिए तो निकलते हैं और जब एम्बुलेंस के चालक से ये बात करते हैं कि हमें पी0एम0सी0एच0 जाना है तो महोदय, चालक क्या बताता है, वह चालक बोलता है कि पी0एम0सी0एच0 में यमराज रहते हैं, वहां से कोई लौटकर आता नहीं है । महोदय, यह स्थिति है और वह व्यक्ति भटकता है, वह कहता है कि आखिर हम जाएं तो कहां जाएं, लेकिन महोदय, हम तो देखते हैं कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, अल्लाह को किसी ने देखा नहीं लेकिन डॉक्टर को महोदय, भगवान के रूप में समाज उसको देखते हैं और पूजते हैं, लेकिन महोदय, वही एम्बुलेंस वाला मरीज को बेचता है और वह किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है और प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद महोदय, उसके चप्पल से उसकी पहचान होती है कि चप्पल उसका बाटा का है या वूडलेंड का है, जूता उसका बाटा का है या वूडलेंड का है, गर्दन में सोने की चैन है कि नहीं, उससे उसका मूल्यांकन होता है और उसके मूल्यांकन के बाद महोदय, उसके साथ इतना शोषण होता है उसके

ईलाज में, पूरे पटना में महोदय, आप देख लीजिए जिनके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है, कुकुरमुत्ते की तरह पटना के बाईपास इलाके में महोदय, बस स्टेंड के इलाके में महोदय, रामकृष्णा नगर के इलाके में महोदय, चारों तरफ शॉर्ट–कट के माध्यम से कैसे हम करोड़पति हो जाएं, कैसे हम बड़ा लोग हो जाएं । महोदय, यह जो पेशा था डॉक्टरी, यह तो सेवा भाव था महोदय, लेकिन आज हो क्या रहा है ये पूरी तरह से कम समय में कैसे कितना बड़ा आदमी हम बन जाएं, शर्मनाक है महोदय और सरकार का महोदय, इस पर कोई अंकुश नहीं है । सरकार राम भरोसे चल रही है, सरकार सिविल सर्जन के माध्यम से, उसको छोड़िए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली कर सकती है क्या ? महोदय, सरकार के पास कोई ऐसा उड़नदस्ता नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगावें । महोदय, यह सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, आप जब जिला में जाएंगे, चाहे समस्तीपुर का जिला हो, दरभंगा का जिला हो, चाहे कोई अनुमंडल हो महोदय, चाहे कोई प्रखंड हो सभी जगह यह लूट मची है पूरी तरह से और सरकार का कहीं कोई पॉलिसी नहीं है । महोदय, स्थिति और भी भयावह है कि जब कोई मरीज अपनी कंस्टीचुएंसी का है, यह कहता है कि विधायक जी हमें वेंटिलेटर उपलब्ध करवा दीजिए, प्राइवेट अस्पताल में मैं 3 लाख दे चुका, 4 लाख दे चुका, आप मुझे दिला दीजिए और स्थिति यह होती है महोदय, कि प्राइवेट अस्पताल वाले जो मरीज डेथ कर जाते हैं उससे भी पैसा वसूलने का काम करते हैं, यह सबसे बड़ा शर्मनाक है और सरकार मूकदर्शन बनी हुई है महोदय । हम कह रहे हैं कि सरकार पॉलिसी क्यों नहीं बनाती, इसपर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती, सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों का भला हो । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज लगातार बजट का जो दायरा है, डब्ल्यू0एच0ओ0 ने माना है कि जो बजट का दायरा है उससे महोदय, 6 परसेंट हेल्थ विभाग को खर्च करना चाहिए, खर्च कितना करते हैं, लेते कितना हैं 1.5 से 2 परसेंट का यह बजट बनाने का काम करते हैं महोदय, यानी इनकी मंशा नहीं है कि गरीबों का भला हो सके । महोदय, हम कहना चाहते हैं अस्पतालों की जो हालात है बेहद खराब है महोदय, अस्पताल में ओ0पी0डी0 में आप जब देखेंगे तो पेट खराब, माथा दर्द और बदन दर्द ये टोटल के टोटल महोदय, एक ही दवा है, इसकी दूसरी कोई दवाई नहीं है महोदय और सरकार लगातार मूकदर्शक बनकर और हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि जो दवा है उसकी गुणवत्ता नहीं है, उसकी कभी जांच नहीं की जाती है और उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार है । महोदय, सरकारी अस्पतालों में प्रसव की स्थिति है कि बगैर विशेषज्ञ चिकित्सक के और नर्स के ममता और आशा के भरोसे उसका महोदय, ऑपरेशन हो रहा है, हम तो कहना चाहते हैं महोदय, ममता

और आशा से प्रसव, कम्पाउंडर से ईलाज, सरकारी अस्पतालों की यही हकीकत बन गयी है, आज महोदय, यही स्थिति है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार में महोदय, 6 हॉस्पिटल को चयनित किया गया था, वह हॉस्पिटल है महोदय, एस0के0एम0सी0एच0, डी0एम0सी0एच0, पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0 और आई0जी0आई0एम0एस0 (पटना) लेकिन महोदय क्या हुआ । आज बेड के लिए पटना के आई0जी0आई0एम0एस0 में महोदय बेड उपलब्ध कराने के लिए कोई भी माननीय सदस्य हों दिल पर हाथ रखकर देख लें, बिना कोई पैरवी के मरीज का वहां ईलाज होता है, यानी पूरी तरह से महोदय, पूरे बिहार में यह संदेश चला गया है कि

क्रमशः

टर्न–9 / सुरज / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री रणविजय साहू : जब तक कोई विधायक नहीं, कोई एम0पी0 को हम नहीं पकड़ेंगे मेरे मरीज का ईलाज होने वाला नहीं है, मेरे मरीज को जगह नहीं मिल सकती है । तो यह हालत है ।

महोदय, मेदांता अस्पताल को आपने एक रुपया में दिया था । किसलिये दिया था, इसलिये दिया था न कि गरीबों का ईलाज हो । उसको पचहत्तर सीट जो आपने कहा था कि सुनिश्चित करने के लिये, कितने गरीबों का ईलाज होता है । एक भी गरीब का ईलाज मेदांता में नहीं होता है और हम कहना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड आपने जो गरीबों के लिये बनाया, मेदांता हॉस्पीटल में उसको मान्यता नहीं मिलता है । महोदय, यह है हकीकत मेदांता अस्पताल का । महोदय, आपके बीच हम कहना चाहते हैं, अभी दो दिन पहले ही मेरा अतिपिछड़ा समाज का बेटा पिंटू ठाकुर का बेटा, रोहित ठाकुर जो 22 वर्षीय था, एक्सीडेंट कर गया । अभी पटना के विलिव इमरजेंसी हॉस्पीटल, रामकृष्णा नगर में भर्ती है । परसों वह भर्ती हुआ है और हॉस्पीटल वाला कहता है कि मेरे यहां पांच लाख का पैकेज है । मैंने कल खुद उसे फोन किया था, उसने कहा कि जो मरीज आता है, वह मेरे यहां से जाता नहीं है, मेरे यहां तो पैकेज है । तो यह मनमानी है आपके पटना में जो अस्पताल है, बाउंसर रखकर, बड़े–बड़े राइफल, बंदूक रखकर गरीब मरीजों का शोषण करने का काम करते हैं, यह स्थिति है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि लगातार बिहार में जो निजी प्रैक्टिस वाले हैं । आई0जी0आई0एम0एस0 का मानक था, आई0जी0आई0एम0एस0 की जब स्थापना हुई थी तो यह मानक था कि कोई भी डॉक्टर प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा । लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारे डॉक्टर हैं लगातार प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम तो बचपन से सुन रहे

हैं कि प्राईवेट प्रैक्टिस बंद होगा, आखिर कब होगा ? 20 वर्षों से तो आपकी सरकार है...

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ । कृपया समाप्त करें ।

श्री रणविजय साहू : आपका विजन नहीं है इसलिये हम कहना चाहते हैं कि पूरी तौर पर बिहार में जो स्थितियां, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को जब मौका मिला था 17 महीना काम करने का मौका मिला था, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ तो आप देखिये कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री रणविजय साहू : बिहार में किस प्रकार से मिशन 60 करके...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार ।

श्री रणविजय साहू : उन्होंने बिहार में औचक निरीक्षण करने का काम किया था...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार अपना पक्ष रखें ।

श्री रणविजय साहू : और माननीय मंत्री जी को तो बंगाल से फुर्सत नहीं है और लगातार एक बार भी औचक निरीक्षण नहीं होता है...

अध्यक्ष : आप आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं ।

श्री रणविजय साहू : जिसके कारण लगातार बिहार में जो डॉक्टर और कर्मी हैं लापरवाही बरतने का काम कर रहे हैं इसलिये महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आज स्वास्थ्य विभाग के लिए लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । बिहार के 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी के...

श्री रण विजय साहू : महोदय...

अध्यक्ष : सुनील जी एक सेकेंड । बोलिये ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, हम यह मांग करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार जी, बोलिये।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आज स्वास्थ्य विभाग के लिए लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । बिहार के 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है और तेज गति से सुधार हो रहा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाएं । बैठ जाइये प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य डॉ0 सुनील कुमार । आपके पास बारह मिनट का वक्त है ।

डॉ0 सुनील कुमार : जहां आज से 20 वर्ष पूर्व, जो बिहार था वह गढ्ढ़ों का बिहार था, अंधकार का बिहार था, आतंकराज का बिहार था, जातीय नरसंहार का बिहार था, चरवाहा विद्यालय का बिहार था, लाठी में तेल पिलावन का बिहार था और भूरा बाल साफ करो का बिहार था । वह ऐसा बिहार था जहां अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा हुआ करता था । उस बिहार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एन0डी0ए0 के सरकार में जिस तरह आगे बढ़ाया है, वह अद्वितीय है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे, बैठे मत बोलिये । आपको मौका मिला था, अब बाद में बोलियेगा ।

डॉ0 सुनील कुमार : आज बिहार देश के सबसे तेज गति में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये सब लोग ध्यान से।

डॉ0 सुनील कुमार : विकास करने वाला राज्य बन गया है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है । उस संकल्प को पूरा करने के लिये बिहार कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिये पूरी तरह तैयार हो चुका है । वर्ष 2005 के पहले जहां बिहार में लोग कहते हैं कि 06 ही मेडिकल कॉलेज थे, मैं कहता हूं कि 03 ही मेडिकल कॉलेज थे । 03 मेडिकल कॉलेज एन0एम0सी0एच0, मगध मेडिकल कॉलेज और एस0के0एम0सी0एच0 तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था जो 1970 के दशक में, उसको सरकार ने अधिग्रहण किया । इसका मतलब है कि 90 के पहले की सरकार भी हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया । लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी मेडिकल कॉलेजों का जाल पूरे बिहार राज्य में बिछना शुरू हो गया और अभी जो कार्यरत मेडिकल कॉलेज हैं एम्स, पटना, पी0एम0सी0एच0, पटना, डी0एम0सी0एच0, दरभंगा, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, गया, एस0के0एम0सी0एच0, पटना, एन0एम0सी0एच0, पटना, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर, आई0जी0आई0एम0एस0, पटना, वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज, पावापुरी, जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, बेतिया, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, पूर्णियां, ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज, पटना ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हर जिला मुख्यालय में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव रखा है । जो प्रपोज्ड मेडिकल कॉलेज हैं गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, समस्तीपुर, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, छपरा, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, झंझारपुर, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, वैशाली, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, सीतामढ़ी, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, मोतिहारी, लॉर्ड मेडिकल कॉलेज, सुपौल,

गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, जमुई, गर्वनमेंट मेडिकल कालेज, बक्सर, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, सीवान, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, आरा, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, बेगूसराय, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, सहरसा, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, मुंगेर, गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, गोपालगंज है । महोदय, मेडिकल कॉलेज में प्रपोज्ड किया गया है कि 423 कर्मी भी वहां अप्वाइंट होंगे तो बेरोजगारी की समस्या भी बिहार की दूर होगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले के बिहार में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिये बिहार के स्टूडेंट तरसते रहते थे, 700 से 800 सीट था । लेकिन आज बिहार राज्य में 2640 मेडिकल स्टूडेंट का सीट उपलब्ध है । हमारे प्राईवेट मेडिकल कॉलेज ने भी बिहार गवर्नमेंट का साथ दिया है । देखिये प्राईवेट मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, किशनगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज, रोहतास, लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज, सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, राधा देवी जे0एम0 मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज, सहरसा, हिमालय मेडिकल कॉलेज, पटना उपलब्ध है । महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अब विश्वस्तरीय में परिणति होने जा रहा है । 5540 करोड़ की लागत से 5462 बेड का पी0एम0सी0एच0 बनने जा रहा है । दो टावर स्टार्ट हो गये हैं, करीब–करीब 1100 बेड पर चिकित्सा उपलब्ध है । इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीच्यूट है । 100 बेडों से बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 02 लाख 80 फुली एयर कंडीशन हॉस्पीटल पी0एम0सी0एच0 कंपाउंड में बनाकर रखा है । पिछले वर्ष उसमें एक लाख मरीजों का ईलाज हुआ है, एक लाख रजिस्ट्रेशन थे । इस अस्पताल में डेली 5 से 8 ओपेन हार्ट सर्जरी होते हैं, 5 से 8 स्टंट लगाये जाते हैं । करीब–करीब 40 एंजियोग्राफी होता है, करीब–करीब 06 से 08 पेसमेकर लगाये जाते हैं । एक ऐसी योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बाल ह्रदय योजना ।

(क्रमशः)

टर्न–10 / धिरेन्द्र / 16.02.2026

...क्रमशः...

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, जिसके लिए पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के ऐसे बच्चे जिनको कन्जेनिटल हार्ट डिजीज हुआ करता था, जिनके हार्ट में छेद हुआ करता था, सरकार अपने पैसे से बिहार के बाहर अहमदाबाद के सत्यसाईं हॉस्पिटल में फ्लाईट से ले जाकर रहने, खाने सारी व्यवस्था, ईलाज की व्यवस्था करती थी, वैसे बाल ह्रदय योजना के अंतर्गत बच्चों का ईलाज भी अब उसी इंदिरा गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हो रहा है और 500 से ज्यादा बच्चों का ईलाज भी हो चुका है ।

महोदय, वर्ष 2005 में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब मरीजों की मदद के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया था, ऐसे असाध्य रोग गरीबों के बीच में जब होता है, जिनकी आय एक लाख से कम होती है तो उनको इसके द्वारा सहायता दी जाती है । महोदय, अभी विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है,

(व्यवधान)

नेता नहीं, जो भी सदस्य हैं वे कह रहे थे । मैं आपको बताना चाहता हूँ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें । आपस में बात नहीं करें ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, मरीजों को फ्री डायरेक्ट डिफ्यूजन में, पूरे हिन्दुस्तान में, पूरे भारत में बिहार अव्वल स्थान रखता है । 611 मेडिसिन फ्री में दिये जाते हैं, 17 विशेष मेडिसिन फ्री में दिये जाते हैं । 100 से 132 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट गरीबों को फ्री में दिये जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास की हों, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है । आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰ में 1200 बेड का नया सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें 90 बेड का अत्याधुनिक आई॰सी॰यू॰ होगा, 160 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होगी । मुँह, गर्दन और सिर के कैंसर पीड़ितों के लिए बिहार में गंगवारा दरभंगा में 100 बेडों का अस्पताल खोल दिया गया है । महोदय, हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंसर जब डिटेक्ट हो जाता है तो उस मरीज को साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर में 100 बेडों का कैंसर पायरेटिव थैरेपी इंस्टीच्यूट खोला गया है । महोदय, नेत्र की बात करें तो राजेन्द्र नगर हॉस्पिटल को स्पेशली नेत्र के लिए बनाया गया है और विशेष सुविधा बिहार के लोगों को मिल सके इसीलिए पी॰पी॰आई॰ मोड में शंकर आई फाउंडेशन, कोयंबतूर से एक एलायंस किया गया है जिसकी आधारशिला भी कंकड़बाग में रख दी गयी है । महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में मीठापुर पटना में एक अति अत्याधुनिक बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। गरीब मरीजों के हितों को देखते हुए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोइयां भी चलती है जिसमें न सिर्फ मरीज बल्कि उनके परिवार को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई है और मात्र 20 रुपये में खाना उपलब्ध होता है । महोदय, पटना के राजवंशी नगर में हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड है ऑर्थोपेडिक एण्ड न्यूरो के लिए, महोदय, 136 बेड का हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर फुल्ली एयर कंडिशनर उपलब्ध है, उस हॉस्पिटल में भी 400 बेडों का सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल सरकार खोल रही है । महोदय, सरकार ने मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें, समय हो रहा है ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, 10 मिनट बढाइये, हम भी डॉक्टर हैं, इन लोगों को बता तो दें कि क्या–क्या सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है । सरकार ने मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्था की है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ कर नहीं बोलें । सुनिये ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, सरकार ने एम्बुलेंस की जो सहायता दी है गरीबों को । 102 में फ्री फॉर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ट्रांसपोर्टेशन, 108 में इमरजेंसी एण्ड ट्रॉमा के लिए और एक है 112 जिसको कहते हैं ई॰आर॰एस॰एस॰, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ उपलब्ध है । महोदय, स्वास्थ्य विभाग के कई सुधार और विकास के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर राजकीय औसत, देश की औसत से कम हो गई है । अगर हमारी सरकार ने प्रयास नहीं किया होता तो मातृ मृत्यु दर औसत से कम नहीं होती, बढ़ जाती । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तेज गति से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के कुछ सुझाव भी, आपने कहा सॉर्ट करने के लिए, तो मैं देना चाहता हूँ । महोदय, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ डॉक्टर, स्टाफ हैं और कम हैं तो उसको मुहैय्या कराना चाहिए सरकार को, दुनिया में यह कहा जाता है कि भारत डायबिटीज का प्रयोगशाला है, 70 परसेंट लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं ऐसे परिवेश में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने भी जिला अस्पताल हैं उसमें डायबिटीजोलॉजिस्ट की एप्वाइंटमेंट होनी चाहिए क्योंकि डायबिटीज सिर्फ दवा से ठीक नहीं होती है, उसके खान–पान, रहन–सहन, तौर–तरीके को भी गाईड करना पड़ता है, इसीलिए सभी जिला अस्पतालों में डायबिटीजोलॉजिस्ट होने चाहिए । दूसरा, अभी हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ गई है, युवा वर्ग को भी हार्ट अटैक हो जाया करता है, ऐसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए । कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटीजोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सभी जिला अस्पतालों में एप्वाइंट होने चाहिए । दूसरा, कभी–कभी सुनने में आता है कि दो–दो, तीन–तीन ऑर्थोपेडिसियन हैं लेकिन वे बोलते हैं कि हमारे पास उतना उपकरण उपलब्ध नहीं है तो एक बार पूरे जिला अस्पतालों की समीक्षा करनी चाहिए । मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं उपकरण रहते....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ । महोदय, डॉक्टर की ड्यूटी के संबंध में भी एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम बननी चाहिए और दूसरे सभी अस्पतालों में डॉक्टर के ड्यूटी का डिसप्ले बोर्ड पर नाम होना चाहिए कि कितने से कितने बजे तक इनकी ड्यूटी है और उनका मोबाईल नंबर क्या है ताकि बिहार के मरीज, अगर उनको असुविधा हो तो उनको फोन कर सकें । अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य में बताये गये स्वास्थ्य विभाग के विकास को देखते हुए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चेतन आनंद । माननीय सदस्य डॉ॰ सुनील कुमार, आपका समय समाप्त हुआ । आपका 10 मिनट समय है ।

श्री चेतन आनंद : अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग पर अपनी बात रखने के लिए जो यह मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ । मैं अपनी पार्टी का भी विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो यह विपक्ष के द्वारा लाया गया कटौती प्रस्ताव है उसके विरोध में मुझे अपनी बातों का रखने के लिए एक अवसर दिया ।

महोदय, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भूल रहा है, उनको याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरीके से बिहार हुआ करता था और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहाँ पर स्वास्थ्य को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार माना गया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बिहार के अधिकांश जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को, ज्यादा भरोसेमंद हो रखी हैं और गिने चुने ऐसे जहां पर अस्पताल हुआ करते थे जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा कि वर्ष 2005 से पहले हमारे यहां कोई सुविधाएं नहीं थीं, अस्पताल भी बहुत कम थे और बहुत ऐसे कम अस्पताल होते थे जहां पर लोग जाकर अपनी ईलाज करा पाते थे और हमें याद है कि उस समय हमलोग जब दिल्ली में रहा करते थे क्योंकि यहां पर तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा, यहां रह नहीं पाता था, जो यहां पर आसार थे, हमलोग जाकर वर्ष 2005 से पहले दिल्ली में रहा करते थे और हमें याद है कि कितने सारे लोग...

(व्यवधान)

अपने समय में बोलियेगा । तो उसके बाद....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठे–बैठे मत बोलें । सभी को बोलने के लिए समय दिया गया है ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, एक लाईन लगा रहता था कि दिल्ली के एम्स में लोग जाकर अपना ईलाज कराने के लिए ललाहित होते थे और जो भी यहां के एम॰पी॰ होते थे उनको इतना ज्यादा कुछ झेलना पड़ता था लेकिन आज देखिये कि बिहार के अंदर ही एम्स खुल गया है, पटना में ही एम्स खुल गया है, दरभंगा में खुलने वाला है, यह अपने आप में, हमारी सरकार ने जितना किया है वह दिखाता है, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपलोगों ने क्या किया था...

.

....क्रमशः....

टर्न–11 / अंजली / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री चेतन आनंद : बिहार की जनता जानती है कि यह वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल, एम0बी0बी0एस0 दिलाने के लिए

क्या–क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है । बिहार का बच्चा–बच्चा जानता है कि वे सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एम0बी0बी0एस0 पास की और किस तरीके से पास की यह हमको बताने की जरूरत नहीं है और क्या–क्या हुआ ? उसके अलावा...

(व्यवधान)

आप रूकिए । आप निश्चिंत रहिए । आप लोग का तो इतना एंटी इनकंबेंसी है कि लोग आप लोगों को अभी तक नहीं देखना चाहते हैं, आप लोग इतना कम हो गए, लोग आपको देखना ही नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया आपस में बात नहीं करें । सुनिए बातों को, सबको मौका मिला है । सारे दलों को मौका मिला है ।

(व्यवधान)

श्री चेतन आनंद : गलती से इतने लोग चुनकर आ गए हैं । इसके अलावा आप देखिएगा बिहार में जब हमलोग बात करते हैं, तो यहां के न मरीज सुरक्षित थे, न यहां के डॉक्टर सुरक्षित थे, उस समय का ऐसा मंजर हमलोग देखते थे कि यहां पर डॉक्टर फिरौती के डर से, किडनैपिंग के डर से यहां से बाहर जाकर अपना काम करते थे और लाचार थे, विवश थे कि बिहार से बाहर जाकर उन्हें अपना कमाई करना पड़ता था । लेकिन आज जब हमलोग पटना में हैं, तो मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हमारे पटना में मेदांता है, हमारे पटना में रूबन है, हमारे पटना में ऐसे अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो वे खोलने का काम किए, वह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहां के जो डॉक्टर्स हैं, जो यहां से बाहर जाते थे, वे अब सेफ महसूस करते हैं, उन्हें डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वह बिहार की गवर्नमेंट ने देने का काम किया है । आप लोग रहते, तो वे डॉक्टर आज भी बाहर रहते । आप लोग की देन है कि इतने टाइम तक वे लोग बाहर जाकर आज बाहर के जो...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठिए । बैठ जाइए । बैठ जाइए । बिना अनुमति के मत खड़ा होइए । बिना अनुमति से कृपया न खड़ा होइए । आप बोलिए ।

(व्यवधान)

कृपया शांति बनाए रखें । सभी दलों को मौका मिला है बोलने का, आपने कहा अपनी बातों को । शांति बनाए रखिए ।

श्री चेतन आनंद : डॉक्टर हैं वे लोग वापस आकर अपना टाइम दे पा रहे हैं और बौखलाहट तो होगी ही न, जब कोई सच बोलेगा, तो मिर्ची लगेगी और इसलिए आप लोगों को मिर्ची लग रही है । खैर कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है, सूरमा भोपाली लोग आज संयोग से उस परिवार के मेन है, यहां पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बताइए ।

(व्यवधान)

है न, वही सूरमा भोपाली की बात कर रहे हैं हम । उसके अलावा आपको याद होगा कि वर्ष 2005 से पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेजेज हुआ करते थे, पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0, डी0एम0सी0एच0, जे0एल0एन0एम0सी0एच0, मतलब अंगुली पर गिन लिए जाते थे । आज मुझे याद है कि जब मैं इससे पहले शिवहर का विधायक हुआ करता था तो हमलोग जाकर...

(व्यवधान)

इसलिए न छोड़ें आपको । आपलोग रहने लायक हैं और सुनिए, आप लोग में से जितने लोग हैं वे लोग भी जल्दी छोड़ देंगे, आप लोग भी आ जाइए, आपका स्वागत है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : चेतन आनंद जी, आसन की ओर देखकर बोलिए ।

श्री चेतन आनंद : इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो मैं जब...

(व्यवधान)

महोदय, पर्सनल बातें यहां पर बोलना बहुत गलत बात है ।

अध्यक्ष : रणविजय जी । रणविजय जी ।

श्री चेतन आनंद : आप तथ्यों पर बात कीजिए, हमलोग आपसे बहस कर रहे हैं, बे–तथ्यों पर बात मत कीजिए । उसके अलावा आपको पता होगा कि किस तरीके से, उस समय जब मैं उधर से विधायक हुआ करता था और किस कारण मैं उधर आया यह पूरा बिहार जानता है और उस समय जब मैं इस तरफ आया तो मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने के लिए गए थे और दो मांगों का एक पत्र हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक था अदौरी–खोरीपाकर पुल और उसी पत्र में हमने लिखा था कि शिवहर में एक मेडिकल अस्पताल हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी के लगे हाथ 15 अगस्त को चार जगह, जितने भी छोटे जिला थे, उन सब जगहों पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की । आज बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है, यह होता है काम और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए । उसके बाद आप लोगों को...

(व्यवधान)

15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो इस बार जीत जाते । उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हरेक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज जब हमलोग देखते हैं, हरेक प्रखंड में हमलोगों को हॉस्पिटल दिखाई देते हैं । हरेक पंचायत में ए0पी0एच0सी0 बनने का काम हुआ है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ।

(व्यवधान)

आप निश्चिंत रहिए । जहां पर नहीं बना है, उधर भी बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मैं यह जानता हूं और यह पूरा बिहार जानता है कि वह एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन हुआ है उसकी वजह से यह संभव हो पाया है । साथ ही साथ, जब हमलोग बात करते हैं कि किस तरीके से, यहां पर डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो हमलोगों ने क्रिएट किया है, उसमें एक और बहुत बड़ा काम जो हुआ है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने लगे हाथ हमको लगता है, जितने भी हाल–फिलहाल में डॉक्टर्स की बहाली हुई है, नर्सेस की बहाली हुई है, यह दिखाता है कि बिहार लगातार चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य कैसे प्रोवाइड कर सकें इसके लिए हमलोग चिंतित हैं और इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद कहूंगा ।

साथ ही साथ, कुछ मेरे अपने सुझाव भी हैं जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराई जानी चाहिए ताकि वे लोग पूरी तरीके से अपना काम कर सकें और उनके लिए भी डेली अलाउंस का प्रावधान होना चाहिए । साथ ही साथ, सी0जी0एच0एस0 के तर्ज पर क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान में, यू0पी0 में, महाराष्ट्र में, अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर सी0जी0एच0एस0 के तर्ज पर, वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनलोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, तो इसी तरीके से हम यह मानते हैं कि बिहार सरकार में भी एक सी0जी0एच0एस0 के तर्ज पर होना चाहिए । साथ ही साथ, अपने औरंगाबाद जिला में, क्योंकि वहां पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, तो हम यह कहना चाहेंगे कि बारूण में लगातार...

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चेतन आनंद : वहां पास में एन0टी0पी0सी0 है, बी0आर0बी0सी0एल0 है, वहां पास में सीमेंट फैक्ट्री का रैक है जिसकी वजह से होता यह है कि वहां के लोगों को थोड़ा ज्यादा हेल्थ कम्प्रोमाइज करना पड़ता है ।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें । माननीय सदस्य, श्री मो॰ कमरूल होदा ।

श्री चेतन आनंद : तो ऐसे में हम यह कहना चाहेंगे कि दुधैला ग्राम में दाउदनगर, नवीनगर, मदनपुर और अन्य जगहों से वेल कनेक्टेड है अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हेल्थ की ज्यादा समस्याएं भी उधर दिखाई देती है और औरंगाबाद से थोड़ा पास भी पड़ेगा । यदि इसके ऊपर विचार होता है तो बहुत अच्छा होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मो॰ कमरूल होदा । आपका समय 4 मिनट है ।

श्री मो॰ कमरूल होदा : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े केवल कागजी पत्रों पर समर्पित हैं । सरकार का आंकड़ा बताता है कि प्रतिदिन हॉस्पिटल में औसत 422 मरीजों का इलाज किया जाता है । महोदय, लेकिन इनका इलाज कौन करता है ? महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025–26 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में डॉक्टरों की 17070 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध केवल 8320 डॉक्टर कार्यरत हैं । इसमें भी विशेषज्ञ की संख्या बहुत कम है । महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जिला किशनगंज में रेफरल हॉस्पिटल छत्तरगाछ है, जहां पर 6 से 7 पद स्वीकृत हैं, यहां पर एक भी डॉक्टर नहीं हैं, वहां का इलाज फोर्थ ग्रेड के कर्मी, चतुर्थ वर्ग के कर्मी वहां का दवाई वितरण करता है और वहां जो कोई एक्सीडेंट होकर आते हैं उनकी मरहम पट्टी करता है यह सच्चाई है महोदय । महोदय, किशनगंज जिला में पी0एच0सी0 एवं एच0सी0 में जहां कम से कम 6 से 7 डॉक्टरों का पद सैंक्शन है । महोदय, डॉक्टरों की घोर कमी है । महोदय, किशनगंज में एक सदर अस्पताल है जहां का सैंक्शन पोस्ट 48 से 46 है, जहां पर मात्र 16 से 18 पद ही हैं, वहां पर इतने ही डॉक्टर इलाज करते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–12 / पुलकित / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री मो0 कमरूल होदा : नतीजतन यह होता है कि गांव के दूर–दूर से जो एक्सिडेंटल केस हैं या जो महिलाएं हॉस्पिटल में प्रसव कराने आती है । डॉक्टरों की कमी की वजह से उन्हें बगल के बंगाल, इस्लामपुर और सिलीगुड़ी के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है । महोदय, यह सच्चाई है ।

महोदय, पोठिया प्रखंड अंतर्गत एक रेफरल हॉस्पिटल जो 30 साल पहले 5 एकड़ जमीन पर बनाया गया था । जिसकी हालत जर्जर ही नहीं बल्कि वह हॉस्पिटल एकदम खत्म हो गया है । वहां पर आज तक उद्घाटन भी नहीं हो सका । वह रेफरल हॉस्पिटल करोड़ों रुपये की लागत से पोठिया प्रखंड में बनाया गया और उसकी हालत ऐसी हो गयी कि उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, डॉक्टर भी नहीं दिया गया । महोदय, मेरी मांग है कि उस रेफरल हॉस्पिटल को दोबारा बनाया जाए और वहां पर डॉक्टर का पद दिया जाए और डॉक्टर वहां पर बहाल किया जाए । ताकि गांव के लोगों को आसानी हो, गांव के मरीजों को वहां पर जाकर के इलाज कराने में आसानी हो । यह स्थिति महोदय स्वास्थ्य विभाग की है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया)

महोदय समाज कल्याण विभाग, हमारे जिला किशनगंज के सहित पूरे बिहार राज्य में सी0डी0पी0ओ0 के आंगनबाड़ी सेविकाओं से अवैध वसूली हो रही है । महोदय उन्हें चयन मुक्ति और स्पष्टीकरण की धमकी दी जाती है। महोदय, पोठिया प्रखंड में प्रभारी सी0डी0पी0ओ0 नरेंद्र कुमार सिंह, सेविकाओं के साथ अभद्र व्यवहार, व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी, टी0एच0आर0 की राशि में 15 से 20 प्रतिशत की अवैध वसूली के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 06.02. 2026 को जिला पदाधिकारी किशनगंज द्वारा प्रभार से मुक्त कर दिया गया था। किंतु पुनः आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया से 07.02.2026 को पत्र निर्गत कर प्रभार दे दिया जाता है । जिससे भ्रष्टाचार को और बल मिलने लगता है । महोदय, 6 तारीख को सी0डी0पी0ओ0 को....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, 6 तारीख को सी0डी0पी0ओ0 को वहां से हटाया जाता है। जिला पदाधिकारी उनके भ्रष्टाचार आरोप को देख करके हटाता है...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है । अब आप बैठ जाइये ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, अभी मेरा दो मिनट भी नहीं हुआ होगा । मेरा समय चार मिनट है, मुझे समय दिया जाए ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य आपका समय पांच मिनट का है । मो0 कमरूल होदा जी, कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, सुन लिया जाए ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज, आप बैठ जाइये ।

श्री राजू तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आज स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और सरकार की ओर से, सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, यह बजट का प्रश्न नहीं है। यह जन–जन के जीवन और विश्वास और भविष्य का प्रश्न है ।

सभापति महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संस्थापक, पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा कहा करते थे– राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, समाज सेवा का संकल्प है ।

सभापति महोदय, जिस तरह से सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से

लेकर के बड़े–बड़े अस्पताल में, यही आई0जी0एम0एस0 हुआ करता था, जहां भूत बंगला की तरह लगता था । मैं विपक्ष के साथियों को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह दौर भी देखें ।

(व्यवधान)

वही मैं याद दिलाना चाहता हूं । उस समय वहां पर क्या था ? और आज की स्थिति में जाइए...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य बैठिये, टोका–टोकी मत करिए ।

श्री राजू तिवारी : तो हजारों की संख्या में लोग गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं। महोदय, पी0एम0सी0एच0 एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल आज बन गया है । क्या व्यवस्थाएं थीं महोदय ? कभी...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य बैठे–बैठे मत बोलिये ।

श्री राजू तिवारी : जैसा कि आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, आज लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बहुत सारे जिलों में बन रहा है, नहीं तो सभी जिलों में बनने के लिए पास हो चुका है, काम लगने वाला है । महोदय, इनके राज में क्या था ? कुत्ता कभी–कभी दिखता था, वही फुटेज हम लोग देखते थे उस समय । कुत्ता बिस्तर पर दिखता था । महोदय इतने गंभीर हैं, ये अभी विपक्ष के लोग बोलते हैं कि विपक्ष आईना होता है । महोदय, देखिए किस तरह से मैं देख रहा हूं लगातार सदन में, हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे एक–एक एन0डी0ए0 के मंत्री, वाद–विवाद के सभी गंभीर से गंभीर जो भी विषय आ रहे हैं प्रतिदिन, उस पर कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन–जन की बात, कैसे जन–जन का कल्याण हो, हर क्षेत्र में, हर विभाग का कैसे, उसके बारे में बारीकियों से अध्ययन करके उसपर काम करना चाहते हैं और विपक्ष का आईना कहां है महोदय ? एक दिन आईना दिखा था । हमको लगता था किस परिस्थिति में आईना आया था, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करता हूं । चूंकि ये लोग किस संस्कार के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं ।

(व्यवधान)

महोदय, ये लोग सुनने की धैर्य नहीं रखते हैं । महोदय, ये लोग....

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्यगण, बैठिए । प्लीज बैठिए । बैठ जाइए ।

श्री राजू तिवारी : हम बता रहे हैं । बैठ जाइए–बैठ जाइए । मैं बता रहा हूँ । महोदय, आजतक....

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, शांति बनाए रखिए। बैठिए, बैठिए।

श्री राजू तिवारी : महोदय, ये व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। इन लोगों का संस्कार जंगल राज का संस्कार है । इन लोगों को, महोदय....

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : बैठिए, कोई इस तरह की बात नहीं हुई है । बैठिए ।

श्री राजू तिवारी : बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम बता रहे हैं । बैठ जाइए, बैठ जाइए । बैठ जाइए आप लोग । हम बता रहे हैं । महोदय, यह गंभीरता दर्शाता है। इनकी गंभीरता बिहार के प्रति क्या है ? यह दर्शाता है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आपको लगता है कि संस्कार शब्द बोलना कोई गुनाह है । आप बैठिए ।

श्री राजू तिवारी : नेता प्रतिपक्ष आईना होता है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य आप इधर देखिये और बिना आसन के अनुमति के मत बोला करिए ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं वही कहना चाहता हूं । इन सामाजिक न्याय के लोगों की गंभीरता देखिए । ये सदन के प्रति कितने गंभीर हैं ? बिहार के प्रति कितने गंभीर हैं ? बिहार की मूलभूत समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं ? यह दर्शाता है न कि नेता प्रतिपक्ष आज तक लापता हैं । हम लोग तो सोच रहे हैं कि ये लोग बतावें । इन लोगों को बताना चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, बहुत कुछ नहीं कहते हुए, अब थोड़ी बात मैं अपने विधानसभा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अरेराज रेफरल अस्पताल है । अरेराज रेफरल अस्पताल को देखा जाए थोड़ा सा, वहां पर टेक्नीशियन की आवश्यकता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अरेराज रेफरल अस्पताल को और सुव्यवस्थित करने का कष्ट करें । हमारे यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पिपरा है । वहां मुख्यमंत्री जी गए थे अपने भ्रमण के दरमियान, उन्होंने वहां उद्घाटन किया था । लेकिन कुछ जमीन की कमी के कारण, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि वहां पर भवन बन नहीं रहा है और उसी में मलाही हमारे यहां एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वह बहुत पुराना अस्पताल है । महोदय, उस अस्पताल को थोड़ा और बनवा करके, व्यवस्थित कर डॉक्टर हमेशा वहां रहें, यह व्यवस्था करने की बात करते हैं। वैसे ही संग्रामपुर में है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : भाई वीरेंद्र जी, आप सीनियर लोग हैं । थोड़ा दूसरों की भी सुनिए ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, ये लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाले लोग हैं । ये लोग कल तक हमारे नेता, हमारे संस्थापक के खिलाफ बोलते थे अनर्गल बात । इन लोगों को व्यक्तिगत टिप्पणी करने में महारत हासिल है । महोदय, ये जंगल राज, लाठी और तेल पिलावन की संस्कृति के लोग हैं । ये लोग कभी सभ्यता, मुख्यमंत्री तो कहते हैं...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, तो ये लोग पहले अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे । महोदय एक मिनट, बस लास्ट कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, इन लोगों को माफी मांगना नहीं है । अब मूर्ति की बात करते हैं । मूर्ति की बात आपकी कृपा से नहीं है, हमारे नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं और इसकी चिंता आपके रहमोकरम पर नहीं, आप हमारे संस्थापक नहीं हैं ।

(व्यवधान)

आप स्थिर रहिये । आपलोग स्थिर रहिये । आप पत्र दिखा दीजिए । आप बैठ जाइये । आपको कोई शर्म नहीं है । जिसके चलते आप सदन में पहुंचे...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : राजू तिवारी जी बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री मो0 गुलाम सरवर ।

श्री राजू तिवीर : आप बेशर्म लोग हैं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी आपका समय समाप्त हो गया । बैठ जाइये।

(व्यवधान)

राजू तिवारी जी आपका समय समाप्त हो गया ।

टर्न–13 / हेमन्त / 16.02.2026

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री गुलाम सरवर जी। आपका समय चार मिनट है।

(व्यवधान)

राजू तिवारी जी, आपका समय समाप्त हो गया। अब आप बैठ जाइये।

माननीय सदस्य श्री गुलाम सरवर। आपका समय चार मिनट है।

(व्यवधान)

प्लीज, बैठ जाइये, हो गया।

श्री मो0 गुलाम सरवर : महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : सर्वजीत जी।

श्री मो0 गुलाम सरवर : महोदय, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। महोदय, मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अखतरूल ईमान साहब का, साथ ही अपने विधानसभा की महान जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे आपके समक्ष अपने क्षेत्र की पीड़ा को बताने के लिए, आपके दरमियान में खड़ा किया है। महोदय, हम सीमांचल इलाके से आते हैं, बायसी विधानसभा से। महोदय, सीमांचल इलाका पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पीड़ित इलाका है। पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब इलाका है, जहां सबसे बड़ा पलायन का मसला है, जहां नदियां जिस इलाके को तबाह और बर्बाद करती रहती हैं। मैं ऐसे इलाके की पीड़ा को लेकर आपके दरमियान में खड़ा हुआ हूं। जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे सीमांचल में जितनी भी विधानसभा हैं, जो भी उसका जिला है, सभी जगहों की ये कहानी है कि वहां जितने भी पद हैं, महोदय, आधे पद तो खाली पड़े हैं और आधे पर जो डॉक्टर हैं, खास तौर पर मैं बायसी विधानसभा की बात कर रहा हूं, अपने प्रखंड और अपने अनुमंडल में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी बात कर रहा हूं। बायसी अनुमंडल में कुल 12 डॉक्टर्स के पद हैं, 6 पर बहाली है, और 5 दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्त कर दिये गये हैं, महोदय। केवल एक पद पर ही वहां डॉक्टर साहब हैं। सोचिए, इलाज की क्या व्यवस्था है वहां पर। महोदय, उसी तरह डगरवा प्रखंड में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहां भी आठ पद हैं, चार पर ही नियुक्ति है और उन चार में से तीन पर डॉक्टर गायब हैं। पूछा जाता है, तो दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। महोदय, एक डॉक्टर के भरोसे दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। जहां पर 200 से ज्यादा प्रतिदिन ओ0पी0डी0 में पेशेंट आते हैं। तकरीबन एवरेज 15 के लगभग प्रतिदिन प्रसव का मामला है। महोदय, केवल ए0एन0एम0 के ऊपर सारी स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर चल रही है। न महिला विशेषज्ञ डॉक्टर है वहां पर, न ड्रेसर है वहां पर, न ही वहां पर सही ढंग से कोई इलाज होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, खासतौर पर मेरे विधानसभा के दोनों केंद्रों में, जो डॉक्टर ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जिसको दूसरी जगहों पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, उसको पुनः वहां पर बहाल किया जाए ताकि महोदय, वहां पर इलाज की जो व्यवस्था है, वह हो सके। वहां शव वाहन की जरूरत है, एंबुलेंस दो ही हैं। महोदय, यह दोनों स्वास्थ्य केंद्र एन0एच0–31

पर है, जहां आए दिन एक्सीडेंट होता है। महोदय, वहां एक ट्रामा सेंटर की जरूरत है। इसी तरह का मामला हमारे अमौर में भी है, कोचाधामन में भी है, बहादुरगंज में भी है, बलरामपुर में भी है। इन तमाम जगहों पर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। महोदय, अभी हाल के दिनों में एक लिंचिंग हुआ, मर्डर हुआ अतर हुसैन का। दो महीना चार दिन हो गये हैं, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आयी है ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़े। यह व्यवस्था है। महोदय, मैं आपके माध्यम से, खासतौर पर सीमांचल में, जो एक बड़ी बीमारी है, कैंसर। महोदय, आपके पटना में जितने भी अस्पताल हैं, जहां भी कैंसर का इलाज होता है, वहां अगर उसको देखा जाए, तो तीन हिस्सा पेशेंट सीमांचल से आते हैं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मो0 गुलाम सरवर : हम चाहते हैं कि सीमांचल में एक कैंसर का हॉस्पिटल खुले इलाज के लिए महोदय, यह बहुत ही पीड़ित इलाका है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जाइये।

श्री मो0 गुलाम सरवर : यह इस बिहार का दुर्भाग्य है कि सीमांचल सबसे...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह। आपका समय एक मिनट है।

श्री मो0 गुलाम सरवर : महोदय, वहां सैलाब भी तबाही मचाए हुए है। आपदा की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नदी कटान हमारे यहां का बहुत...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज, बैठिए आप। अब बैठ जाइए। आपका समय समाप्त हुआ, बैठ जाइए।

श्री अरूण सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात अपने क्षेत्र की मांग से शुरू करता हूं। विक्रमगंज में अनुमंडलीय अस्पताल है और आठ प्रखंड का वह अनुमंडल है। वहां ए0एन0एम0 की भी ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होती है और आवास भी है, लेकिन चहारदीवारी नहीं होने के चलते बहुत अव्यवस्थित है। हम मांग करते हैं कि चहारदीवारी बनायी जाए। महोदय, एक बात हमको समझ में नहीं आती है, यह अंतर्विरोधी बात लगती है, हम कह रहे हैं कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट कर रही है, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, खोल रहे हैं। पहले बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र का हमने निर्माण कराया है। डॉक्टर की हमने बहाली की है, यह बात हम समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, उतने ही प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। शायद इसका दबाव सरकार...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह जी, आपका समय समाप्त।

श्री अरूण सिंह : समय हो गया सर ? इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर जो भी बात बोल रहे हैं इस मामले में, उसकी कोई सत्यता नहीं है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जाइए। श्री सतीश कुमार सिंह। एक मिनट समय है आपका।

(व्यवधान)

ऐसा नहीं है, सबके साथ एकरूपता रखी गयी है।

श्री सतीश कुमार सिंह : सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय, स्वास्थ्य पर सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों को कहना चाहता हूं। महोदय, हमारे विधानसभा में रेफरल अस्पताल, रामगढ़ है। वहां 13 पद डॉक्टरों के स्वीकृत हैं, लेकिन मात्र वहां पर 10 डॉक्टर खाली हैं और मात्र तीन डॉक्टर कार्यरत हैं, मतलब, 10 पोस्ट खाली हैं वहां पर। वही हाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दुर्गावती का है। 14 स्वीकृत पद हैं, वहां पर 11 पद खाली हैं। प्रखंड नुआव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका भी वही हाल है। सदर अस्पताल, भभुआ की स्थिति यह है कि 57 पोस्ट हैं और 34 पोस्ट खाली हैं, मात्र 23 डॉक्टर कार्यरत हैं। महोदय, जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे, तब तक इलाज कैसे संभव हो पाएगा ? तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि एन0एच0–19 पर दुर्गावती के पास बिहार सरकार की बहुत सी जमीन है,

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सतीश कुमार सिंह : वहां स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण कराया जाय।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सतीश कुमार सिंह : महोदय, हम लोगों का कैमूर, स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आपको एक मिनट ही दिया गया है। प्लीज, अब आप बैठ जाइये।

श्री सतीश कुमार सिंह : महोदय, हमारे इलाके के लोगों को तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री अजय कुमार, अपना पक्ष रखिये।

श्री सतीश कुमार सिंह : महोदय, एक और चीज, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, लेकिन कार्य नहीं हुआ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री अजय कुमार। एक मिनट समय है आपका।

श्री अजय कुमार : सर, छोटा दल है, एक मिनट से तो काम नहीं चलता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात, किसी भाषण में जाए बगैर, मैं सीधे मुद्दों की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, आपका 8 प्रतिशत का जो लक्ष्य रखा था राष्ट्रीय स्तर पर, यह 2025–26 में 6.6 प्रतिशत का आवंटन है, जो हमें लग रहा है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि राज्य में जो 39 प्रतिशत महिलाएं हैं, ग्रीन ऊर्जा की कमी, कोरोनिल एनर्जी डेफिशिएंसी रोग से ग्रसित हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा ? तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर यह सच्चाई है

कि सिर्फ पटना में बड़े–बड़े हॉस्पिटल खोलने से काम नहीं चलेगा। आपका बिहार, पूरा बिहार है। प्रखंड के अंदर जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं। सदर अस्पताल है, उसमें डॉक्टर नहीं हैं। एविडेंस के तौर पर मैं कहना चाहता हूं और उदाहरण के तौर पर कि समस्तीपुर, ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, जो जिला का इकलौता हॉस्पिटल है, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, वहां पर रेडियोलॉजी नहीं है। वहां पर 200 स्टाफ हैं, उसके जगह पर सिर्फ 57 स्टाफ हैं।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आपका...

श्री अजय कुमार : सर, बस खत्म कर रहे हैं। पांच वेंटिलेटर, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, पड़ा हुआ है। सिर्फ टेक्नीशियन आपके नहीं रहने के कारण वह धूल फांक रहा है।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अजय कुमार : लाखों का आपका बर्बाद हो रहा है। सर, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य से कोई भी पेशेंट आये, तो उसको भर्ती करना चाहिए, वापस नहीं करना चाहिए।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। एक मिनट समय है आपका।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, आप एकदम कटवा देख कर देखते हैं। सर, 58 सेकंड से आप बोलना चालू करते हैं। हुजूर, थोड़ी सी दया कीजिए, सहरसा बहुत गरीब जिला है। सर, डब्ल्यूएचओ,..

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : शांति, शांति।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, अब मैं समय नहीं मागूंगा।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब मेरी बात सुनिए। सिर्फ आसन की तरफ देखिए। इधर–उधर मत देखिये।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, इधर से बोलता है, किधर देखें सर ? डब्ल्यूएचओ को रिपेट से सत्तर कटैया गांव है, जो हॉटस्पॉट ऑफ कैंसर माना गया है।

(क्रमशः)

टर्न–14 / संगीता / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : 4 से 5 साल में एक सौ से ज्यादा पेशेंट मरे हैं वहां पर और जब होमी भाभा इंस्टीच्यूट ऑफ कैंसर देखने के लिए गया तो अगल–बगल के गांवों में लगभग 80 परसेंट लोग कैंसर से पीड़ित हैं जो आई0जी0आई0एम0एस0 और महावीर कैंसर संस्थान का रिपोर्ट है और उसी में बड़ा मेहरबानी करके एम्स को यहां से पता नहीं किस साजिश के तहत आपलोगों ने भेज दिया हैं दरभंगा, यह मुझे नहीं मालूम है । वहां से बी0एड0

कॉलेज, सारे कॉलेज वहां से लॉ कॉलेज, बी0एड0 कॉलेज सारा कॉलेज भेज दिया गया...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : नहीं सर, मैं चाहता हूं 217 एकड़ जमीन सैंक्शन है, मैं चाहता हूं वहां कैंसर का जरूर हॉस्पिटल खुलवाइए...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री रामेश्वर महतो, श्री रामेश्वर महतो ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए । समय समाप्त हो गया, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर महतो : महोदय, मैं अपनी...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आपका 3 मिनट समय है महतो जी ।

श्री रामेश्वर महतो : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के लाए हुए प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और आदरणीय नेता श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी की तरफ से रख रहा हूं और अपनी बात रखूं इससे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे गांव में एक बहुत पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था और मैं कोई पुरानी बात, 2005 से पहले की बात नहीं कहूंगा कि उस केंद्र में भैंस बांधा जाता था और भूसा रखा जाता था, मरीज तो वहां कभी नहीं होते थे । जब मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य था, माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था वहां पर बहुत ही बढ़िया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलकर तैयार हुआ और अभी चल भी रहा है, इसी सत्र से शुरू हुआ माननीय मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और जो स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था है पूरे राज्य में वह कम्पेरिजन नहीं कर सकते हैं हम 2005 से इसलिए मैं 2005 से पहले की कोई बात नहीं रखूंगा । महोदय, आज मुझे लगता है कि दुनिया से सबसे बड़ा अस्पताल पी0एम0सीएच0 पटना में लगभग बनकर तैयार होने की कगार पर है । अब मुझे लगता है जॉर्जिया में एक है माननीय मंत्री जी शायद वह देखते होंगे वह 5400 बेड का है और 5462 बेड का है तो मुझे लगता है 62 बेड ज्यादा है ऐसा मुझे लगता है खैर एशिया का ही सही लेकिन जो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, वहां पर अगर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है तो हम बिहारियों के लिए बड़े गर्व की बात है । महोदय, जो–जो स्वास्थ्य विभाग में काम हुए हैं मुझे लगता है कि इस देश में ये राज्य बिहार ऐसा है जहां सबसे ज्यादा गति से स्वास्थ्य विभाग में सुविधाएं उपलब्ध गयी हैं । हमारी जनसंख्या अधिक है, हम गरीब राज्य हैं उसके बावजूद भी मैंने कोरोना के समय में भी देखा जो व्यवस्था बिहार में थी और किसी राज्य में नहीं थी हुजूर । मैं आपलोगों की तरह इसलिए नहीं पिछला बात बोलूंगा क्योंकि आपलोग शोर मचायेंगे मेरा टाइम कम हो जाएगा लेकिन 2005 से पहले लोग डरते थे

अस्पताल में जाने से, 2005 से पहले स्वास्थ्य केंद्र में कोई जाता ही नहीं था, वहां भैंस बांधा जाता था, यह आपलोगों को पता है यह बात । महोदय, आज पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 तैयार है प्रखंडों में और जिस तरह से सुविधाएं हैं और डॉक्टर भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बार जब अपना यात्रा शुरू किया था और माननीय मंत्री जी को मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि जो भी सरकारी अस्पताल में हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं या प्रभारी हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर यह हो जाता है और सुविधा लोगों को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा । महोदय, साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं उसमें एक ग्राउंड फ्लोर पर फिजियोथेरेपी सेंटर हो, बुजुर्गों को खास करके जो समस्या होती है, फिजियोथेरेपी से कई सारी बीमारियों का इलाज हम कर पाते हैं, जैसे–घुटना का दर्द, कमर का दर्द, इसके लिए लोग खास करके बुजुर्ग लोग बहुत...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य...

श्री रामेश्वर महतो : महोदय, मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपको खास करके धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए काम किए । बहुत–बहुत धन्यवाद आपका ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, श्री रोमित कुमार ।

श्री रोमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के लोकप्रिय नेता और अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आपका चार मिनट समय है ।

(व्यवधान)

अपने–अपने सीट पर बैठे–बैठे मत बोला करिए ।

श्री रोमित कुमार : आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी तथा अतरी विधान सभा के देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझपर विश्वास करके इस पवित्र सदन में अपनी आवाज उठाने का अवसर दिया । मैं सरकार के बजट के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। महोदय, 2005 के पहले की बिहार की दुर्दशा कुछ इस प्रकार था :

कभी शाम ढलते ही यहां सन्नाटा घर कर जाता था,
सड़कों पर गड्ढा था या गड्ढे में सड़क बस खुदा ही जानता था,
चुल्हों में धुआं तो था पर चारा कहीं और जाता था ।
लालटेन की मध्यम लौ में विकास अपना मुंह छुपाता था
मेहनत तो बहुत थी पर रंगदारी का ही जमाना था ।
खून–पसीने की कमाई तो बस साहेब के कुनबे को खाना था
वो चरवाहा विद्यालय वाली ज्ञान की अनूठी मांग थी

जहां कलम की जगह मासूम के हाथों में लाठी, पेलावर, रैली थमाई थी...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : बोलने दीजिए न, कितना समय ही हुआ है ।

श्री रोमित कुमार : अब 2005 नीतीश जी की सरकार आयी और नीतीश जी के सरकार में बदलाव हुआ...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : इनको बोलने दीजिए ।

श्री रोमित कुमार : अब समय बदला है और बदली है जीवन की चाल, गांव–गांव सड़कें रौशन हुईं बिछा विकास का जाल...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : रोमित जी, रोमित जी रूक जाइए । आलोक जी बोलिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, चरवाहा विद्यालय दुनिया के द्वारा, पूरी दुनिया में इसको सराहा गया...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : ये कोई महत्वपूर्ण बात आपका नहीं है इसलिए बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

रोमित जी आप अपना बोलते रहिए ।

श्री रोमित कुमार : अब बिजली घर में मेहमान नहीं सहेली बनकर तैरती है हमारी बेटियां अब सड़कों पर निडर होकर चलती है । आपलोगों को सम्मान मिला है ....

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आप बैठ जाइए । आलोक जी आप कृपया अपने सीट पर बैठिए ।

श्री रोमित कुमार : मजबूत साथ मिला है, लालटेन बुझी बिहार में एल0ई0डी0 का नया प्रकाश मिला है और अब लालटेन सिर्फ सिंबल में दिखता है चाहे यहां से भी विलुप्त होने की कगार पर है । कल की बदहाली अब कहानी बन गई, नई दौर की खुशहाली ही नीतीश जी के कामों की रवानी बन गई । महोदय ये पंक्तियां केवल पंक्तियां नहीं बल्कि बिहार के परिवर्तन की जीवंत गाथा है । बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं वह ऐतिहासिक है । वर्ष 2005 में जहां मात्र 6 चिकित्सा महाविद्यालय थे आज 12 संचालित हैं और 13 निर्माणाधीन हैं । हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई है । यह

केवल संस्थाओं की संख्या में वृद्धि में नहीं बल्कि हमारे युवाओं के सपनों को पंख देने और आम जनता को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है । अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है जहां सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहां एक नए सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक विकसित किए जा रहे हैं । जिनमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जैसे विभागों के लिए अत्याधुनिक मशीनें और डॉक्टर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं । गया में कैंसर के इलाज के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया गया है ताकि मरीजों को मुंबई और दिल्ली न जाना पड़े । एक सौ बेड का क्रिटीकल केयर ब्लॉक लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से गंभीर मरीजों के लिए एक समर्पित यूनिट बनाया गया है । आयुष्मान भारत के माध्यम से हजारों गरीब परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है । 2005 के पहले जहां मातृ मुत्यु दर 374 था जो नीतीश जी के सरकार में अब लगभग घटकर 100 के पास आ गया है, शिशु मृत्यु दर जो 61 था वह 27 के पास आ गया है, और पी0एच0सी0 में औसत 30 से 40 मरीज 2005 में आते थे वह बढ़कर लगभग एक हजार प्रतिमाह हो गया है । ये आंकड़े नहीं हैं महोदय, बल्कि संवेदनशील और परिणाम आधारित शासन का परिणाम है महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहता हूं यह सरकार केवल योजनाएं बनाने में विश्वास नहीं करती बल्कि...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य रोमित जी...

श्री रोमित कुमार : मैं कुछ मांगे अपने नेता के सामने रखना चाहता हूं अपने क्षेत्र का...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप समाप्त करिए । माननीय सदस्य रोमित जी आपका समय पूरा हो गया ।

श्री रोमित कुमार : धन्यवाद सर ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री सियाराम सिंह ।

श्री सियाराम सिंह : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार की 18वीं ऐतिहासिक विधान सभा के सदस्य के रूप में पहली बार बाढ़ विधान सभा से चुनकर मैं आया हूं और बाढ़ पटना जिला का एक ग्रामीण अनुमंडल है ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / यानपति / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री सिया राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, लगभग 19–20 वर्षों से मैं वहां चिकित्सकीय कार्य कर रहा हूं और 28–29 वर्षों से इस हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैं जुड़ा हूं । मैं 97 में, 2005 के पहले पटना मेडिकल कॉलेज के छात्र के रूप में

अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक के रूप में मैं बाढ़ में कार्यरत भी था उसके बाद मैं पार्टी से जुड़कर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में सदन में स्वास्थ्य बजट के पक्ष में बोलने का मौका मिला है । महोदय, मैं दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति सुना रहा हूं कि जिसे मैं ओढ़ता हूं, बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं और उसी अनुभव के आधार पर वर्तमान बजट का विश्लेषण भी प्रस्तुत कर रहा हूं । महोदय, 24 नवंबर, 2005 को जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो उसके बाद 2005 के पूर्व जो है स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी । छोटी–छोटी बीमारियों के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता था । डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी थी । प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में थे । दवाओं की उपलब्धता नगण्य थी । फार्मासिस्ट और कंपाउंडर के भरोसे पहले पी0एच0सी0 चलता था और अस्पताल भवनों में पशु बांधे जाते थे और बेड पर, वहां पर कुत्ते लेटे रहते थे । ऐसा न्यूज में जब हमलोग छात्र थे पटना मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा पढ़ते थे महोदय । यानी पूरी व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था कहिए 2005 के पहले आई0सी0यू0 में थी और गुलाबी फाइलों में स्वास्थ्य योजनाएं पड़ी–पड़ी दम तोड़ती थीं महोदय । अब जो है, जब 1990 से 2005 के दौर में जाइये तो मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे और 1990 से लेकर 2005 में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला । काग्रेस के रीजन में भी, मुझे याद है, मैं तो मेडिकल का छात्र रहा हूं, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में बना था, वह आजादी के पहले ही बना है । बाकी जो हमारे अनुग्रह नारायण सिंह, गया मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा महाराज जी का था हमारा एस0के0एम0सी0एच0 मेडिकल कॉलेज और हमारा नालंदा मेडिकल कॉलेज ये चारों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल रहे थे । मात्र सरकार की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज जो 1970 में खुला वह भागलपुर मेडिकल कॉलेज था । तो राजद के साथ–साथ कांग्रेस भी उतना ही स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है जितना राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेवार है । आज राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक लोग हैं जो जीतकर आए हैं, वे खोजते हैं कि स्वास्थ्य, पी0एच0सी0 में डॉक्टरों की कमी है तो महोदय मेडिकल कॉलेज जो है एक तरह से फैक्ट्री होता है डॉक्टरों के निर्माण के लिए तो आपके 15 वर्षों के शासनकाल में कितने मेडिकल कॉलेज खुले, आप आत्मचिंतन कीजिए । ये आपके लिए आत्मचिंतन का विषय है, आप बार–बार टोका–टोकी करते हैं उसमें मैं उस समय छात्र रहा था इसीलिए सारी बातों को मैं आपको बता रहा हूं । और आज देखिए कि मेडिकल कॉलेज जो है 25 के करीब हमलोग पहुंच गए, 12 अभी संचालित हैं और जब मैं पटना मेडिकल कॉलेज में छात्र था तो उस समय सीटों की संख्या पटना मेडिकल कॉलेज में 100,

दरभंगा में 80 मतलब पूरे बिहार प्रांत में साढ़े तीन सौ सीटें थीं आज हमारे यहां करीब–करीब चार गुणा सीटें सरकारी डॉक्टरों का बढ़ गया है और जैसा कि एम0सी0आई0 मानक है कि 50 लाख के पॉपुलेशन पर एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा । हमारे राज्य का पॉपुलेशन 14 करोड़ है तो 28 मेडिकल कॉलेज एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार भी खुलना है महोदय । तो हमारी सरकार हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नीतीश जी, लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी के माध्यम से इसपर काम हो रहा है । तो जो आप मांग करते हैं, हमारे बीच विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमारे यहां दो ही एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर हैं, बाकी आयुष है, डेंटल हैं, जो आपने व्यवस्था बनाई और 2005 में नवंबर में जब हमारी सरकार आई तो जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी उसमें काफी सुधार हुआ । मैंने बताया कि जब मैं मेडिकल छात्र था वहां पर पी0एम0सी0एच0 का जो अब का बिल्डिंग, पहले का बिल्डिंग और अब का बिल्डिंग देखिए, पहले हमलोग जाते थे तो कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से रहता था, आज कनेक्टिविटी हमारा जो है, मरीन ड्राइव से है । और यहां पर जो है 5462 बेड है...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : सियाराम जी, आप अपना संक्षिप्त कीजिए ।

श्री सियाराम सिंह : एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है । महोदय, मातृ मृत्यु दर में भी हमलोग करीब–करीब तीन लाख 74 प्रति 10 लाख जीवित जन्म 104 के करीब पहुंच गए हैं । सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव और ए0एन0एम0 आशा कार्यकर्ताओं की देन है कि आज हमारा अस्पतालों में प्रसव सुरक्षित हो रहा है इसलिए आशा कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपया प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है । 2005 में टीकाकरण जो है, 2005 के पहले टीकाकरण 18 प्रतिशत था आज टीकाकरण 90 परसेंट के लक्ष्य को हमलोग पहुंच रहे हैं । आज मैं जाता हूं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घूमने के लिए तो आज वहां के प्रभारी से पूछता हूं कहां गयी ए0एन0एम0 तो बोलती हैं कि घर–घर टीका करने गई हैं । उसी लक्ष्य को हमलोग पूरा कर रहे हैं । इंद्रधनुष योजना जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके 30 हजार रुपये की टीकाकरण जो है वह हमारे बच्चों को मिल रहा है । सर्वाइकल कैंसर मरीजों को, नियमों में, वैक्सीन उसमें देने का प्रावधान है । करीब–करीब सरकारी संस्थाओं में मरीजों की संख्या आप उस समय 2005 के पहले क्या स्थिति थी 39 आज हमारे यहां 11600 पूरे मंथ में मरीज आते हैं । यानी कि पहले एक दो मरीज ही आते थे आज तीन सौ से चार सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं और दवा भी उनको मुफ्त में मिलता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 दवाएं और जिला अस्पताल में साढ़े तीन सौ दवाएं । महोदय, अब बजट हमारा 2005 के पहले कितना बजट था स्वास्थ्य का 708 करोड़ आज हमारा बजट जो है 21 हजार करोड़ है और भारत सरकार का बजट 1

लाख 7 करोड़ है यानी कि भारत सरकार के बजट का हमलोग 25 परसेंट बजट बिहार सरकार में है ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आपका समय अब समाप्त हो गया । माननीय सदस्या, श्रीमती करिश्मा । 8 मिनट आपका समय है ।

सियाराम सिंह : दो मिनट महोदय । बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल को जिला अस्पताल, ब्लड बैंक की स्थापना बाढ़ मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज खोलने का...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती करिश्मा : रेस्पेक्टेड सर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जिन्होंने, मैं फर्स्ट टाइम एम0एल0ए0 हूं और उन्होंने मुझे वाद–विवाद में भाग लेने का मौका दिया है । मैं धन्यवाद देना चाहती हूं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : शांति बनाए रखिए, उनको बोलने दीजिए ।

श्रीमती करिश्मा : अपने परसा विधान सभा के लोगों को जिन्होंने 45 साल बाद एक महिला पर, अपनी बेटी पर विश्वास जताया । हर जाति धर्म के द्वेष और लोभ से ऊपर उठकर उन्होंने मुझे नेतृत्व का मौका दिया । रेस्पेक्टेड सर, मैं सदन के समक्ष कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहती हूं । CAG reported that the Govt. of Bihar had not prepared any comprehensive health policy…

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : गायत्री जी, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए ।

श्रीमती करिश्मा : or plan to address gaps in health infrastructure or equipment in every healthcare facility and between the financial year 2016-22. 31 percent of budget provisions for health were left unspent in Bihar. सर, मैं पूछना चाहूंगी कि 31 प्रतिशत बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया । अगर खर्च किया गया होता तो यह मंजर और आलम ही कुछ और होता । कितने हॉस्पिटल्स बन गए होते और कितने मरीजों की जान बच जाती । CAG in 2025 flagged significant financial irregularities in several govt. departments amounting to over Rs. 70000 crores नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार बजट का 8 प्रतिशत हिस्सा हेल्थ पर खर्च होना चाहिए लेकिन बिहार में 2026–27 फाइनेंशियल इयर के लिए केवल 6.3 प्रतिशत हेल्थ के लिए एलोकेट किया गया है । Less than 1 percent of states

healthcare expenditure is directed towards health facilities as a result of 70-90 percent patients suffering from many kind of mental health condition they are refused to any kind of treatment. Bihar tops the SDG India index chart with 33.76 percent of its population multidimensionally poor. Bihar remains country's worst performing states in several SDG Indies. According to the data of NCRP of ICMR Bihar is one of the worst cancer affected states in India. बिहार में सर 63.9 परसेंट वीमेन they suffer from anemia.

(क्रमशः)

टर्न–16 / मुकुल / 16.02.2026

क्रमशः

श्रीमती करिश्मा : and children between the ages of 6 to 59 months, उनका परसेंटेज हैं 64.4 परसेंट बच्चे एनिमिया से ग्रसित हैं और स्वच्छ भारत केवल एक खोखला नारा नजर आता है, हाईकोर्ट ने अप्रैल, 2023 में High Court ordered that sanitary napkin vending machines and incinerator should be established in evey middle and High Schools of Bihar but in the past three years I did not come across a single Sanitary napkin vending machine or incinerator in my constituency parsa. Respected Sir, राज्य के पी0एम0सी0एच0 ग्राउंड के पीछे सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पिछले 8 सालों से उसका निर्माण ही हो रहा है, पता नहीं यह हॉस्पिटल 8 सालों के बाद भी खुला क्यों नहीं, किसकी जवाबदेही बनती है । आई0जी0आई0एम0एस0 में पिछले एक साल से पी0ई0टी0 स्कैन मशीन काम नहीं कर रही है । इसके कारण मरीजों को 20 से 30 हजार रुपये प्राइवेट में खर्च करके कैंसर डिटेक्ट करवाने की मशीन है, जबकि यह आई0जी0आई0एम0एस0 में 10 हजार रुपये में हो जाता । वर्ष 2011–2014 में करोड़ों खर्च किये गये ऑटो–एनलाइजर मशीन खरीदने के लिए, लेकिन एक दशक बीतने के बाद भी कुछ मशीनें डिब्बों में बंद पड़ी हैं और कुछ मशीनें पड़े–पड़े खराब हो गयी हैं । आदर्श मानक है कि हर 50 सर्जिकल बेड पर एक ओ0टी0 होना चाहिए अगर पी0एम0सी0एच0 में 200 मरीज भर्ती हैं तो 24 घंटे में 4 से 5 बड़े ऑपरेशन होने चाहिए, लेकिन आलम यह है कि ओ0टी0 की कमी के कारण एक दिन में मात्र 4 से 5 बड़े ऑपरेशन हो पाते हैं ।

''टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं,
और जिल्ले–इलाही के करम देख रहे हैं ।
ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारे,
तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं ।''

पिछले एक महीने से मेरे परसा विधान सभा में रैबीज वैक्सीन मिल नहीं रही है, मैंने सब कुछ पदस्थ अधिकारियों से बात की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है । ये कैसे लोग सरकार में बैठे हैं, जो ये सुद भी नहीं ले सकते गरीबों की, वे गरीब कहां जायेंगे, एक मामूली सा रैबीज वैक्सीन उसके लिए उपलब्ध नहीं है । परसा के सी0एच0सी0 में 50 प्रतिशत विशेष चिकित्सकों की कमी है और आज तक परसा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर आप पी0एच0सी0 की बात करें ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, अब आप संक्षेप कीजिए ।

श्रीमती करिश्मा : उसमें न कोई सर्जन उपलब्ध है, न कोई वहां पर मेडिसिन उपलब्ध है । मेरे औचक निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि ई0सी0जी0 तो हो रहा है, जब मैंने अधिकारियों से बात की तो पता चला कि ई0सी0जी0 के लिए कोई टेक्नीशियन ही नहीं है तो इतना घोर अंधेरा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा, क्यों इस तरह से सरकार मौन बैठी है । 4 district hospital were in Japanese Encephalitis endemic areas and did not have diagnostic services facility like test for Japanese Encephalitis and chikanguniya. CAG noted how state health society and BMSICL failed to serve purpose. सी0ए0जी0 के अनुसार 4 टेस्ट चेक्ड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ओ0टी0 नहीं थे सर, जबकि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैण्र्ड के अनुसार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ओ0टी0 होने चाहिए थे । CAG reported that test checked District Hospitals में 80 परसेंट ड्रग्स शॉर्टेज थी ।

''हम एक उम्र से वाकिफ हैं जनाब,
हमें न समझाइए कि लुत्फ क्या है और सितम क्या है ।
तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं,
कमाल यह है कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं।
मैं इस बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कह दूं,
मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं ।''

Respected Sir, I demand कि मेरे परसा कॉन्सिचुएंसी में जल्द से जल्द रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करायी जाए और सेंटरी नेप्कीन वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर उपलब्ध कराये जाएं ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती करिश्मा : तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि 300 से 400 छात्र या छात्राओं के लिए मेरे परसा विधान सभा में मात्र एक शौचालय है ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : करिश्मा जी, अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य, श्री सम्रीद वर्मा । आपका समय 10 मिनट का है ।

श्रीमती करिश्मा : तो कैसा स्वच्छ भारत और कैसा हम बेटियों का सम्मान कर रहे हैं । धन्यवाद सर।

(व्यवधान)

श्री सम्रीद वर्मा : आदरणीय....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : शांति बनाए रखिए, अपनी–अपनी सीट पर बैठिए ।

श्री सम्रीद वर्मा : आदरणीय महोदय जी, आज मेरे लिए बहुत गर्व का मौका है जब मुझे सरकार के पक्ष में पहली बार बोलने को मिला है, मैं इसके लिए अपने पूरे एन0डी0ए0 नेतृत्व और खासकर हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बहुत–बहुत आभारी हूं और मैं अपने सिकटा के देवतुल्य जनता का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे चुनकर इस सभा में भेजा है । आदरणीय महोदय, आज मैं यहां खड़ा हुआ हूं हमारी सरकार के स्वास्थ्य, परिवहन और भी आदि बजट के प्रस्ताव पर और मैं इसके पक्ष में कुछ बोलना चाह रहा हूं । आदरणीय महोदय, बिहार काफी बदल रहा है और तीव्र गति से बदल रहा है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन और प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉन्सटेंट सपोर्ट के साथ वह डबल इंजन की सरकार इस प्रोग्रेस के पीछे है जो पावर दे रही है हमारे बिहार को, यह बजट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह बजट एक रोड मैप है विकसित बिहार की तरफ ले जाने का । आदरणीय महोदय जी, अगर हम आगे की बात करते हैं, एक विजन की बात करते हैं तो हमें थोड़ा इतिहास देखना चाहिए कि किस तरीके से हम 2000 के पहले, हम नहीं पूरा देश, पूरी दुनिया बिहार को जंगल राज के नाम से बोला करती थी, पहले अगर यहां पर हॉस्पिटल हुए करते थे तो जैसा कि हम सब जानते हैं न्यूजों में आता था किस तरीके से वह खाली पड़े रहते थे और वहां तक पहुंचने के जो रोड्स थे वे रोड नहीं गड्ढे होते थे । आदरणीय महोदय, पहले अगर पी0एच0सी0 सेंटर थे तो यह डाटा है साफ कि मात्र 40 से भी कम लोग पूरे महीने में वहां जाया करते थे और आज अगर हम देखें तो आज का जो डाटा है वह दिखाता है कि नीतीश जी के राज में 11 हजार से ज्यादा पेसेंट्स अब इस सरकार की व्यवस्था पर अपना विश्वास दिखाती है । आदरणीय महोदय, हम देख रहे हैं जैसा कि मेरे पहले भी बोला गया, पी0एम0सी0एच0 एक वर्ल्ड क्लास उसका यूनिट–1 मुख्यमंत्री जी खुद जाकर देखे थे, उसका निरीक्षण किया है, यूनिट–1 और 2 शायद बन चुका और जल्द ही थर्ड और फोर्थ यूनिट भी बन जायेगा और जब वह पूरा कम्प्लीट हो जायेगा तो वन ऑफ द बेस्ट

हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड होगा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो हम बोलते हैं कि विकसित देश के मुताबिक, कम्पटीशन में वह हॉस्पिटल रहेगा । महोदय जी, पहले जो लोग चरवाहा विद्यालय के बारे में बातें करते थे वे मेडिकल कॉलेजों के बारे में क्या बोलेंगे । महोदय जी, आज पहले जब हमने 2005 के बाद नीतीश कुमार जी और एन0डी0ए0 की सरकार आयी थी तो मात्र 6 मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार में थे और वह भी उनके कार्यकाल में एक भी नये नहीं बने थे और उसके बाद आज के समय में वह 6 से बढ़कर 12 ऑपरेशनल कॉलेज हैं और लगभग 13 और अभी अंडर डेवल्पमेंट हैं तो नीतीश जी का जो विजन है ऑलमॉस्ट हरेक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशियलिटी हॉस्पिटल होगी । माननीय महोदय जी, मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे बेतिया जिला में जो जी0एम0सी0एच0 हॉस्पिटल है वह ऑलमॉस्ट नियर कम्प्लीशन है और एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल वह भी एक बनकर ऑलमॉस्ट तैयार है और हम इस पर बहुत गर्व करते हैं । हमारी सरकार ने यहां तक कि आशा बहनों के लिए भी सोचा है और उनका मानदेय बढ़ाकर 3 हजार रुपये तक कर दिया है । हमारे मोदी जी और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो गारंटी है वह दिखाता है कि किस तरीके से बिहार में आयुष्मान कार्ड ऑलमॉस्ट 4 करोड़ लोगों को इशू हो चुका है और ये उनको लाभ देता है, 5 लाख रुपये तक का सबका निजी हेल्थ के लिए ।

क्रमशः

टर्न–17 / सुरज / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री समृद्ध वर्मा : महोदय, आज पूरा बिहार, एक ग्रीन बिहार की तरफ बढ़ रहा है । हमलोग पेट्रोल और डीजल के जो बसेज हैं या पब्लिक ट्रांसर्पोट हैं, वह तीव्र गति से ट्रांजिशन की ओर है और इलेक्ट्रिक और सी0एन0जी0 बसेज भी मेजर सिटीज में अब काफी जल्दी बदल रहे हैं और आ रहे हैं । हमारे पिंक बसेज जो अभी शुरू हुये हैं, वह दिखाता है कि किस तरह से हमलोग वूमन इम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और यह पूरे इंडिया के लिये एक एग्जाम्पल है ।

महोदय, मैं इंडो–नेपाल बार्डर पर पश्चिम चंपारण में सिकटा विधान सभा का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला है और मेरा सिकटा वर्ल्ड के लिये एक गेटवे हो सकता है । हमलोगों के यहां इंडो–नेपाल बार्डर जो रोड हैं, सरकार की तरफ से जो बना है वह हमलोगों के लिये एक लाईफलाइन बन चुका है । मेरे पूरे क्षेत्र में किसी भी कोने से दूसरी जगह जाने में मात्र 15 मिनट लगते हैं और यह एक गेम चेंजर है और वही रोड अंत में पहुंचा देता है हमलोगों को रक्सौल तक । जहां पर एक वर्ल्ड क्लास भव्य तरीके का

एयरपोर्ट, अभी लैंड एक्यूजीशन चालू है और वह भी बनने को तैयार हो रहा है और वहीं रक्सौल से जैसा कि हमारी सरकार ने बताया कि रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेस–वे सिकटा को कनेक्ट कर देगा, मेजर पोर्टस् और ग्लोबल मार्केट्स में । तो Sikta will no longer be a border village but it will be a global hub.

अध्यक्ष महोदय, सिकटा सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक संवेदनशील इलाका है । मेरी विनती है इस सरकार से कि सिकटा के स्ट्रैटेजिक और आर्थिक विकास को हमेशा अपनी विशेष प्राथमिकता में रखें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आज यहां गीता के एक संदेश से समाप्त करना चाहता हूं :

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

इसका अर्थ यह है कि अपने–अपने नियत कर्मों में लगा हुआ मनुष्य ही परम सिद्धि को प्राप्त करता है । इसलिये मेरे फाइनल वर्डस् हैं Serving the people of bihar is our dharma and this budget is our commitment to that duty. मैं अपने पूरे, जो हमारा यह बजट है मैं इसको पूर्ण तरीके से समर्थन देता हूं । जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री अमित कुमार । आपका 5 मिनट समय है ।

श्री अमित कुमार : महोदय, आज इस सदन में पहली बार बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको कोटि–कोटि धन्यवाद देता हूं...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आपका 5 मिनट समय है ।

श्री अमित कुमार : जी, आज मैं इस सदन में लोक जनशक्ति पार्टी(रामविलास) की तरफ से स्वास्थ्य विभाग पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण परिवार के युवा को इस गौरवशाली सदन में आने का अवसर दिया और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री, इस सदन के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और एन0डी0ए0 के सारे हमारे वरिष्ठ साथियों का भी धन्यवाद देता हूं । महोदय, इस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से पहले और स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों को बताने से पहले मैं अपने बेलसंड विधान सभा के देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देता हूं और कुछ पंक्तियों के माध्यम से सदन का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करता हूं :

क्षेत्र की मिट्टी का चंदन माथे पर सजाकर आया हूं,
बेलसंड की जनता का अटूट विश्वास साथ लाया हूं,

सेवा का संकल्प है मन में,
और विजन बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का
विकास की नई इबादत लिखने इस सदन में आया हूं ।

महोदय, आज बिहार के इस गौरवशाली सदन को संबोधित करते हुये मुझे बहुत गर्व हो रहा है और हमारी सरकार न्याय के साथ विकास के संकल्प को दोहराती है । बीते वर्षों में राज्य ने स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया है । आज जब हमलोग 2005 से पहले 6 मेडिकल कॉलेजों की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि भाई आपलोग 2005 से पहले की बात करते हैं । 2005 से पहले की अगर बात की जाय तो स्वास्थ्य और बिजली पर जो भी कहा जाए, हमलोग जब छोटे थे तो लाईन नहीं रहने के कारण, बिजली नहीं रहने के कारण छत पर सोते थे और जब लाईन दो मिनट के लिये आता था तो सब जगह हल्ला होता था कि लाईन आया, लाईन आया । जब हमलोग तकिया, चद्दर लेकर जब नीचे जाते थे, सीढ़ी पर ही रहते थे कि लाईन कट जाता था । तो यह माहौल था उस समय का तो अस्पताल की तो बात ही छोड़ दीजिये । महोदय, आज 12 कॉलेज हमारे यहां चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं और 13 नये मेडिकल कॉलेजों का काम भी बहुत ही तेजी से हो रहा है और साथ ही 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है । पी0एम0सी0एच0 में जहां 5540 करोड़ की लागत से 5062 बेड वाले विश्वस्तरीय अस्पताल का निर्माण हो जा रहा है जिसका लक्ष्य 2028–29 तक पूर्ण करना है । साथ ही, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कैंसर मरीजों के लिये भी विशेष उपचार की व्यवस्था है । मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत भव्य पोर्टल के माध्यम से डिजिटल क्रांति के द्वारा भी स्वास्थ्य के सेवाओं को पारदर्शी बनाया गया है । सरकार स्वास्थ्य के साथ सम्मान भी दे रही है । आशा कार्यकर्ताओं, आशा दीदीयों के मानदेय को बढ़ाकर तीन हजार करना और ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को छः सौ रुपये प्रति प्रसव भी कर दिया गया है । दीदी के रसोई के माध्यम से बीस रुपये में मरीज और उनके परिजनों को सब्सिडाइज्ड युक्त भोजन भी प्राप्त कराया जा रहा है, जो जीविका दीदीयों के आत्मनिर्भर होने का भी प्रतीक है ।

अध्यक्ष महोदय, इन प्रयासों का फल है कि आज बिहार की शिशु मृत्यु दर 23 परसेंट और नवजात शिशु की मृत्यु दर 18 परसेंट हो गयी है, जो कई राज्यों से बेहतर है । यह आंकड़ा गवाही देता है कि बिहार अब पिछड़ों की कतार में नहीं बल्कि विकास की नई अग्रदूत की कतार में खड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय, जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की भी याद हमको आती है, जब वह कहा करते थे कि मैं उस घर में दीया जलाने चला हूं, जहां सदियों से अंधेरा है । वे मानते थे कि सच्चा विकास तभी है जब समाज के सबसे अंतिम पायदान पर

खड़े व्यक्ति के आंखों के आंसू भी पोंछा जा सके । हमारी सरकार आज स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों के दरवाजे तक ले जाकर उन्हीं के सपनों को साकार कर रही है । उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुये माननीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के अनुरूप हमारी सरकार राज्य के स्वास्थ्य संरचना को इतना बेहतर कर रही है कि किसी भी बिहारी को ईलाज के लिये बिहार से बाहर न जाना पड़े । हमारे विजन के अनुरूप चिकित्सा, शिक्षा और विस्तार किया जा रहा है ताकि बिहार के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिये भी बिहार के बाहर न जाना पड़े । मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना और भव्य पोर्टल के माध्यम से डिजिटल बिहार के सपनों को भी साकार किया जा रहा है, जहां 95 परसेंट पंजीकरण ऑनलाइन भी हो रहे हैं । अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार केवल अस्पताल नहीं बना रही है बल्कि एक स्वस्थ भविष्य की भी नींव रख रही है । आयुष्मान भारत के और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चार करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना हमारी सेवा भावना का प्रमाण है । हम एक ऐसा बिहार बनायेंगे, जहां स्वास्थ्य सुविधा केवल विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार होगा । महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का युवा सिपाही होने के नाते मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आज इस तकनीकी युग में विडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से पटना और दिल्ली में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लोगों तक पहुंचायी जा सकती है...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य अब आप अपना भाषण समाप्त करिये ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बस । जिससे धन और समय दोनों की बचत हो सके । सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

श्री अमित कुमार : धन्यवाद महोदय ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार, आपका समय सात मिनट है ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं । अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को और यहां बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष करके बेगूसराय की जनता को जिन्होंने मुझे अपनी आवाज बनाकर इस सदन में बोलने के लिये भेजा है । आज मैं सरकार के पक्ष में और विरोधी दल के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं तो बहुत कुछ लिखकर लाया था, आपने कहा सात

मिनट बोलना है तो मैं शुरू करता हूं । इस बार का बिहार का जो बजट था लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का और उसमें स्वास्थ्य विभाग का बजट है 21 हजार 270 करोड़ का बजट है जो कि 6 परसेंट होता है । अभी हमारे राजद के एक विधायक, मैं बैठकर सुन रहा थ हाऊस में, बराबर और एक के बाद एक बोले जा रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को कि भाई कम से कम 6 परसेंट होना चाहिये खर्चा बजट में और केवल एक परसेंट है और मैं तब से से वही हिसाब जोड़ने में रह गया बाकी विषय छूट गया बोलने वाला कि भाई कैसे साढ़े तीन लाख का 22 हजार करोड़ डेढ़ परसेंट होता है, ये जोड़कर बता दें । एक के बाद एक और कई लोग वहां से वक्ता बोल गये महोदय ।

(व्यवधान)

नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और उसके बाद फिर बोल रहे थे कि इतना ही कम है एक, डेढ़ परसेंट बजट है और कटौती प्रस्ताव भी ले आते हैं कि और कम कर दीजिये बजट । यह दोनों कैसे चलेगा ?

(क्रमशः)

टर्न–18 / धिरेन्द्र / 16.02.2026

...क्रमशः....

श्री कुंदन कुमार : महोदय, और फिर कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का मेडिकल प्रैक्टिस बंद करा दीजिये और उस समय क्या कह गए कि हम बचपन से देख रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब का प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करना है लेकिन बंद नहीं हो रहा है तो जब ये बच्चे थे तो यहां के मुख्यमंत्री कौन थे ? कौन थे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करा दिये । हमारे सम्राट जी तो सदन में कहा है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का, आप क्यों नहीं बंद किये और केवल उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे । महोदय, जब–जब इनको समय मिला, अभी भी नीतीश जी ने मौका दिया, बार–बार नीतीश जी सदन में कहते हैं कि जब भी गड़बड़ करते हैं तो इनको निकाल देते हैं लेकिन जब–जब नीतीश जी ने इनको मौका दिया, इनके युवराज स्वास्थ्य विभाग जरूर लेते थे, क्यों नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दिये। महोदय, केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, चार–चार बड़े विभाग के मंत्री थे, नगर विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और कौन–कौन मतलब डायरेक्टली स्टार के थे और पूरा यह कहते रह गए कि बहुत रोजगार योजना देंगे, भ्रमित कर रहे थे । ये बता दें आज सदन में खड़ा हो कर कि जिस चार विभाग के वहां माननीय मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री भी थे तो कितना रोजगार देने का काम इन्होंने किया है । एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया है इन चार विभागों में....

(व्यवधान)

बैठिये न, आपको ज्ञान नहीं है । बोलने के लिए बार–बार उठ जाती हैं ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, बैठे–बैठे नहीं बोलिये ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, इन चार विभागों में...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, बैठिये । बोलने दीजिये । माननीय सदस्या, आप अपनी जगह पर बैठ जाइये ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, इस सदन में अपने नेता सम्राट जी के सामने कह रहा हूँ कि अगर उस चार विभाग में ये घोषित कर दें कि एक भी नौकरी दिये हैं तो मैं कल अपने विधान सभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । क्या बात कर रहे हैं ? गलत बोलने का काम करते हैं । महोदय, कई सारी बातें आ चुकी हैं यहां पर, कैसे पी॰एम॰सी॰एच॰ एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, कैसे यहां पर और सारे अस्पताल, महोदय, सबसे बड़ा होता है विजन और इस सरकार का वह विजन क्या है? महोदय, केवल जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने का विजन नहीं है, इस स्वास्थ्य सेवा को ग्राम तक, पंचायत तक बनने का, कई जगह देखिये आप प्रखंडस्तर पर कितने अच्छे–अच्छे अस्पताल बन रहे हैं और अपना वेलनेस सेंटर है, पी॰एच॰सी॰ है, ए॰पी॰एच॰सी॰ है, सी॰एच॰सी॰ है । पंचायत स्तर तक एक–एक पंचायत में दो–दो अस्पताल खोलने का काम किया है, यह तो विजन हमारे नीतीश जी और सम्राट जी का है, ये कहते हैं कि कुछ काम नहीं होता है यहां पर । मैं तुलना के तौर पर, महोदय, जो आ गया है उसको रिपिट नहीं करूंगा केवल दो–चार, हमारे मंगल जी के नेतृत्व में अभी यहां पर पटना में ही मीठापुर में 138.19 करोड़ की लागत से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहा है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक अस्पताल है 400 बेड का, प्राइवेट पार्टनरशीप (पी॰पी॰पी॰) मॉडल पर शंकर नेत्रालय को भी लाया गया है और इतना ही नहीं, अगर डबल इंजन सरकार का ये लोग बार–बार कहते हैं कि डबल इंजन सरकार कहां है, अगर डबल इंजन सरकार का कोई मॉडल है तो सबसे बड़ा मॉडल यह बिहार है, यहां आइये, जहां एक तरफ बिहार सरकार इस तरह से अस्पताल ला रही है, वहीं पर केन्द्र सरकार एम्स देने का काम कर रही है, प्रधानमंत्री जन औषधी देने का काम कर रही है और आयुष्मान कार्ड बिहार में लगभग चार करोड़ लोगों को मिल गया है और लगभग 39 लाख जो 70 साल से उम्र में बड़े थे उनको भी आयुष्मान कार्ड देने का काम इस सरकार ने की है और इतना ही नहीं कई ऐसे, आज ओ॰पी॰डी॰ रजिस्ट्रेशन, हमलोग डिजिटल होते जा रहे हैं, पूरा देश डिजिटल हो रहा है, इनको समझ में नहीं आयेगी डिजिटल की बात । महोदय, 95 परसेंट ओ॰पी॰डी॰ रजिस्ट्रेशन अब डिजिटल होता है पूरे बिहार में, एक बार इसके लिए भी लोगों को सोचना

चाहिए, वही बिहार है जहाँ चरवाहा विद्यालय, पहलवान कॉलेज और क्या–क्या होता था, खुलता था । यहां आज हम डिजिटल होते जा रहे हैं । महोदय, 600 से ज्यादा दवाई फ्री में मिलती है, इनके समय में क्या मिलती थी, सरकारी में गए और पूर्जा दे दिए, बोलियेगा तो बहुत कुछ खोल देंगे । इसी बिहार में, इसी पटना में सबसे बड़े पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर हुआ करते थे, उस पेडियाट्रिक के डॉक्टर ने इनके जब मुख्यमंत्री, राजद के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक बड़ी एस्टीम कार खरीदी और एस्टीम कार खरीदे तो वे डॉक्टर साहब, जब इनके युवाराज बच्चे थे उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाते थे, उनकी नई कार चोरी हो गई, वे बड़े ताव में दूसरे दिन सुबह–सुबह गए कि आज हम जायेंगे मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि हमारी कार चोरी हो गई, तुरंत उपलब्ध करा दीजिये, जैसे ही वे मुख्यमंत्री आवास गए बगल में नई कार दिख गई और नई कार ही नहीं दिखी, डॉक्टर साहब सकपकाए, नाम खोल देंगे, इसीलिए ज्यादा छेड़ियेगा तो छोड़ेंगे नहीं । महोदय, कार वहीं दिख गई, डॉक्टर साहब हिम्मत कर गए मुख्यमंत्री के पास तो उन्होंने कहा कि....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, मुख्यमंत्री जी, हमारी कार यहां मिल गई है, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, कहा कि क्या कीजियेगा, बच्चा लोग से भूल हो गयी है, कुछ दे दीजिये मिठाई के लिए, कल गाड़ी, वह डॉक्टर साहब मिठाई के लिए भी पैसा दे दिए और दूसरा दिन भी गाड़ी नहीं पहुँची । गाड़ी तो गई, मिठाई भी चली गयी ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री कुंदन कुमार जी, अब आप बैठ जाइये । समय आपका समाप्त हो गया है ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, दीनकर जी की धरती से आता हूँ, दो लाईन बोलने दीजिये ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : ठीक है, बोल लीजिए एक लाईन ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, मैं सम्राट जी और नीतीश जी के लिए दो लाईन कहना चाहता हूँ, दीनकर जी की धरती से आता हूँ । वसुधा का नेता कौन हुआ ? भूखंड विजेता कौन हुआ ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ ? इन सबका जवाब है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया ।

महोदय, बेगूसराय की दो मांग है । मंगल जी के नेतृत्व में वहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो खुल ही रहा है और मुख्यमंत्री महोदय ने मेडिकल हॉस्पिटल देने का काम किया है ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, भारत सरकार ने तीन–तीन आयुर्वेदिक एम्स देने का काम किया है तो मैं मंगल जी से कहना चाहता हूँ कि...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइये । माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, आपका दस मिनट का समय है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा है उसके समर्थन में तथा विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में....

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, एक मिनट । श्री आलोक कुमार मेहता जी, बोलिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय सदस्य श्री कुंदन जी बोल रहे थे, उसके पहले कई साथियों ने बार–बार चरवाहा विद्यालय का नाम लिया । महोदय, सुन लिया जाय....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी ।

(व्यवधान)

आप इतना पढ़े–लिखे लोग हैं । क्या चरवाहा, चरवाहा करते हैं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, प्लीज सीट डाउन । आप बैठ जाइये, आलोक जी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में एवं विपक्ष के द्वारा लाये गए कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, आप स्वयं पढ़े–लिखे लोग हैं । क्या, चरवाहा–चरवाहा बार–बार चरवाहा–चरवहा कर रहे हैं । माननीय सदस्य, आप बैठिये । व्यर्थ का समय मत गुजारिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, जब बात चरवाहा विद्यालय की बात हो रही है तो मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य कह रहे चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा पूरे विश्व ने की तो पूरे विश्व में किस देश ने चरवाहा विद्यालय को फॉलो किया, किसने चलाया चरवाहा विद्यालय अगर प्रशंसा की तो चलाना चाहिए था । आज सबसे बड़ी बात है । महोदय, दौर चल रहा है, अंग्रेजी के कहावतों से

शुरू करना था तो मैं भी कहना चाहती हूँ थॉमस कार्लाइल की इंपोर्टेंट लाईन है...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, बार–बार मैं कह रहा हूँ कि आपलोग बैठे–बैठे मत बोलिये, परमिशन मिले तभी बोलिये । आप बैठै–बैठे बोलते हैं।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, He who has hope, He who has health has hope and he who has hope, has everything. माननीय महोदय, ये इनकी बैचेनी दिखा रही है । माननीय महोदय, इनकी बैचेनी दिखा रही है । थॉमस कार्लाइल ने कहा था, He who has hope, He who has health has hope and he who has hope has everything. हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वर्ष 2005 में सत्ता संभाली तो उनकी यही सोच थी, और यही स्पष्ट समझ थी कि बगैर हमारे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या कराए बिना हम विकसित और उन्नत बिहार की परिकल्पना करेंगे तो बेमानी होगी, तो उनकी सोच स्पष्ट थी, सोच बहुत अच्छी थी लेकिन रास्ते बहुत कठिन थे । हम जब बात करते हैं 2005 से पहले कि तो बहुत बुरा लगता है लेकिन उस समय की अगर हम याद करें पी0एच0सी0 और सुविधाओं की तो मन व्यथित हो जाता है । उस समय पी0एच0सी0 की बात तो छोड़ दीजिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पी0एम0सी0एच0 में न रूई थी, न सुई थी, न दवाई थी, न मरीज थे, मरीज के नाम पर कुत्तों और सुअरों का बसेरा हुआ करता था महोदय । हमारे जो महिला–पुरुष भाई मरीज थे, स्वास्थ्य सुविधाओं के वगैर दम तोड़ देते थे....

....क्रमशः....

टर्न–19 / अंजली / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : हमारी महिला बहनें जब प्रसव में होती थीं, प्रसव से पहले ही दम तोड़ देती थीं । हमारे जच्चा–बच्चा के जीवन पर बहुत बड़ा संकट था । इलाज के लिए लोगों को या तो बिहार के बाहर जाना पड़ता था और अपनी जमीन–जायदाद बेचनी पड़ती थी ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आप बार–बार बीच में टोका–टोकी मत करिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : हमारे नेता ने ऐसी जगह से यात्रा की शुरूआत की ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय सदस्या को इस तरह का भ्रम फैलाने....

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आलोक जी, नहीं–नहीं । बैठे–बैठे बोलना गलत है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : हमारे नेता ने ऐसी जगह से शुरूआत की जिसमें, यह हमारे नेता की इच्छाशक्ति थी कि उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को, आज माननीय मंत्री जी ने...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : बार–बार आप, प्लीज । जब आपकी बारी थी, आपको बोलने दिया न । नहीं, ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए । बैठिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : ये इनकी बेचैनी है महोदय, सत्ता में नहीं आने की बेचैनी है और कुछ नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइए सब लोग । अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइए । आप बैठिये । सुनने की आदत बनाइए सुनिए की । क्या फालतू बात में मसाला लगाना ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं की आज चर्चा चारों ओर हो रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के स्वास्थ्य की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है महोदय । ये लोग कहते हैं कि विकास में स्वास्थ्य के लिए ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आप बैठ जाइए । सुनने की आदत बनाइए । आपकी बात भी सुनते हैं लोग, तो आप भी सुनिए न । क्या फालतू बात । प्लीज बैठिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मैं 13 तारीख को सदन में बैठी थी, जब स्वास्थ्य विभाग के क्वेश्चन आ रहे थे, इनकी बेचैनी तो सुनिए, बेचैनी है सत्ता में नहीं आने की इसलिए लगातार बोले जा रहे हैं । महोदय, जब मैं 13 तारीख को बैठी थी, बिहार के स्वास्थ्य के क्वेश्चन आ रहे थे, तो विपक्ष की तरफ से भी क्वेश्चन आ रहा था, ये मांग कर रहे थे आई0सी0यू0 की, ये मांग कर रहे थे ए0एन0एम0 कॉलेज की, ये मांग कर रहे थे कैंसर के इलाज की, तो मैं कहती हूं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : सबसे पहले आप बैठिए । बिना परमिशन के आप नहीं बोल सकते हैं । बार–बार उठ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मैं कहना चाहती हूं कि अगर हमारी बेसिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं करायी गयी, तो कैंसर और आई0सी0यू0 पंचायतों में आप कैसे मांग कर

रहे हैं, आपके समय में तो बेसिक सुविधाएं ही नहीं मुहैया थीं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़संकल्प था, कहते हैं न–

''खुल जाएंगे सारे रास्ते,
रुकावटों से लड़ तो सही,
सब होगा हासिल,
तू जिद पर अड़ तो सही ।''

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य आलोक बाबू, ये क्या टोका–टोकी आप कर रहे हैं । इतने सीनियर लोग हैं । उनको बोलने तो दीजिए । बैठिये आप ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय मुख्यमंत्री जी जिद पर अड़े थे कि न सिर्फ जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लड़ना है उन्हें, बल्कि...

(व्यवधान)

सही बात तो उनको सुनना नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज बैठ जाइए । बैठिए आप ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : एक मिनट महोदय । सभापति महोदय...

(व्यवधान)

आलोक जी । आलोक जी ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आप बैठिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य आलोक मेहता जी बहुत संयमित रहने वाले नेता हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपकी माननीय सदस्या बोल रही थीं, तो पूरा सदन ने सुना, आपको भी सुनना पड़ेगा । जो भी इशूज हों, आप अपनी बात रखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी माननीय सदस्या जब बोल रही थीं तो पूरा सदन सुना । उन्होंने जो बोला वह सच्चाई है क्या ? नहीं है । लेकिन इसके बावजूद भी हमलोगों ने सुना । सरकार उसका जवाब देगी । सरकार अपनी बातों से आपको संतुष्ट भी करेगी, लेकिन इस तरह उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : नहीं । बेकार, व्यर्थ का समय बिताने से क्या फायदा । आप उनको बोलने दीजिए । बोलिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने न सिर्फ यह जिद की थी कि हम जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, बल्कि उन्होंने यह भी ठाना था ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : एक मिनट, बैठ जाइए । आप बोलिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैंने आपसे समय मांगा था सिर्फ एक बात के लिए कि सदन की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए । महोदय, कोई भी इस तरह का असत्य, क्या उस जमाने में अस्पतालों के बेड पर कुत्ते ही सोते थे...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : शालिनी मिश्रा जी, बोलिए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय सभापति महोदय...

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, क्या गरीब लोग जो अस्पताल में जाते थे...

(व्यवधान)

कुत्ता कह रहे हैं । बिहार के गरीब लोग जो अस्पताल में जाते थे, कुत्ता कह रहे हैं । आज किसी एक बेड पर कुत्ता सोया हुआ है तो इस तरह की भाषा बोलकर, भ्रामक बात बोलकर बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आलोक बाबू, अब आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : जब तक वर्ल्ड बैंक का दरवाजा नहीं खुला था...

(व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आपको समय दिया, अब आप बैठिये । नो–नो बैठ जाइए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय सभापति महोदय, यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को न सिर्फ आज विकास पुरुष कहा जाता है, बल्कि नए बिहार का विश्वकर्मा भी कहा जाता है । महोदय, जितनी जर्जर स्थिति थी, उससे उसको बहाल किया, अच्छी स्थिति लेकर आए और यह जिद किया कि हमारे नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो । महोदय, वर्ष 2005 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे और कितने अब हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है, तो मैं उसको कहना नहीं चाहती हूं । पी0एम0सी0एच0 जिस दुर्दशा का दंश झेल रहा था आज वही पी0एम0सी0एच0 2028 से 2029 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा । आई0जी0आई0एम0एस0, एम्स, एल0एन0जे0पी0 जैसे हॉस्पिटल में आई0सी0यू0 बनाना, ज्यादा बेड करना यह सब हमारी सरकार ने किया है । आज हमारे दूरदर्शी नेता की सोच है जिसकी वजह से पी0एम0सी0एच0 ही नहीं, सदर अस्पताल नहीं, सभी अस्पतालों में आमूलचूल

परिवर्तन हुआ है, जहां मरीजों की लाइन लगी रहती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जिस जमाने में आपने सत्ता हमें दी थीं, तब सिर्फ 39 मरीज हर महीने आते थे, वह बढ़कर 12 हजार हो गई है, यह है विकास, यह है हमारी सरकार का काम । महोदय, अब प्रत्येक जिले में आई0सी0यू0 और डायलिसिस उपलब्ध है यह है विकास, यह है हमारे स्वास्थ्य विभाग का काम, यह है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का काम ।

महोदय, मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी ज्यादा भारी संख्या थी, वह घटकर अब बहुत कम हो गई है और मैं सदन में गर्व के साथ कहती हूं कि यह देश के राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गई है बिहार में । इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को और आशाकर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं । इमरजेंसी में मरीजों को खाट पर जाना पड़ता था, अब इमरजेंसी से लेकर हम एंबुलेंस तक आ गए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो रही है, लोग अपनी तरफ से जाते हैं और जीवन दान पाकर अस्पताल से आते हैं ।

महोदय, किसी असाध्य बीमारी के लिए सदस्यों ने कहा है फिर भी मैं बताना चाहती हूं कि हमने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिकित्सा सुविधा से हजारों लोगों की जान बचाई है, हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं पूरे बिहारवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, हर हफ्ते बोर्ड बैठता है और हर हफ्ते उस पर काम होता है और हर हफ्ते लोगों के खाते में, अस्पताल के खाते में पैसे जाते हैं । महोदय, मैं कहना चाहती हूं सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है, चिकित्सक, स्पेशलिस्ट, पारामेडिकल स्टाफ के बिना अस्पतालों में काम नहीं हो सकता, तो बिहार सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं और हजारों लोग आए हैं विशेषज्ञ और डॉक्टर ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाइए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : एक मिनट महोदय । महोदय, एक दिन हमारे एक सदस्य कह रहे थे, बात नौकरी की आई तो उन्होंने कहा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष नौकरी मैन ऑफ बिहार हैं, उन्होंने उपाधि दी है, मैं तो कहना चाहती हूं कि उनको लैंड फॉर नौकरी मैन ऑफ द बिहार, चारा मैन ऑफ द बिहार, अलकतरा मैन ऑफ द बिहार कहना चाहिए । महोदय, इसकी उपाधि देनी चाहिए ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, बस एक सेकंड दिया जाए ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज, अब आप बैठ जाइए । अब हो गया, बैठ जाइए ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : सभापति महोदय,

''सुनाने की आदत है तो सुनेंगे कैसे,
बिना हुज्जत के बुझेंगे कैसे ।''

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह ।

टर्न–20 / पुलकित / 16.02.2026

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय । आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे मौका मिला और मैं औरंगाबाद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं पहली बार चुनकर यहां आया हूं और इस पवित्र मंदिर का एक हिस्सा बना हूं उसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद अपनी जनता को, अपनी सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया । आज का जो बजट है, इसके ऊपर लंबी चर्चा भी चली । महोदय, इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा चली। मैं इस विषय के पक्ष में और अपने कुछ साथी, अपने कुछ माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव का भी प्रावधान रखा है । मैं उनसे भी आग्रह करने के लिए, विनतीपूर्वक आग्रह करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें । वह इसलिए, महोदय, क्योंकि यह बजट बहुत लंबी दूरी तय करके आया है । जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार इस मंदिर का हिस्सा बनने का मुझे एक मौका मिला है । अपने वरीय साथियों को, अपने वरीय सदस्यों को भी मुझे लगातार सुनने का मौका मिला और जब पीछे के अपने वाद विवाद और अपने विषयों पर जब चर्चा चल रही थी, तो उसमें कुछ सदस्यों से सुनने को मौका मिला कि जब विधायक जी पहले क्षेत्र में जाते थे, तो बिजली उनके साथ जाती थी और बिजली उनके साथ वापस चली आया करती थी । कुछ अपने साथियों के साथ यह भी चर्चा में यह भी सुनने को मौका मिला कि सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क हुआ करती थी । महोदय, वहां से आज हम इतनी लंबी दूरी तय करके और साथ में...

(व्यवधान)

अब मैं पूरी बात बता दूंगा । आप सीनियर सदस्य हैं हमारे, तो आपसे सीखने का मौका भी जरूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ में कुछ विषय को भी आपके बीच में रखूंगा । जब लोग कटौती प्रस्ताव की भी चर्चा कर रहे थे, तो अपने क्षेत्र में और मैं अपने विषय को भी जरूर रखूंगा, जो मैंने मांग कुछ दिन पहले उठाई थी, इसलिए कहीं भी इसके बीच में कुछ अंतरद्वंद ना हो, इसलिए मैं अपनी मांग को भी पहले रख देता हूं जो मैंने पहले उठायी थी। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने औरंगाबाद के देव के

पातालगंगा में एक मेडिकल कॉलेज का की घोषणा की थी । मैंने उसकी मांग उठाई थी कि उसका जल्दी से जल्दी काम शुरू करके उसकी शुरुआत की जाए और उसको कार्यान्वित कराया जाए । उसके साथ में अति विशिष्ट सेवा शुरू करने की मांग की थी और माननीय मंत्री जी और बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह पूरा आश्वासन मिला कि यह काम हो रहा है । महोदय, जब मैं कहता हूं कि यह इतना लंबा फासला तय करके जब बजट आया है । महोदय, एक तरफ तो हम बात करते थे कि बिजली नहीं थी, रोड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे और आज जब कटौती प्रस्ताव के बारे में हमारे माननीय सदस्य कुछ बोल भी रहे थे, तो उनकी मांग थी कि महोदय, दो एंबुलेंस से उसको चार कर दिया जाए, हमारे जो पी0एच0सी0 है, उसको अपग्रेड कर दिया जाए, हमारे जिला में जो छोटा अस्पताल है, उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए । महोदय, चाहिए सब कुछ, और फिर भी कटौती करना है, यह दोनों कैसे संभव हैं ? इसलिए मैं आग्रह करता हूं और मैं अंतरात्मा पर हाथ रख कर मैं चाहता हूं अपने उन सदस्यों से, जिन्होंने इस बात को कहा भी है कि कटौती प्रस्ताव के फेवर में उन्होंने बोला है, मैं एक बार उनसे आग्रह भी करता हूं । ये मेडिकल का जो पूरा इको सिस्टम है, ये सिर्फ पेसेंट और डॉक्टर तक नहीं है । महोदय, यह पूरा का पूरा इको सिस्टम है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा अपने विभागीय मंत्री जी को कि आज कम से कम स्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा रोजगार देने वाले विभागों में से एक आज यहां बनकर के अपने बिहार के नागरिकों को रोजगार देने का भी काम कर रहा है । मैं 2005 और 2004 के पहले की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक तरफ ध्यानाकर्षण जरूर करना चाहूंगा, और इसीलिए मैंने आग्रह किया है कि अपनी अंतरात्मा पर एक बार हाथ रखकर जरूर जब कटौती प्रस्ताव की बात करें, तो एक बार जरूर उन आंकड़ों को भी जरूर देख लेना चाहिए । महोदय, जब मैं इको सिस्टम हेल्थ की बात करता हूं, तो इस इको सिस्टम में हमको सिर्फ डॉक्टर नहीं, हमको पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, हमको फार्मासिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, और आज तो हमारी जीविका दीदियां भी अस्पताल में हमारे एक पौष्टिक आहार पर काम कर रही है । महोदय, उस तरह से रोजगार का सृजन भी हुआ है, लेकिन जब मैं अंतरात्मा की बात कर रहा था, तो मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि 2000 और यह प्योर आंकड़ों की बात होगी, महोदय, इसमें कहीं कोई यह अंतरद्वंद नहीं हो सकता ।

महोदय, 2005 से पहले की जो सरकार थी, एक भी मेडिकल कॉलेज, उनके कालखंड में, मैं 15 साल की सिर्फ बात करूंगा, एक भी मेडिकल कॉलेज खुला नहीं । महोदय, जब हम आगे बढ़कर इसको देखते हैं कि क्यों आज लोग कह रहे हैं कि यहां भी डॉक्टर होना चाहिए, वहां भी

डॉक्टर होना चाहिए और मेरे औरंगाबाद के जब देव में अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां भी डॉक्टर होना चाहिए। महोदय, लेकिन परेशानी क्या है कि एक डॉक्टर को बनाने के लिए 5 साल एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई लगती है और 3 साल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लगते हैं । बिना पोस्ट ग्रेजुएट के वह टीचर नहीं बन सकते और 3 साल आगे पढ़ेंगे तो सुपर स्पेशलिटी पढ़कर जिसके न्यूरो सर्जन और कार्डियोथोरासिक सर्जन की मांग भी हमारे किसी सहयोगी, किसी सदस्य ने मांगी है, तो उसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती । महोदय, जब मेडिकल कॉलेज 15 साल खुला ही नहीं, तो कम से कम एक चीज तो तय हो गयी कि नया ह्यूमन रिसोर्स और एक मेडिकल पूरे इको सिस्टम को खड़ा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनपावर और करिकूलम तीनों की जरूरत पड़ती है । आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, आज हमारे करिकूलम खड़े हैं, लेकिन उसके साथ में मैनपावर की जो थोड़ा बहुत अभाव है, उसका श्रेय हम सबको लेना चाहिए । महोदय, मैं अंतरात्मा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज तो हम सवाल और जवाब करके एक–दूसरे के साथ बच जाएंगे, लेकिन आज अगर इस कटौती प्रस्ताव को हमने वापस नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियां भी हमसे सवाल जरूर पूछेंगी । 15 साल, 15 साल हम सभी ने कभी भी एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक फार्मेसी कॉलेज और एक पैरा मेडिकल कॉलेज को आगे खोलने की कोई जहमत हमने नहीं उठाई। यह अपने आप में हमारे लिए चिंता का विषय है । 5 साल हमारे एक एम0बी0बी0एस0 को तैयार होने में, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट को और तीन साल उस समय रेजीडेंसी स्कीम चलती थी, उसके बाद वह असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर, टीचर बनते थे । महोदय, ये टीचर जब बनते थे, उसके बाद 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 साल एसोसिएट प्रोफेसर और तब प्रोफेसर बनकर आगे बढ़ते थे जो एक मेडिकल कॉलेज में दो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, अब तो महोदय तीन हो गये हैं उसके ऊपर, मैं केंद्र सरकार का अभिनंदन करना चाहूंगा कि अब तीन पोस्ट ग्रेजुएट एक प्रोफेसर के माध्यम से मिल जाता है । जब यह इको सिस्टम ही नहीं खड़ा हुआ, जब हमारा ये पांच, तीन, आठ और पीछे का, आठ साल था, ये 16 साल जब हमारा बिहार से पीछे चला गया और उसके बाद हम यहां खड़े होकर कहते हैं कि– This policy and this state, this government does not has a comprehensive health policy महोदय, यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है । मैं एक बार आग्रह करूंगा कि जिसको भी इस सरकार की नीति और नियत पर शक हो, कम से कम अपने स्वास्थ्य विभाग की जब हम लोग बात करते हैं, यहां पर तो एक बार पिछले 3 साल के बजट का प्रावधान जरूर पढ़ लेना चाहिए, वहां पर । किस तरह से उस 2005 के कालखंड के बाद दवाइयों की चर्चा चल रही थी । पहली बार इस बिहार में 2006 के बाद 41 दवाओं के साथ शुरू हुई, जहां पर फ्री दवाइयों

का वितरण शुरू किया गया, और आज 611 और कैंसर और स्टंट, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कोई अपने साथी कह रहे थे, यहां पर कि कोई बड़े हार्ट अटैक या न्यूरो के किसी बीमारी से कोई ग्रसित होता है तो चिंता में पड़ जाता है कैसे जाएं । महोदय, पहले यह सवाल आता था कि कहां जाएं ? पहले किसी अस्पताल में जाएं कि किसी आसपास के जमींदार और साहूकार के पास जाकर के पहले घर और जमीन गिरवी रख के जाएं वहां पर, ताकि हमारे बच्चों का इलाज या जो हमारे यहां किसी रोग से पीड़ित हो ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आप बैठ जाए ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : एक मिनट दिया जाए । महोदय मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा इसमें आपके आशीर्वाद रहा तो । महोदय, अगर वहां होता तो आज महोदय किसी को सोचना नहीं पड़ता है कि उसके पास अधिकार है आयुष्मान का महोदय...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री विमल राजवंशी । आपका समय चार मिनट है ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : आयुष्मान कार्ड के साथ कहीं भी जा सकते हैं । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री विमल राजवंशी : माननीय सभापति महोदय, आज हम स्वास्थ्य विभाग के अनुमोदनों पर चर्चा कर रहे हैं, 2026–27 के बजट पर । बिहार के करोड़ों नागरिक की जीवन सुरक्षा और सम्मान का समाधान है । इस बिहार के पवित्र मंदिर में जितने भी बैठे हुए सदस्यगण हैं, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और हमारे नेता चिराग पासवान जी को भी प्रणाम करता हूं और अपनी जनता को भी नमस्कार करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एन0डी0ए0 सरकार की नेतृत्वकारी भूमिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निभाई है वह विपक्ष की समझ से परे है । क्योंकि इनके जमाने में अस्पताल में जब मरीज आते थे खाट पर, आज तो हमारी गौ माता को भी देखने के लिए हमारी सरकार ने एंबुलेंस दिया है ।

आज राज्य सरकार ने विभिन्न मोड में मातृत्व मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है । एस0आर0एस0, 2023 के अनुसार मातृत्व मृत्यु अनुपात घटकर 104 पर आ गयी है । शिशु मृत्यु दर 23 प्रतिशत, नवजात मृत्यु दर 18 प्रतिशत तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 27 प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है । यह केवल आंकड़ें नहीं बल्कि हजारों माताओं और बच्चों की सुरक्षित मुस्कान है ।

सात निश्चय के अंतर्गत सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षा जीवन, संकल्प के तहत प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा रहा है । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उच्च स्तरीय अस्पताल के रूप में विकास किया

जा रहा है । पी0एम0सी0एच0 को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है । दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 2546 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माण हो रहा है । कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं । कैंसर उपचार आयुष पद्धति के कॉलेज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण, यह सब इस बात का प्रमाण है कि सरकार केवल घोषणा नहीं परिणाम दे रही है ।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मिला है । बाल हृदय योजनाओं के अंतर्गत हजारों बच्चों का सफल ऑपरेशन हुआ है । दवा आपूर्ति के क्षेत्र में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है ।

किंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा दायित्व केवल उपलब्धि और बखान करना नहीं है बल्कि व्यवस्था को और भी मजबूत बनाना है । इसलिए मैं सरकार से कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटनाएं आज भी चुनौती है । जिसके लिए सरकार के समक्ष कुछ सुझाव देना है । एन0एच0 और एस0एच0 पर ट्रॉमा सेंटर खोला जाए, ब्लैक स्पॉट की पहचान की जाए, 15 मिनट के भीतर एंबुलेंस प्रतिक्रिया की समय–सीमा उपलब्ध हो । हर अनुमंडल अस्पताल में 24×7 ट्रामा केयर यूनिट की व्यवस्था हो, जिसमें सिटी स्कैन और ब्लड बैंक की सुविधा होनी चाहिए ।

मैं विशेष रूप से नवादा जिला के रजौली स्थित 75 शैय्या अनुमंडलीय अस्पताल का मुद्दा उठाना चाहता हूं जो एन0एच0–20 पर स्थित है। यह अस्पताल दुर्घटना पीड़ितों के लिए जीवन रेखा है परंतु चिकित्सकों और कर्मियों की कमी से उपाधीक्षक का पद रिक्त है तथा ट्रॉमा सेंटर एवं पीकू का संचालन न होने से मरीजों को रेफर करना पड़ता है । इस स्थिति स्थिति को सुधारने के लिए सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो । साथ ही जब गरीब और गंभीर मरीज..

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विमल राजवंशी : महोदय, एक मिनट दिया जाए । पटना के अभाव में भटकते हैं तब जनप्रतिनिधियों को ....

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री विमल राजवंशी : महसूस करते हैं, इसलिए अति आपातकालीन और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को पारदर्शिता की प्रक्रिया...

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : प्लीज अब बैठ जाइए ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : श्री ललित नारायण मंडल।

श्री ललित नारायण मंडल : आदरणीय सभापति महोदय, हमको बोलने का मौका आपने दिया इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम अपने माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, गृह मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का और अपने मुख्य सचेतक श्रवण बाबू का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, पहले की जो स्थिति थी, हमारे बहुत सारे साथियों ने आपको बताया है। आज हम जब हॉस्पिटल जाते हैं देखने के लिए, तो वहां पर डॉक्टर बैठे रहते हैं। डॉक्टर के पास कलम होती है, डॉक्टर के पास पेपर होता है और हॉस्पिटल में दवा मिलती है। डॉक्टर मरीज को देख कर दवा लिखते हैं और ज्यादातर दवाएं फ्री में हॉस्पिटल में ही मिल जाती हैं। यह इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में संभव हुआ। पहले तो हम लोग देखते थे कि हॉस्पिटल में पुर्जा लिखने के लिए कागज तक नहीं मिलता था, यह स्थिति थी वहां पर और बेड पर कौन सोता था, यह सुनकर हमारे विरोधी दल के साथियों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उस बात को नहीं कहना चाहते हैं। आज तो बेड भरा पड़ा रहता है और हर हॉस्पिटल में, हमारी सुल्तानगंज की बात करते हैं सर, सुल्तानगंज का चाहे रेफरल हॉस्पिटल हो, चाहे शाहकुंड का हॉस्पिटल हो, चाहे मायागंज का हॉस्पिटल हो, मरीजों से भरा पड़ा रहता है। अगर उनको कोई जरूरत होती है, तो मोबाइल से हम डॉक्टर से बात करते हैं और पेशेंट को उचित सहायता मिलती है और सुविधा मिलती है। साथियों, ये हमारी एनडीए की सरकार है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की व्यवस्था है जिसके लिए हम उनको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पी0एम0सी0एच0 को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 5462 बेड के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। सर, इसके लिए हम उनको बहुत–बहुत बधाई देते हैं कि बिहार के विकास के लिए और बिहारियों के इलाज के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने और नीतीश कुमार ने मिल कर समाज का बहुत बड़ा इलाज किया। कैंसर अस्पताल गंगवारा में, दरभंगा में खोलने की बात हो रही है जिसमें सिर, मुंह, और गर्दन के कैंसर का इलाज होगा। यह बहुत बड़ी बात है। लोक निजी भागीदारी पी0पी0पी0 के तहत शंकर आई हॉस्पिटल फाउंडेशन इंडिया, कोयंबटूर के द्वारा अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल, कंकड़बाग, पटना में भी उसकी आधारशिला रखी गई है, जिससे कि हम बिहारियों को बहुत फायदा होगा। उसमें यह भी बात आ रही है कि राज्य के गरीबों का इलाज, नेत्र रोगियों का इलाज वहां पर फ्री होगा, यह साधारण बात नहीं है। आशा कार्यकर्ता एवं आशा फेसिलिटेटर का मासिक बढ़ाकर 3000 रूपये कर दिया गया है तथा ममता कार्यकर्ताओं का भी वेतन प्रतिमाह 600 रूपये कर दिया गया है। पहले वह लोग बहुत चंद रुपयों में ही काम करते थे। आज वह लोग

आसानी से काम करते हैं और दूर–दराज के गांव से पेशेंट को लाकर हॉस्पिटल में रखते हैं और उनका इलाज होता है। जनता बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसूता को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रूपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रूपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होता है। कहीं पर कोई बेईमानी नहीं है, कहीं पर कोई घूसखोरी नहीं है। इलाज होता है और पेशेंट को हॉस्पिटल में हम लोग देखने जाते हैं। पूछते हैं कि आप लोगों को कोई असुविधा है? तो पेशेंट कहता है, सर, हमको कोई असुविधा नहीं है। जो भोजन मिलना चाहिए, चार्ट बना हुआ है, उसके अनुसार हमको भोजन मिलता है। जो दवाई चाहिए, वह दवाई मिलती है। और क्या चाहिए जनता को ? हम इसके लिए बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गरीब मरीजों को इलाज के लिए 2025 में लगभग 202 करोड़ रूपये खर्च के रूप में सरकार ने वहन किया। गरीब जनता अपनी, जो गंभीर बीमारी है, उसके इलाज में खर्च नहीं कर पाती थी, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, दीदी के रसोई द्वारा संचालित कैंटीन में जो प्रति थाली 20 रूपये की दर से भोजन मुहैया होता है, उसमें पेशेंट और उनको देखने वाले आते हैं, उनको मिलता है। यह भी बहुत बड़ी बात है।

जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में 4 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 70 वर्ष से अधिक आयु के 30 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान तथा वंदना कार्ड बनाया गया है, जो उनके फ्री इलाज की बात करेगा। सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह जनता के बहुत फायदे की बात है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जनता बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बहुत खुश है और इस खुशी का इजहार आपने देखा। सर, आप तो चुनाव में भी हमारे क्षेत्र में थे, हमारे भाई सम्राट चौधरी जी भी हमारे क्षेत्र में थे, हमारे श्रवण बाबू भी थे, वहां पर जनता ने खुले दिल से एनडीए को मदद की और 202 के पार करके अब फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान है। जनता को अब यह नहीं लगता है कि हम कैसे इलाज करायेंगे। हम कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से कि सर, हमारे सुल्तानगंज बाजार में एक महिला अस्पताल है। सर, दो ही महिला अस्पताल हैं पूरे बिहार में। एक सुल्तानगंज में भी है। जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां के लोग कहते हैं कि सुल्तानगंज के महिला अस्पताल को फिर से पूरी क्षमता के साथ चालू कराइए। हम अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कहना चाहते

हैं कि जनता की आवाज हमने आप तक पहुंचायी, अब आप जो कीजिए, जनता के साथ न्याय कीजिएगा। भागलपुर जिले के रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में आई, हार्ट, कैंसर इत्यादि के डॉक्टर नहीं हैं। अगर संभव हो सर, वहां पर आई के, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को प्रतिनियुक्त किया जाए।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सर, उसके बाद शाह कुंड में जो हॉस्पिटल है, उसको रेफरल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। वहां भी यह बात आती है। सजौर में स्वास्थ्य उप केंद्र का भवन एकदम जर्जर है। भवन है ही नहीं, सर। अगर उसका भवन बनवा दिया जाए, तो वहां की जनता भी आपको, हमको, बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, हम सभी साथियों को बहुत आशीर्वाद देगी, सर। इसलिए सजौर के हॉस्पिटल पर भी ध्यान दिया जाए।

महोदय, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में हम मायागंज की बात करते हैं, पी0एम0सी0एच0 की बात करते हैं, आई0जी0आई0एम0एस0 की बात करते हैं। जब इलाज फ्री हो रहा है, तो वहां पर पेशेंट आता है। किसी को एक्स–रे कराना है, किसी को ब्लड टेस्ट कराना है, किसी को कुछ कराना है, वहां पर लंबी लाइन लग जाती है। लंबी लाइन का कारण है कि जो ऑपरेटर्स हैं, उनका अभाव है, मतलब ऑपरेटर्स कम है। पहले मान लिया जाए, रोज वहां 500 पेशेंट आते थे। उनके इलाज के लिए पर्याप्त ऑपरेटर्स थे, लेकिन अब 1000 पेशेंट रोज आते हैं। उसके लिए ऑपरेटर्स की संख्या अगर बढ़ा दी जाए और दक्ष कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो जनता जो ऊब कर बाहर जाकर टेस्ट करा लेती है, वह टेस्ट नहीं करवाएगी, सर।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री ललित नारायण मंडल : इसलिए हम चाहते हैं कि वैसे हॉस्पिटल में, जहां पर पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर आप ऑपरेटर्स और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की कृपा करें, सर।

अध्यक्ष : श्री मुरारी पासवान।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, एक सेकेंड। सर, आई0जी0आई0एम0एस0 में, मायागंज में, पी0एम0सी0एच0 में हम मोबाइल से वहां के अपने डॉक्टर से बात करके इलाज करा लेते हैं। एक निवेदन है, सर, हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि एम्स में हम फेल हो जाते हैं। सर, एम्स में जब हम अपने पेशेंट के लिए पैरवी करते हैं कि इसका इलाज करा दीजिए, इसको इंडोर करा दीजिए, तो वहां पर हमारी नहीं चलती है। हम निवेदन करते हैं, हमको लगता है कि यह दर्द हम सभी विधायकों का होगा। सर, एम्स में हमारी बात सुनी

जाए। सर, हम अपनी बात नहीं करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, अगर सुनी जाए, तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, सर।

अध्यक्ष : श्री मुरारी पासवान। आपका समय पांच मिनट है।

टर्न–22 / संगीता / 16.02.2026

श्री मुरारी पासवान : धन्यवाद सर । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सभी अपने विपक्ष के साथियों से सुन रहे थे किसी ने कहा कि हम कुत्ता बेड पर सोते हुए नहीं देखे तो सबसे पहले हम अपने युवा सम्राट, हृदय सम्राट, अपने उपमुख्यमंत्री सम्राट जी का मैं अभिनन्दन करता हूं । साथ ही, अपनी मधुर वाणी से सभी सदस्यों का और निष्पादन करने वाले, उत्तर देने वाले अपने विजय बाबू को भी, साथ ही, इस स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं । धन्यवाद के पात्र आप विपक्ष भी हैं, चूंकि वर्षों से देख रहे हैं कि जनता ने 1990 से लेकर 2005 तक मौका दिया, लेकिन लक्ष्य नहीं रहने के कारण लक्ष्यविहीन होकर भटकते रहे, लक्ष्य दिखाई देना चाहिए । एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कहते हैं, भगवान भी मौका तीन बार देता है। भगवान ने मौका भी तीन बार दिया अपनी करिश्मा बहन कही थी कि हमको और नेतृत्व ने मौका दिया, मौका तो दिया, राबड़ी जी को भी मौका मिला, तेजस्वी जी को भी मौका मिला, तेजप्रताप जी को भी मौका मिला, साधु यादव जी को मौका मिला, लेकिन रहा क्या ? कर क्या सके, बिहार को आगे बढ़ा पाये क्या, बिहार को सींच सके क्या ? कारण यही था कि लक्ष्य नहीं था । अपने देहात में कहा जाता है, सुनते हैं कि खाली मन शैतान का, जब मन में कुछ लक्ष्य नहीं हो, मन में कुछ करने की क्षमता नहीं हो, मन में कुछ विकास करने की आदत न हो, तो हम करेंगे क्या ? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के आधार की कुर्सी पर जिस तरह से बैठे रहे, वही दिखाई देते रहा । भूरा बाल समाप्त करो, यही ईर्ष्या रहा, द्वेष रहा...

(व्यवधान)

कहेंगे सुनिए, धैर्य से सुनिए । सुनिए धैर्य से । भूरा बाल समाप्त करो ।

(व्यवधान)

आप माई समीकरण के आधार पर चलने वाले थे। कोई समीकरण नहीं था, एक ही समीकरण था, माई का समीकरण, आप उसी संस्कृति के हिसाब से चल रहे थे और जिस संस्कृति से चले, उस संस्कृति को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करिए ।

श्री मुरारी पासवान : अब इस सभ्य समाज में छोड़ना चाहिए। अब वह समाज नहीं रहा, विकास का दरिया बह रहा है। अपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में

हम सभी बिहार के एक अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं। पहले हम सभी को कहा जाता था पूरे देश में बिहार छोड़कर कि बिहार, बिहारी शब्द सुनकर ही घृणा करते थे लोग और दूर खड़े रखते थे, लाइन में खड़े रखते थे, लेकिन आज का कैसा बिहार है, आज जब जाते हैं, तो क्या अनुभव होता है, इस अनुभव को भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए हम सभी किस तरह से हैं।

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिए अब ।

श्री मुरारी पासवान : लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए शून्य से ऊपर आना चाहिए था । नीतीश कुमार जी के हाथों में जब सरकार मिली, तो शून्य में मिली ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री मुरारी पासवान : आप स्वास्थ्य पर सुन रहे हैं, सुनिए, भइया सुनिए । तीन बार मौका मिला, तीन बार में एक–एक अगर स्वास्थ्य विद्यालय बनवाए होते, मेडिकल कॉलेज बनवाए होते, तो कम से कम तीन बनता...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री मुरारी पासवान : लेकिन 6 के 6 ही रहे, 1990 से 2005 तक 6 के 6 ही रहे, आगे नहीं बढ़े।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । संक्षेप कर लीजिए ।

श्री मुरारी पासवान : जी । हम चर्चा इसलिए...

(व्यवधान)

अब तो सुना जाए, अब तो हमारे बिहार का विकास हो रहा है । कंधे से कंधा मिलाकर काम करें । जिस तरह से कहा जाता है कि हम अगर भक्ति भाव करते हैं, तो हमें कुछ न कुछ मिलता है, ध्यान से ज्ञान मिलता है और हम आए हैं यहां ध्यान के साथ ज्ञान करने, अर्जन करने के लिए और एक लक्ष्य बनाकर चलने का निर्णय है, जिस तरह से अपने नीतीश कुमार जी लक्ष्य बनाए हैं...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री मुरारी पासवान : राज्य की जनता को मौलिक एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सहित स्वास्थ्य सुविधाएं एवं संचालित योजनाओं की समय–समय पर समीक्षा...

अध्यक्ष : श्री मुरारी पासवान जी, अब समाप्त करें ।

श्री मुरारी पासवान : कुशल दिशानिर्देश के परिणामस्वरूप राज्य में गत वर्षों में स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं ।

श्री मुरारी पासवान : हम सुधार के साथ ही आगे बढ़ते हैं । साथ ही, हम एक बात और कहना चाहते हैं अपने क्षेत्र के विषय में, हमारे बड़े भाई ने, चूंकि जो रेफरल अस्पताल है हमारे पीरपैंती में, वह बचपन के खेल का केंद्र रहा था हमारा,

चूंकि डॉक्टर का भी अभाव था और पेशेंट तो जाते ही नहीं थे। पेशेंट क्यों जाते ? क्योंकि दवाई ही नहीं थी, तो कुत्तों के झुंड निकलते हमने देखा है...

अध्यक्ष : अब आपका समाप्त हुआ, आपने अपनी बातों को रख दिया ।

श्री मुरारी पासवान : और पीरपैंती 30 शैय्या बेड है और आगे बढ़ाकर सौ शैय्या बनाया जाए यही अनुरोध है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

बोलिए, कोई बात है ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब समाप्ति का समय है और माननीय मंत्री जी को अपना वक्तव्य देना है । मैं सिर्फ दो निवेदन, मेरी पार्टी के लोग बोल नहीं सके इस मामले को । एक ये है कि आयुष्मान एक बड़ा प्रोग्राम है, गरीबों का बड़ा भला हो रहा है, लेकिन जांच में जो पैसे लगते हैं 10, 20, 30 हजार गरीब नहीं दे पा रहा है सर, उसका प्रावधान कराने के लिए सरकार से सिफारिश करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । आपकी बात आ गई ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : जी सर । सर, एक मामला है कि शाम को पोस्टमॉर्टम पहले अंग्रेज के समय में 5 बजे के बाद नहीं होता था, सरकार को भी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए । सरकार खड़ी हो गई है । माननीय मंत्री खड़े हो गए हैं । माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री मंगल पांडे, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हो रहे प्रस्ताव की चर्चा पर भाग लेने वाले सभी पक्ष–विपक्ष के 23 सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार सदन के पटल पर रखे हैं । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कि इस सदन में मुझे स्वास्थ्य विभाग के 8वीं बार बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । महोदय, यह विभाग एक ऐसा विभाग है जो गरीबों के कल्याण से जुड़ा रहता है और हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के नेता दीन दयाल उपाध्याय जी ने हमलोगों को अंत्योदय का मंत्र दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने जो विभाग मुझे सेवा करने के लिए दिया उसमें अंत्योदय, जो हमारे मूलमंत्र में है, उस भाव से

मैं बेहतर तरीके से सेवा कर पाया हूं अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यह कहना चाहता हूं ।

महोदय, मैं अपने विभाग के संदर्भ में अपनी बातों को रखूंगा और अगले वित्तीय वर्ष के संदर्भ में, जो बजट के प्रस्ताव आए हैं वह भी मैं बात कहूंगा, लेकिन माननीय सदस्यों ने, जो कुछ विषय सदन के अंदर लाए हैं उस विषय पर थोड़ी चर्चा जरूर कहना चाहता हूं । एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि इस सदन में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है वह एक प्रतिशत है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बिहार का बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये का है और स्वास्थ्य विभाग का बजट 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, तो जरूर कोई भी बयान इस सदन में देने के पहले, यह बहुत जिम्मेवारी से बैठकर बोलने वाली जगह है और यह जगह ऐसी नहीं है कि कोई राजनीतिक मंच लगा है और बाजार में हम कहीं भाषण दे रहे हैं । इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आपको सुझाव देना हो, कोई कमी हो जरूर बताइए, लेकिन सत्य पर आधारित होना चाहिए, मिथ्या पर आधारित बयान सदन में शोभा नहीं देता है ।

(क्रमशः)

टर्न–23 / यानपति / 16.02.2026

(क्रमशः)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 21 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट का यदि प्रस्ताव है तो यह 6 प्रतिशत से अधिक है और देश के कुछ प्रमुख राज्यों में ही इतने बजट का प्रावधान किया जाता है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने द्वय उपमुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए इतने बजट का प्रावधान किया है । वित्त मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी राशि मुझे काम करने के लिए दी है । महोदय, मेदांता हॉस्पिटल की चर्चा की गयी महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा, हॉस्पिटल बन गया गरीबों का कोई इलाज नहीं होता, इस राज्य में देखनेवाला कोई नहीं है, महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 का शासन गरीबों का शासन है और गरीबों की सेवा के संकल्प के साथ काम करनेवाला शासन है । महोदय, मैं माननीय सदस्य को आंकड़ा पढ़ना चाहता हूं । मैंने कहा कि मिथ्या पर आधारित बात यहां नहीं होनी चाहिए । जानकारी लेकर आप बात रखिए । मैंने सभी सदस्यों की बातों को लिखा है, जो काम मुझे करना है वह भी मैंने लिखा है । मैं कहना चाहता हूं कि अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2026 तक कुल 9072 मरीजों के इलाज हुए हैं । इसमें कार्डियक

साइंस के 1377, ओंको साइंस के 7105, न्यूरो साइंस के 249, रीनल साइंस के 259, हेमोटोलॉजी के 53 और ट्रांस्प्लांट रिनुअल बोनमेरो 29 । तो माननीय सदस्य यह सब जानकारी रखकर, जो भी सदन में अपनी बातों को रखते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा तथ्यात्मक बात होती ।

(व्यवधान)

यह फ्री में ही होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जानकारी लेकर पढ़ लिखकर, सदन में आने के पहले पढ़ लिखकर आना ज्यादा अच्छा होता है । मैं बार–बार कह रहा हूं, यह बहस की जगह नहीं है और न ही यह पब्लिक का मंच है । हम सब लोग राजनीति करते हैं और जब जनसभा में जाते हैं तो अपनी बात और अपने दल की बात करते हैं । लेकिन जब सदन में जनता निर्वाचित करके भेजती है तो यहां तथ्यों पर आधारित सत्य बात ही करनी चाहिए और जानकारी लेकर करनी चाहिए । महोदय, मैं एक जरूर थोड़ा शेयर भी पढ़ना चाहूंगा कि जो बातें मैंने कहीं चूंकि

''यह जो तुम्हारी शक करने की आदत है इसे छोड़ना पड़ेगा
मुझ पर ऐतबार का तार जोड़ना पड़ेगा
रिश्ता विश्वास पर चलता है, अहम का परदा खोलना पड़ेगा ।''

यह मैं कहना चाहता हूं महोदय । एक और विषय आया महोदय, मेंटल हेल्थ का विषय आया, माननीय सदस्या ने उस विषय को लाया निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लिए मेंटल हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में उनके नेतृत्व में आज मैं कह सकता हूं कि बिहार के कोईलवर में मेंटल हेल्थ का जो हॉस्पिटल बना है वह राष्ट्र स्तरीय अस्पताल है और माननीय सदस्या को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, दीदी आप एक दिन अपना महत्वपूर्ण समय दीजिए मुझे आप एक घंटे का समय दीजिए मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं दीदी मैं आपको लेकर चलूंगा उस अस्पताल में और उस अस्पताल के गेट से लेकर मरीजों के इलाज से लेकर मरीजों को कैसे खाना खिलाया जाता है, मुस्कुराइये नहीं दीदी, बहुत गंभीर बात आपने उठाई थी

(व्यवधान)

और मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रही थीं तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था,

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जाइये ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : आप जो बोल रही थीं मैंने चुपचाप सुना पूरी बातों को...

अध्यक्ष : आपने अपनी बातों को रखा है ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : और मैंने पूरी गंभीरता से आपकी बातों को सुना है, मैंने प्रशंसा भी की है कि आपने एक बहुत ही सही विषय को उठाया है । मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मैं एक दिन, एक घंटे का बहुमूल्य समय केवल चाहता हूं । आप

दीदी अपनी सुविधा से समय बता दीजिएगा मैं आपके साथ अस्पताल चलूंगा और चलकर दिखाउंगा कि कोईलवर का मेंटल हॉस्पिटल हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैसा बना है तब आप विचार बनाइयेगा कि बिहार में कैसा मेंटल हॉस्पिटल है, तब शायद उचित होगा । दीदी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रही थीं मैं बैठकर पूरा सुना हूं...

अध्यक्ष : सुनना चाहिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : आपने कैंसर की बात की । वुमन कैंसर की बात की । दीदी, मैं बताना चाहता हूं आपको, बिहार इकलौता राज्य है पूरे देश में, जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त में एच0पी0वी0 वैक्सिन देता है यह करनेवाला बिहार इकलौता राज्य है और कैंसर के संदर्भ में कितना काम हुआ है उसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने बजट भाषण में दी है । उसको मैं दुहराउंगा नहीं उसको आप पढ़ लीजिएगा दीदी । आपने जे0ई0 और ए0ई0एस0 की बात की, एक दिन और समय दीजिए एक घंटा मेरे साथ आप मुजफ्फरपुर चलिए, मुजफ्फरपुर एस0के0एस0सी0एच0 में या जो माननीय सदस्य मुजफ्फरपुर जिले के होंगे उनलोगों ने उस अस्पताल को देखा है, विश्वस्तरीय वह अस्पताल मैंने बनवाया है मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और वह सौ बेड का अस्पताल है दीदी, पूरे देश में सौ बेड का पीकू हॉस्पिटल कहीं नहीं है मुजफ्फरपुर को छोड़कर यह मैं आपको बताना चाहता हूं । आपको, हमको, सबको एक बिहारी होने के नाते गर्व करना चाहिए कि हम उस बिहार विधान सभा के, सदन के सदस्य हैं जिस राज्य के अंदर सौ बेड का वर्ल्ड क्लास पीकू हॉस्पिटल है जो देश में कहीं नहीं है दीदी और आप एक दिन जरूर चलिए मेरे साथ । पूरी फैसिलिटी दिखाउंगा । बेड पर बच्चे को कैसे रखा जाता है, उसका गार्जियन जब बगल के भवन में रहता है, अपने बच्चे को कैसे मॉनिटर करता है एक–एक मॉनिटरिंग कैसे होती है वह चलकर जब दिखाउंगा तब शायद आपको ध्यान में आ जायेगा कि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राष्ट्रीय स्तर नहीं विश्व स्तर की तरफ बढ़ रही हैं । दीदी, आपके लिए भी थोड़ा चार लाइन मैंने लिखा है, मैंने बैठे–बैठे लिखा चूंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप ये बात बोलियेगा लेकिन जब आपने बोला तो मैंने भी चार लाइन लिख लिया ।

''जब खुशी देने का वक्त था, तब तो सितम ढाया आपने
अब बहार आई है तो कांटे दिखते हैं आपको ।''

(व्यवधान)

महोदय, नहीं–नहीं मैंने लिखा है, मैंने यहां बैठे–बैठे लिखा, मैंने अपने मित्र को पढ़ाया भी कि देखिए ठीक लिखा है या नहीं लिखा है चूंकि ये भी बहुत शेरो–शायरी जानते हैं । महोदय, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों ने जो

सुझाव दिए हैं या अपने क्षेत्र के विषय रखें हैं, निश्चित रूप से विषयों को मैं देखूंगा और जहां जिन सुविधाओं का विस्तार या उन्नयन करना है वह मैं करूंगा । आज जरूर यह बताना चाहता हूं कि बिहार की पहचान स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ही होती थी पहले और राष्ट्रीय स्तर पर भी...

(व्यवधान)

आलोक जी...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, प्लीज बैठिए आप । आपके दल को मौका मिला था बोलने के लिए, आपने बातों को रखा है ।

(व्यवधान)

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : आलोक जी, भाषण देना है । भाषण सुनियेगा कि बात सुनियेगा ।

अध्यक्ष : आलोक जी बैठ जाइये ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : भाषण हम देने लगेंगे तो तिरतिरी लगेगा, सदन छोड़कर चले जाइयेगा फिर ।

(व्यवधान)

देखिए, अभी हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, सदन छोड़कर भाग जाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अपनी बातों को, आलोक जी, बात सुन लीजिए, बैठ जाइये ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : मैं कह रहा हूं सदन छोड़कर भागना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं बचेगा ।

अध्यक्ष : अरूण जी, बैठिए । आलोक जी बैठिए ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : आलोक जी, ठीक है । आलोक जी, आपको नेता प्रतिपक्ष बनने का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी बात आ गई ।

श्री मंगल पांडेय, मंत्री : खिसक रहे हैं थोड़ा–थोड़ा । नहीं–नहीं, आप नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं मेरी शुभकामना है । देखिए, भाग गए न, सदन छोड़कर भाग गए न, सुनने की भी हिम्मत नहीं है, इतना आप कमजोर होंगे मैंने सोचा नहीं था ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण बहिर्गमन कर गए)

देखिए महोदय, भाग गए ये लोग सदन से । चूंकि विकास और इनका दल ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक नहीं लगते हैं । विकास सुनते ही इनलोगों के मन में बहुत खटास पैदा हो जाती है ।

(क्रमशः)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : मैं तो विकास की बात कर रहा था तो वे कैसे सुनते इसलिए चले गए । हमारे गार्जियन बिजेंद्र बाबू कह रहे हैं कि इन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जनता ही ट्रीटमेंट कर देती है । वह तो मैंने आमंत्रण दे दिया है ।

महोदय, मैं कहना यह चाह रहा था कि बिहार की चर्चा पहले जब होती थी तो होता था स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोई भी मानक आप देखिए तो हर कोई देखता था नीचे से बिहार किस नंबर पर है, अब हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की जब चर्चा, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में होता है महोदय तो अब वहां के अधिकारी भी कहते हैं कि जरा ऊपर से देखो बिहार कितने नम्बर पर है । चूंकि आज बहुत सारे मानकों में बिहार नम्बर–1 पर है उसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है । महोदय, नवजात शिशु मृत्यु दर जो है वह आज घटकर 18 हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है महोदय । उसी प्रकार से 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु होती है वह भी घटकर 27 हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से कम है । महोदय, शिशु मृत्यु दर भी घटकर 23 हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से कम है और ये सभी चीजें राष्ट्रीय औसत से बेहतर तो तभी न हैं जब अस्पताल में सुविधाएं दी जा रही हैं, अस्पताल में यदि सुविधाएं नहीं होतीं, आज मुख्यमंत्री जी एस0एन0सी0यू0 नहीं बनवाये होते तो इन बच्चों के जीवन को हम कैसे बचा पाते और इन मानकों में हम देश से भी बेहतर कैसे हो पाते । हमने यह सारे काम किये हैं महोदय । मातृ मृत्यु दर 300 से भी अधिक था महोदय 2005 में, आज वह घटकर 104 पर आ गयी है और सस्टेनेबल डेवल्पमेंट गोल (एस0टी0जी0) के तहत 2030 तक इसको 70 पर लाना है महोदय । उस लक्ष्य के साथ हमलोग आगे बढ़ रहे हैं । महोदय, जब हमलोग को जनता ने सेवा करने का अवसर दिया था तो इस राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट 4.2 था, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व हमारे राज्य का बहुत था और जनसंख्या का जो बोझ है वह हमारे ऊपर था । आज स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग विभिन्न विभागों के प्रयास से वह टी0एफ0आर0 घटकर 2.8 पर आ गया है, इसमें हमने बहुत सुधार लाया है । पिछले 16 महीनों से राज्य के अस्पतालों में जो दवाइयां पहुंचाई जाती हैं, जिसकी चर्चा सभी माननीय सदस्य कर रहे थे और सभी माननीय सदस्य के सामने मैं कहना चाहता हूं कि आज पिछले 16 महीने से पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में बिहार नंबर–1 पर चल रहा है, लगातार महोदय और ये कोई बिहार सरकार का या बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा नहीं है महोदय यह डी0वी0डी0एम0एस0 का आंकड़ा है, ड्रग्स एण्ड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम जो भारत सरकार की है,

उस आंकड़े में बिहार पिछले 16 महीने से लगातार नंबर–1 पर है जिसकी शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 में भैरो सिंह शेखावत जी से करवाई थी, आज वह यात्रा पहुंचकर यहां तक पहुंच गया कि हमलोग देश में लगातार नंबर–1 चल रहे हैं । महोदय, टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, किसी भी राष्ट्र और राज्य के स्वास्थ्य मानक के लिए और टीकाकरण में आज बिहार 93 परसेंट पर पहुंच गया है, देश के टॉप–3 राज्यों में हम पहुंच गये हैं । महोदय, गरीबों को जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम 5 लाख तक की मुफ्त कैशलेस सेवा देते हैं, आज वह 4 करोड़ 14 लाख कार्ड बन गया है और कार्ड बनाने में महोदय, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि बिहार पूरे देश में कार्ड बनाने के मामले में आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, एक नंबर तो हम हो नहीं सकते हैं चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी हमसे दोगुनी है लेकिन अब थोड़ा सा से ही मध्य प्रदेश हमसे आगे है महोदय तो आज गरीबों की सेवा की भावना जो अंत्योदय की बात मैंने कही, उस अंत्योदय की भावना के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, आज उसी का परिणाम है पूरा विभाग महोदय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दो सालों से उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी कुछ समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री रहें, उनके रहते समय भी इस कार्ड को बनाने में बहुत गति प्रदान की गयी थी तो हम सब लोग कैसे गरीबों को सेवा दें इस दिशा में काम करते हैं । मेडिकल कॉलेज की बात बहुत आ गयी है उसको बार–बार नहीं दोहरना चाहता लेकिन संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के 58 वर्षों के बाद इस राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे 6 सरकारी और 3 प्राइवेट और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 58 वर्षों में 9 मेडिकल कॉलेज और 20 वर्षों में महोदय 18 नये मेडिकल कॉलेज, आज 27 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर हैं महोदय । किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और 18 तो आज शुरू हो गये हैं, कुल 27 मेडिकल कॉलेज आज बिहार के अंदर चल रहे हैं, अगले तीन वर्षों के अंदर महोदय इस राज्य में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 46 हो जायेगी । आज उस टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं, हमने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया ताकि सभी व्यवस्थाएं और शिक्षण का कार्य ठीक से चलें । माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि यदि चिकित्सक बनाने का महाविद्यालय ही नहीं रहेगा तो चिकित्सक बनेंगे कहां से और यदि जिन लोगों पूर्व में लम्बे समय तक शासन किया उनलोगों का थोड़ा भी ध्यान रहता महोदय तो आज बिहार में बहुत चिकित्सक बन रहे होते, लेकिन अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है उस निर्णय के आलोक में अब

हमलोग हर जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत इस मेडिकल कॉलेज के साथ–साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, ए0एन0एम0 हो, जी0एन0एम0 हो, बी0एस0सी0 नर्सिंग हो, एम0एस0सी0 नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, पारा मेडिकल की पढ़ाई हो, फार्मेसी की पढ़ाई हो आज हर चीज को पिछले एक दशक में हमने राष्ट्रीय स्तर पर लाकर उन व्यवस्थाओं को आज पहुंचाया है । महोदय, मुझे आज खुशी है कि हमारे राज्य के अंदर ऐसे भी नर्सिंग संस्थान हैं, जिन नर्सिंग संस्थानों से बेटियां पास होकर विदेशों में सेवा देने जा रही हैं, उस स्तर के भी आज नर्सिंग संस्थान बिहार के अंदर हैं । महोदय, मैं भी मानता हूं और लगातार मुख्यमंत्री जी भी अनुश्रवण करते हैं मानव बल की बहुत जरूरत होती है और लगातार हमारी जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने के लिए हम काम कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष 2025–26 में 7 हजार 468 ए0एन0एम0 की नियुक्ति की गयी, 9 हजार 54 ए0एन0एम0 की नियमित नियुक्ति और एन0एच0एम0 के तहत 5006 ए0एन0एम0 की नियुक्ति अर्थात् कुल 14 हजार 60 ए0एन0एम0 की नियुक्ति बहुत शीघ्र होने वाली है और 5006 नर्सेज की नियुक्ति तो हम अगले 15 दिनों के अंदर करने वाले हैं । ये 597 नियमित सामान्य चिकित्सकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल 2387 चिकित्सकों की नियुक्ति पिछले साल की गयी । महोदय, 2025–26 में 1126 विशेषज्ञ चिकित्सक और एन0एच0एम0 के तहत 228 चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी । 2025–26 में एन0एच0एम0 के तहत कुल 3682 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की गयी है और महोदय, विभिन्न संवर्ग अंतर्गत विभिन्न पदों पर 39,095 नियमित नियुक्ति एवं एन0एच0एम0 के तहत 5226 रिक्ति अर्थात् कुल 44321 रिक्तियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जिसमें से कई पदों की परीक्षाएं ली जा चुकी हैं, कई पदों की परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, कई के कागजात भी जांच हो चुके हैं तो बहुत जल्दी इन सब नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली हैं । दवाओं की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है और बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, कुल 1 करोड़ 79 लाख परिवार हैं जिनको हमको यह लाभ पहुंचाना है और 1 करोड़ 79 लाख परिवार में से महोदय 1 करोड़ 69 लाख परिवार तक हमने यह कार्ड पहुंचा दिया है, मतलब लगभग 95 प्रतिशत घरों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम हम सब लोगों ने किया है ।

क्रमशः

(क्रमशः)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : और अब इस बदलती हुई दुनिया में डिजिटल सेवाओं की बहुत जरूरत होती है, पूरा व्यवस्था अब डिजिटलाइज्ड हो रहा है । कई माननीय सदस्य ने कहा टेलीमेडिसिन की बात की । मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीमेडिसिन की सेवा देने में भी बिहार सदैव दूसरे से लेकर चौथे स्थान के बीच में हर साल, पिछले तीन साल से रहता है और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको हम टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं । हम मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत भव्या से जो एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑनलाईन पंजीकरण कर रहे हैं । हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसके माध्यम से सभी अस्पतालों को हम सी0सी0टी0वी0 कैमरा से लगातार निगरानी करते हैं ताकि वहां की व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहे और जो टेलीमेडिसिन की मैंने बात की 02 करोड़ 82 लाख मरीजों का टेलीमेडिसिन के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में हमलोगों ने यह सुविधा उपलब्ध करायी है । मैंने चमकी बुखार के बारे में पहले ही बताया कि ए0ई0एस0 को ही चमकी बुखार कहते थे । उस संदर्भ में जो काम हमलोगों ने किया है, उसे आज सबलोग देख रहे हैं और उसका परिणाम है कि 2019 के बाद से पूरी तरीके से उस चमकी बुखार को नियंत्रित करने में हम सफल रहे हैं । लेकिन उसके लिये प्रतिवर्ष हमको मेहनत करना पड़ता है । फरवरी के महीने से लेकर मई के महीने तक ट्रेनिंग करायी जाती है और फिर उसके बाद नीचे के अस्पतालों में व्यवस्था बनायी जाती है । बाल ह्रदय योजना की चर्चा हुई । महोदय, अभी तक 2746 बच्चों की जान हमने बचायी है । आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी उस कार्यक्रम में थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने इस योजना का शुभारंभ बिहार में किया था । अध्यक्ष महोदय, इसका दर्द वही जान सकता है, जिसके घर में किसी बच्चे के ह्रदय में छेद होगा और वह गरीब होता है, दूसरा इसका दर्द नहीं समझ सकता है । मेरे भी परिवार में, मेरे बचपन में मेरे घर में ऐसा हुआ था इसलिये इस बीमारी के बारे में समझ मुझे थी, तब मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इस योजना को लागू किया था और आज 2746 बच्चों की जान हमलोगों ने बचायी है । महोदय, जो हमने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण की बात कही अभी तक 06 लाख 78 हजार 115 किशोरियों को हम एच0पी0वी0 वैक्सिन देने में सफल हुये हैं । अभी हम 1941 एंबुलेंस से सर्विसेज दे रहे हैं । बहुत शीघ्र इसमें और 124 एंबुलेंस जोड़ने वाले हैं, 2065 एंबुलेंस हो जायेगा, जिससे हम लोगों को सेवाएं देने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीनियर रेजिडेंट का पद हो, जूनियर रेजिडेंट का हो, ट्यूटर का हो, फार्मासिस्ट का हो, ड्रेसर का हो, एक्स–रे टेक्निशियन हो,

ओ0टी0 असिस्टेंट हो, ई0सी0जी0 टेक्निशियन हो, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी हो, लैब टेक्निशियन हो । ऐसे सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया और कार्रवाई चल रही है । महोदय, इस पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को हम जो लगातार बेहतर कर रहे हैं । इस बार जब जनता के आर्शीवाद से हमलोगों की सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है । मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सात निश्चय पार्ट–3 के तहत स्वास्थ्य विभाग को भी कुछ काम करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी का मिला है, कुछ निर्णय हुये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा के विस्तार किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत सभी प्रखंड स्तरीय सामान्य स्वास्थ्य केन्द्रों को आगे आने वाले वर्षों में, मैं वर्षों स्पष्ट कर रहा हूं महोदय कोई ऐसा नहीं समझे कि महीनों में । चूंकि यह एक लंबा काम है । कुछ वर्ष लग सकते हैं, दो साल, तीन साल लग सकते हैं । ये स्पेशलिटी हॉस्पीटल के रूप में विकसित करने का काम हमलोग करेंगे । जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाकर हमलोगों ने काम शुरू कर दिया है और क्रिटिकल केयर ब्लॉक विभिन्न सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में और कुछ मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी भारत सरकार के सहयोग से बनवा रहे हैं । प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में जैसे–मेदांता को हमलोगों ने दिया, शंकरा आई फाउंडेशन को हमलोगों ने दिया । उसी प्रकार से प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने की नीति हमलोगों ने बनायी है । नए मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में बेहतर शिक्षा एवं उपचार के लिये पी0पी0पी0 मॉडल पर हम काम करेंगे, उसका प्रस्ताव हमने तैयार कर लिया है और इसको बढ़ावा देने वाले हैं । जिसकी चर्चा हो रही थी सदन में, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी निर्देश मिल चुका है और माननीय मुख्यमत्री जी का इस संदर्भ में वक्तव्य भी आया है । सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु आवश्यक नीति निर्माण का काम किया जाए । दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकों के लिये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जायेगी, जो रूरल एरिया में, जो दूरस्थ एरिया में चिकित्सक हैं, उनको हम अतिरिक्त सैलरी देने की व्यवस्था करेंगे । ताकि हमारे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चिकित्सक आसानी से जुड़ सकें । अंत में महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी नागरिकों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के लिये लगातार प्रयासरत है एवं सात निश्चय योजना–3 के तहत तय किये गये सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये दृढ़ संकल्पित है और आगे कार्य करेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष

2026–27 के लिये अनुदान मांग संख्या–20 के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 11237.64 करोड़ रुपए एवं योजना मद में 10032.77 करोड़ रुपए अर्थात कुल 21270.41 करोड़ रुपए की अनुदान की मांग की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ।

महोदय, एक बार फिर से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस सदन में आठवीं बार स्वास्थ्य विभाग का बजट रखने का अवसर दिया है । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार उत्तर समाप्त हुआ...

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, और मैं आग्रह करूंगा कि जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया है, उसे वह वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपए से घटाई जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 21270,40,73,000/– (इक्कीस हजार दो सौ सत्तर करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–16 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–47 (सैंतालीस) है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक–17 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग

मंगल पाण्डेय

मंत्री, स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

का

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष:
2026-27

सुलभ स्वास्थ्य -
सुरक्षित जीवन

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा नवनियुक्त विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों का नियुक्त पत्र वितरण

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा
7468 नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ए.एन.एम.) का नियुक्त पत्र वितरण

मंगल पाण्डेय

मंत्री, स्वास्थ्य विभाग,

बिहार, पटना

माननीय अध्यक्ष महोदय,

समाज के अंतिम पायदान तक प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाएं सहज एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बदलते परिवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का निरन्तर विस्तार, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पूर्ण पारदर्शिता के साथ समाज के हर घर–हर व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में किये गये निरंतर प्रयास एवं पहल के कारण स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों में विगत वर्षों में आशातीत प्रगति हुई है। इसी का परिणाम है कि जहाँ एक ओर सरकारी संस्थानों में चिकित्सीय सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सूचकांक भी बेहतर हो रहे हैं। राज्य का **शिशु मृत्यु दर** (IMR) **SRS 2023** के अनुसार घटकर **23** हो गया है, जो **राष्ट्रीय औसत से बेहतर** है। **नवजात शिशु (जन्म से 28 दिन) मृत्यु दर** (Neo-natal Mortality Rate-NMR) भी SRS 2023 के अनुसार घटकर 18 हो गया है, जो **राष्ट्रीय औसत से बेहतर** है। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर (Under 5 Mortality Rate) SRS 2023 के अनुसार घटकर 27 हो गया है, जो भी **राष्ट्रीय औसत से बेहतर** है। राज्य का **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) घटकर SRS 2023 के अनुसार वर्तमान में**

104 है, जिसे चरणबद्ध तरीके से SDG (Sustainable Development Goal) 2030 के तहत 70 तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है। **संस्थागत प्रसव का दर** वर्ष 2019–20 (NFHS-5) के सर्वे के अनुसार **76.2** प्रतिशत है। कुल प्रजनन दर (**TFR**) NFHS-4 (2015-16) के आँकड़ों के अनुसार 3.4 था, से घटकर **SRS-2023** के अनुसार वर्तमान में **2.8** हो गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS – 5) के अनुसार राज्य का **पूर्ण प्रतिरक्षण** का प्रतिशत **71 प्रतिशत** था। राज्य स्तर से किये जा रहे निरंतर प्रयासों एवं सघन अनुश्रवण के परिणामस्वरूप एच.एम.आई.एस. (वर्ष 2025–26) के दिसम्बर, 2025 माह के प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य का **पूर्ण प्रतिरक्षण** का आच्छादन **93 प्रतिशत** हो गया है।

राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार जिला एवं अनुमण्डलीय अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जा रही है। नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार सभी स्वास्थ्य संस्थानों में समुचित मानव बल उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **7,468** ए0एन0एम0 की नियमित नियुक्ति की गई है।
- साथ ही **9,054** ए0एन0एम0 की नियमित नियुक्ति तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत **5,006** ए0एन0एम0 की नियुक्ति अर्थात् **14,060 ए0एन0एम0** की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **597** नियमित सामान्य चिकित्सकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कुल **2,387** चिकित्सकों (सामान्य एवं आयुष) की नियुक्ति की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल **1,126** नियमित विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कुल **228** विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत **कुल 3,682** सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) की नियुक्ति की गई है।
- विभिन्न संवर्ग अंतर्गत विभिन्न पदों पर 39,095 नियमित नियुक्ति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 5,226 रिक्तियों अर्थात् **कुल 44,321** रिक्तियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

विभिन्न राजकीय चिकित्सकीय संस्थानों में नागरिकों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में भी निरंतर सुधार हुआ है। अब लगभग सभी प्रखण्ड स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों तक एक्स–रे, ई0सी0जी0, नेत्र परीक्षण एवं पैथोलॉजिकल जाँच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में डायलेसिस, सी0टी0 स्कैन एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है।

साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की कड़ी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में 350 से अधिक प्रकार की दवायें, अनुमण्डलीय अस्पताल में

250 से अधिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 240 से अधिक, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में 150 एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में 120 प्रकार की दवायें उपलब्ध है।

राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाकर सरकार द्वारा सभी जिलों में जीपीएस से लैस 180 मुफ्त औषधि वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत सरकार के Drug and Vaccine Distribution Management System (DVDMS) Central Dashboard पर **औषधियों की आपूर्त्ति एवं वितरण में बिहार सितम्बर, 2024 से अर्थात् विगत 17 माह से प्रथम स्थान** को बनाये हुए है।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **सात निश्चय–3** के तहत प्रखण्डस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र, जिला अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ की जा रही है।

महोदय,

अब मैं सदन में कुछ विशेष स्वास्थ्य योजनाएँ/पहल के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराना चाहता हूँ।

सार्वभौमिक टीकाकरण की प्रगति :–

शिशुओं एवं गर्भवती माताओं के नियमित टीकाकरण की कड़ी में प्रति माह लगभग 1,22,000 टीकाकरण सत्रों का आयोजन एवं प्रतिवर्ष लगभग 37 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटेनस एवं गलघोंटू से सुरक्षा प्रदान करने हेतु Tetanus-diphtheria (Td) का टीकाकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य के चिन्हित **2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर)** पर स्थापित 'प्रतिरक्षण कॉर्नर' पर भी प्रति सप्ताह तीन दिन टीकाकरण की सुविधा है। टीकाकरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु चयनित शहरी क्षेत्रों में **281 मॉडल इम्यूनाईजेशन सेन्टर** स्थापित है। टीकों का गुणवत्तापूर्ण भंडारण, ससमय उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु **Electronic Vaccine Intelligence Network (eVIN) System** क्रियाशील है।

परिणामस्वरूप वर्त्तमान में राज्य का पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन लगभग 93 प्रतिशत (दिसम्बर, 2025 स्रोत एच.एम.आई.एस.) है।

संस्थागत प्रसव की प्रगति की स्थिति :–

- राज्य में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने एवं मातृ स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ बनाने के प्रयास की कड़ी में 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' के तहत गर्भवती

महिलाओं को हर महीने अब 2 के बजाय 3 दिन यथा प्रत्येक माह के 9, 15 एवं 21 तारीख को शिविर लगाकर मुफ्त और व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रसव सेवा केन्द्र, जो गत वित्तीय वर्ष में 702 थे, को बढ़ाकर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1,270 कर दिया गया है।

- राज्य में अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक कुल 120 प्रथम रेफरल इकाई (FRU) में C-Section की सुविधा दी जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 17,53,764 संस्थागत प्रसव हुए हैं, वहीं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2025 तक 13,46,235 संस्थागत प्रसव हुए हैं।

- वैसे गाँव, जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक गृह प्रसव हो रहे हैं, वैसे गाँवों को चिन्हित कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु **'होम डिलीवरी मुक्त पंचायत पहल'** अभियान चलाया जा रहा है।

- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसवोपरांत प्रसूता माताओं के डिस्चार्ज होने के उपरांत घर तक ख्याल रखने के उद्देश्य से उपहार स्वरूप 'जच्चा–बच्चा किट' उपलब्ध कराया जा रहा है।

शिशु स्वास्थ्य पहल :–

- बीमार नवजात के उपचार हेतु राज्य के 45 स्वास्थ्य संस्थानों में क्रियाशील **विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU)** के माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन 55,000 बीमार नवजातों की भर्ती कर उच्च तकनीक से शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया जा रहा है।

- इसके अंतर्गत "कंगारू मदर केयर" की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही माँ को नवजात के देखभाल हेतु प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।

- SNCU के अंतर्गत बीमार नवजात को अंतःवासी मरीज मानते हुए नवजात के स्थान पर उसकी माता अथवा किसी एक परिजन को निःशुल्क भोजन दिये जाने की व्यवस्था है।

- इसके साथ ही **विशेष नवजात देखभाल इकाई** (SNCU) के स्वरूप को उत्क्रमित करते हुए राज्य के 15 अनुमंडलीय अस्पतालों में 20 बेड का मातृ नवजात देखभाल इकाई (MCNU) संचालित है, जहाँ बीमार नवजात के साथ–साथ उनके माँ के रहने की भी व्यवस्था है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक 18 वर्ष तक के कुल 3,698 बच्चों को शल्य चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें न्युरल ट्यूब दोष, फटे होंट एवं तालु, जन्मजात मोतियाबिन्द, माईक्रोसेफली, जन्मजात ह्रदय रोग, जन्मजात बहरापन इत्यादि सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :–

इसके तहत समुदाय स्तर पर किशोरों, उनके माता पिता, परिवारों एवं समुदाय के बीच किशोर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 7,863 (दिसंबर, 2025 तक) किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस का आयोजन राज्य के 26 जिलों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में किया गया।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान :–

इस अभियान (17 सितम्बर से 2 अक्टूबर–2025) के अंतर्गत कुल 1,62,135 (बच्चें, किशोर/किशोरियाँ एवं गर्भवती महिलाओं) लाभार्थियों का अनीमिया जाँच, स्वास्थ्य संस्थान एवं विद्यालयों में कुल 12,80,425 किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता पर परामर्श, 3,23,997 किशोरियों का HPV Vaccination, 2,98,217 किशोरियों का नेत्र जाँच एवं दृष्टिदोष पाये गये 4274 के मध्य निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया।

कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहल के साथ 'कुष्ठ रोगी खोजी अभियान' चलाया जाता है और मरीज की पुष्टि के उपरांत उसके सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को रिफैम्पिसिन एकल खुराक (Single dose rifampicin) दवा खिलायी जाती है, ताकि कुष्ठ के प्रसार दर को रोका जा सके।

ए.ई.एस. नियंत्रणार्थ पहल :–

- राज्य में चमकी बुखार के बेहतर प्रबंधन एवं सहज उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु SoP-2025 एवं मार्गदर्शिका के अनुसार चिकित्सकों एवं संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है, ताकि मरीजों का त्वरित एवं सही उपचार हो सके।
- भारत सरकार द्वारा चिन्हित राज्य के 15 ए.ई.एस. अति प्रभावित जिलों में 10 बेड का शिशु चिकित्सा गहन इकाई कार्यरत है।
- साथ ही मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल में 100 बेड का शिशु चिकित्सा गहन इकाई तथा सदर अस्पताल में 8 बेड का इंसेफलाईटिस वार्ड कार्यरत है।

इसी प्रकार **डेंगू पर नियंत्रण** हेतु भी Administrative Standard Operating Procedure है, जिसके अनुसार पूर्व तैयारियाँ कर डेंगू के नियंत्रणार्थ सारी कार्रवाई की जाती है।

मलेरिया पर नियंत्रण हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में प्रति हजार जनसंख्या पर एक से कम मलेरिया रोगी प्रतिवेदित हुए, जिसे वर्ष 2027 तक शून्य किये जाने का लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्बाद्ध रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है और जाँच की संख्या को बढ़ाया गया है।

कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम अतर्गत वर्ष 2013 में बिहार राज्य के 38 जिलों में से 33 जिले कालाजार आक्रांत जिले के रूप में घोषित थे, वहीं वर्ष 2022 से अति कालाजार प्रभावित प्रखंडों (प्रखंड स्तर पर प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक या एक से अधिक मरीज) की संख्या शून्य प्रतिवेदित है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा **वर्ष 2023** तक **कालाजार उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्य को बिहार राज्य** ने **एक वर्ष पूर्व** अर्थात **वर्ष 2022** में ही **पूर्ण** कर लिया। अब इसी स्थिति को आगे बनाये रखने का प्रयास जारी है। यह उपलब्धि वर्ष में दो बार कीटनाशक का छिड़काव, गहन अनुश्रवण एवं अन्य विभिन्न प्रयासों के कारण संभव हो सका है।

यक्ष्मा नियंत्रण :–

- राज्य में यक्ष्मा रोगियों का Treatment Success Rate वर्तमान में **86 प्रतिशत** है तथा **मृत्यु दर 2.1 प्रतिशत** है।
- राज्य को टीबी मुक्त बनाने हेतु वर्ष 2025 में आधुनिकत्तम उपकरणों–**91 CBNAAT** एवं **560 TrueNat** मशीनों द्वारा **7,55,917** जाँच किए गये, जो कुल टीबी जाँच 11,87,795 का **64%** है। CBNAAT एवं TrueNat से संक्रामक रोगियों की तेजी से पहचान होती है। रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स की जानकारी मात्र दो घंटे में उपलब्ध हो जाती है।
- 495 डिजिटल एक्स–रे द्वारा **8,13,650** लोगों का **चेस्ट एक्स–रे** किया गया, जिनमें से **42,319 टीबी संभावित रोगी** पहचान कर उपचार प्रारंभ किया गया।
- AI युक्त **हैण्डहेल्ड एक्स–रे** से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग सुविधा उपलब्ध है। टीबी मुक्त भारत अभियान तहत फुड बास्केट वितरण एवं सम्पर्क रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :–

- राज्य के 34 जिलों के 397 प्रखंडों में लगभग 4 लाख प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कार्यकर्ता तथा 40 हजार से अधिक सक्रिय बूथ के माध्यम से राज्य के 397 प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान दिनांक 10 फरवरी से 27 फरवरी, 2026 तक संचालित किया जा रहा है, जिसमें 11 फरवरी 2026 को **"मेगा डे"** के रूप में मनाया गया। इस अभियान में एक ही दिन में **1 करोड़ 35 लाख से अधिक** लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया गया।

राज्य में विगत वित्तीय वर्ष में लगभग 18 हजार से अधिक हाइड्रोसील ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं तथा अन्य चिन्हित मरीजों की सर्जरी सुनिश्चित की जाएगी।

राज्यस्तरीय लोक/बाल एवं किशोरी कल्याणकारी पहल

बाल हृदय योजना :–

'बाल हृदय योजना' अन्तर्गत 'प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउन्डेशन', अहमदाबाद सहित राज्य के तीन प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों यथा– इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं जय प्रभा मेदान्ता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल, पटना में बच्चों के हृदय रोग के जाँच हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें अबतक सभी जिलों से आए 5,093 बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की गई। दिनांक 31 जनवरी 2026 तक कुल 2,746 बच्चों का सफलतापूर्वक ईलाज किया जा चुका है ।

बाल श्रवण योजना :–

बिहार राज्य के जन्म से लेकर 5 वर्ष के मूकबधिर बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु संचालित बाल श्रवण योजना अन्तर्गत मूकबधिर बच्चों का कॉक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी की जा रही है। योजना अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक कुल 514 बच्चों का सफलतापूर्वक कॉक्लियर इम्प्लांट (Cochlear implant) किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना :–

इस योजना अंतर्गत थैलेसीमिया पीड़ित 12 वर्ष से कम आयुवर्ग के बच्चों का Bone Marrow Transplantation (**अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण**) विधि से निरोधात्मक उपचार क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सी०एम०सी०) वेल्लोर, तमिलनाडु के माध्यम से निःशुल्क कराया जा रहा है, जिस पर प्रति लाभार्थी लगभग 15 लाख रूपये का खर्च आता है और इस पर होने वाले व्यय का वहन 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' से किया जा रहा है। बिहार में 3070 थैलेसीमिया मरीजों को चिन्हित किया गया है। अब तक कुल 406 बच्चों एवं उनके परिजनों के कुल 1173 सैंपल की जाँच की गई है, जिसमें से कुल 128 बच्चों का डोनर के साथ HLA मैच पाया गया है। अब तक 30 बच्चे रोग मुक्त हो चुके हैं एवं 15 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं संबंधित अन्य ईलाज CMC Vellore में जारी है।

''मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना'' :–

इस योजना अंतर्गत 09 से 14 वर्ष आयुवर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) से प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल 6,78,115 किशोरियों को HPV के टीका से आच्छादित किया गया है।

ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ईलाज हेतु चिकित्सकीय अनुदान :–

राज्य में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy-DMD) एवं अन्य आनुवंशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से ग्रसित मरीजों को प्रति मरीज 6 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना

- राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के नाम से राज्य के मूल निवासियों को चिकित्सीय सहायतार्थ वर्ष 2006 से लगातार संचालित है।
- राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को गम्भीर और मंहगे ईलाज विशेष कर असाध्य/गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के ईलाज हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- बिहार के मूल निवासियों, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रूपये है, वे इस योजना के पात्र होते हैं।
- वर्त्तमान में विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक 15.02.2018 के तहत कुल 16 प्रकार के गंभीर रोगों यथा–कैंसर, ह्रदय रोग, ब्रेन सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, हीप/नी रिप्लेसमेंट, कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हिमोफीलिया इत्यादि में चिकित्सा अनुदान की राशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट रोगों के लिए विशेष परिस्थिति में भी अनुदान प्रदान की जाती हे।
- चिकित्सा अनुदान सभी सरकारी अस्पतालों एवं सी0जी0एच0एस0 से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए मान्य है।
- **इस जनकल्याणकारी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 27,890 मरीजों को 216.75 करोड़ रू0 तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 (जनवरी, 26 तक) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के 21,380 मरीजों को ईलाज हेतु कुल 168.34 करोड़ रू0 की अनुदान राशि दी गई है।**
- चिकित्सा अनुदान की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त बिहार भवन, नई दिल्ली एवं मुम्बई स्थित निवेश आयुक्त एवं पटना स्थित सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान, पटना को समय–समय पर मरीजों की अनुदान हेतु एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजी लैब और उच्चस्तरीय उपकरण अनुभाग

राज्य द्वारा अभिनव पहल करते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों की अत्याधुनिक तरीके से जाँच हेतु राज्य के पहले **संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजी लैब और उच्चस्तरीय उपकरण अनुभाग** की शुरूआत की गई है, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ के विभिन्न मानकों की जाँच आधुनिक तरीके से किये जाने की व्यवस्था है।

आधारभूत संरचना

महोदय,

आधुनिक युग की मांग के अनुसार स्वास्थ्य संरचनाओं का उन्नयन की दिशा में कई पहल किए जा रहे हैं, जो निम्नवत् हैः–

सभी जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की सुविधा :–

राज्य के मेधावी छात्रों के राज्य के बाहर चिकित्सा शिक्षा, सक्षम तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु पलायन को रोकने, चिकित्सकों की कमी को कम करने एवं राज्य में रोगियों को बेहतर एवं उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

- राज्य में वर्ष–2005 से पूर्व **6** संचालित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल थे, यथा– PMCH, NMCH, SKMCH, ANMMCH, JLNMCH & DMCH

- वर्ष–2005 के बाद राज्य में संचालित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, यथा– भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल, पावापुरी, **नालंदा,** जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, **मधेपुरा,** श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, **समस्तीपुर,** राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, **बेतिया (पश्चिम चम्पारण),** राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, **पूर्णियाँ** तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, **छपरा (सारण)** संचालित है, जिसमें श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण) में वर्तमान में सिर्फ अस्पताल संचालित है एवं आगामी शैक्षणिक सत्र से पठन–पाठन प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

- Establishment of new medical colleges attached with existing district/ referral hospital"- Phase-II अंतर्गत सीतामढ़ी, झंझारपुर (मधुबनी), सिवान, बक्सर, जमुई जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है।

- विकसित बिहार के सात निश्चय अंतर्गत 3 जिलों, यथा– बेगूसराय, महुआ (वैशाली) एवं भोजपुर (आरा) का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। राज्य स्कीम अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, यथा– मुंगेर एवं सुपौल का निर्माण किया जा रहा है।

- मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) एवं गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण का निर्णय लिया जा चुका है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- राज्य के 9 जिलों, यथा– सहरसा, गोपालगंज, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बाँका, औरंगाबाद, अररिया एवं खगड़िया में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें अररिया, बाँका एवं कैमूर जिला में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि का हस्तान्तरण हो चुका है तथा अन्य जिलों में भूमि चयन कर हस्तान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- साथ ही स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की घोषणा के आलोक में राज्य के अन्य 7 जिलों यथा– किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल एवं शेखपुरा में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा भूमि चयन प्रक्रियाधीन है।

- राज्य में स्वायत्तशासी संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना संचालित है, जिसमें 150 MBBS सीट एवं 113 PG सीट उपलब्ध है।

इस प्रकार राज्य में 12 राजकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल, केन्द्र सरकार के अधीनस्थ 02 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा, पटना), एक स्वायत्तशासी संस्थान, आई0जी0आई0एम0एस0, पटना तथा निजी प्रक्षेत्र में संचालित 12 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल अर्थात् राज्य में कुल 27 राजकीय/केन्द्रीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित है।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों का विकास और विस्तार

- **पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पुनर्विकास की वृहत योजनाः**– पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन के क्रम में चरणबद्ध तरीके से कार्ययोजना तैयार कर 250 नामांकन एवं 5,462 बेड के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा रु० 5,540.07 करोड़ की पुनर्विकास योजना की स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण में 1,117 बेड वाले 2 टावर के अस्पताल भवन को संचालित कर दिया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2028–29 तक संपूर्ण परियोजना को पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- **दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का पुनर्विकासः**– दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को कुल 250 नामांकन एवं 2500 शय्या के अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किये जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 132 करोड़ रूपये की लागत से 400 शय्या के सर्जिकल वार्ड का निर्माण हो चुका है। पुनः समीक्षोपरांत अतिरिक्त बेडों की क्षमता को देखते हुए वर्तमान में 1700 शय्या के अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसे आगामी 3 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में MBBS/PG पाठ्यक्रम के सीट एवं शैय्या की अद्यतन स्थिति :–

- राज्य में वर्तमान में 12 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित है, जिसमें शैय्या की कुल संख्या 12,204 तथा MBBS सीटों की संख्या 1420 है।
- 9 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों (PMCH, NMCH, DMCH, ANMMCH, SKMCH, JLNMCH, BHIMS, GMC, Bettiah & IGIMS) में पी0जी0 पाठ्यक्रम में सीट (डिग्री/ डिप्लोमा) की कुल संख्या–778 है।
- केन्द्र अधीनस्थ संचालित दो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों यथा– अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 150 MBBS सीट तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा, पटना में 100 MBBS सीट है।
- वर्त्तमान में निजी प्रक्षेत्र में संचालित कुल 12 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में शैय्या की कुल संख्या– 9542, MBBS-1900 सीट तथा PG-611 सीट है।
- शैक्षणिक सत्र 2026–27 में राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 550 MBBS सीट एवं निजी प्रक्षेत्र में संचालित/प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 2,850 MBBS सीट बढ़ोत्तरी हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 97, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में 10 एवं जिला अस्पतालों में 85 कुल–192 सीटों पर डी0एन0बी0 पी0जी0 पाठ्यक्रम संचालित है।

महोदय,

स्वास्थ्य संरचनाओं के उन्नयन एवं विस्तारीकरण की कड़ी में राज्य में अब एक और एम्स बनने जा रहा है, जिसके विकास एवं निर्माण कार्य की प्रगति निम्नवत् है:–

- **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दरभंगा** बिहार सरकार द्वारा एम्स, दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की गयी है तथा भू–खंड का बाउण्ड्री निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु DPR बनाने का कार्य IIT, दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है।
- **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना** परिसर में कुल 14.85 करोड़ की लागत से 248 शय्या के धर्मशाला भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सुपर स्पेशियलिटी / अतिविशिष्ट अस्पताल / ब्लॉक :–

- राज्य के चार पुराने चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों यथा **अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया; दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा; जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर तथा श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर** में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसके माध्यम से आमजनों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

- **लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना**: रूपये **215.00 करोड़** रूपये की लागत से **400 शय्या** क्षमता वाले हड्डी रोग अतिविशिष्ट (सुपर स्पेशियलिटी) अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को इस वित्तीय वर्ष तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

- राज्य में अतिविशिष्ट चिकित्सा हेतु **नेत्र रोग** के लिए **राजेन्द्रनगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल** एवं **हृदय रोग** के लिए **इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान** नये भवनों में क्रियाशील है।

- **मधुमेह** एवं अन्य **अंतःस्रावी (Endocrine)** रोगों के लिए अतिविशिष्ट अस्पताल **न्यू गार्डिनर रोड, पटना** को भी **100 शय्या** के नये अस्पताल के रूप में उत्क्रमित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में आरंभ किये जाने का लक्ष्य है।

- **राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, भागन बिगहा, रहुई, नालन्दा** – राज्य में दंत चिकित्सा एवं शिक्षा को विस्तार प्रदान करते हुए राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना– भागनबिगहा, रहुई, नालन्दा का निर्माण कराया गया है। उक्त महाविद्यालय में प्रतिवर्ष **100 नामांकन** एवं **100 शैय्या** के सामान्य अस्पताल क्रियाशील है।

- **बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान (BIMHAS), कोईलवर, भोजपुर**:– बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान (BIMHAS) के माध्यम से वर्ष 2022 से मानसिक रोगियों को सेवायें दी जा रही है। इस संस्थान के माध्यम से छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में उच्चत्तर शिक्षण तथा राज्य एवं निकटवर्ती राज्यों के मानसिक रोगियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में अंतः एवं बाह्य कक्ष सेवायें, जाँच, ECT, मनोवैज्ञानिक के माध्यम से काउन्सलिंग एवं टेलीमेडिसिन (टेली मानस) सुविधा सहित दीदी की रसोई के माध्यम से मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की सुविधा उपलब्ध है। **बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (संशोधन) नियमावली 2023** भी बनाई गई है।

- **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना** – राज्य की जनता को अतिविशिष्ट चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में **रुपये 513.21**

करोड़ की लागत से अतिरिक्त **1200 बेड** के नये अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो अंतिम चरण है। इन निर्माण कार्यों से कुल **3000 बेड** का अस्पताल हो जाएगा। साथ ही **रू० 284.18 करोड़** की लागत से **अतिरिक्त 500 बेड** के नये भवन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त IGIMS परिसर में **क्षेत्रीय चक्षु संस्थान** का नया भवन विगत 02 वर्षों से क्रियाशील है, जहाँ राज्य के लोगों को अतिविशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही **आई. बैंक** एवं अत्याधुनिक **किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट** भी संचालित है।

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटनाः–

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में पटना के मीठापुर में **'बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय'** की स्थापना की गयी। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार हैं तथा दिनांक 01.04.2023 से राज्य के सभी सरकारी/निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थान इससे संबद्ध किए गये हैं। सात निश्चय–2 के अंतर्गत **रू० 138.19 करोड़** की लागत से नए एवं आधुनिक भवन का निर्माण प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। भवन पूर्ण होने के पश्चात् Nursing, Paramedical, Dental, MBBS एवं PG पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक संचालन एवं अनुश्रवण में सुविधा उपलब्ध होगी।

लोक निजी भागीदारी (PPP) के तहत अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, कंकड़बाग, पटना की स्थापनाः–

राज्य में आमजनों को नेत्र की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **शंकरा आई फाउण्डेशन इंडिया, कोयम्बटूर, तमिलनाडु** के द्वारा **अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, कंकड़बाग, पटना** की स्थापना की आधारशिला रखी गयी है तथा निर्माण कार्य जारी है। इसके पूर्ण होने से राज्य अंतर्गत गरीब नेत्र रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा मुफ्त में उपलब्ध होगी।

सदर अस्पतालः–

- राज्य के 25 सदर अस्पताल यथा–आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, रोहतास, नालंदा, सीवान, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, कटिहार, जहानाबाद एवं नवादा को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने का कार्य प्रगति पर है।
- जिसमें से 21 सदर अस्पताल यथा– आरा, अररिया, वैशाली, बांका, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा, सिवान, भागलपुर, कटिहार, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, मधेपुरा, रोहतास, बेगूसराय, औरंगाबाद एवं गोपालगंज के मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- शेष 04 सदर अस्पताल यथा– जहानाबाद, समस्तीपुर, सारण एवं नवादा के मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

अनुमण्डलीय अस्पतालः –

- राज्य में कुल 55 अनुमण्डलीय अस्पताल संचालित है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैर आच्छादित 19 अनुमण्डलों में अनुमण्डलीय अस्पतालों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रः–

- प्रखण्ड स्तर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (अनुमण्डल तथा जिला मुख्यालय स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को छोड़कर) को 6 बेड से बढ़ाकर 30 बेड क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उत्क्रमित करने का कार्य प्रगति पर है।

- वर्तमान में कुल 474 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से अब तक 379 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रः–

- राज्य में कुल 1433 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 1204 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में संचालित है।

- वर्ष 2025–26 में 214 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर :–

- राज्य में कुल 14627 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, इनमें से कुल 10,417 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में संचालित है। इन स्वास्थ्य उपकेन्द्र / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में से 7920 सरकारी भवन में क्रियाशील है। वर्त्तमान में 594 के भवन निर्माण का कार्य प्रगति में है।

सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / रेफरल अस्पताल में MGPS का कार्यः–

राज्य के 239 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / रेफरल अस्पतालों में मेडिकल गैस पाईप लाईन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ट्रॉमा सेन्टर :–

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजमार्गों के निकट ट्रॉमा सेन्टरों की स्थापना एवं निकटवर्ती राजकीय अस्पतालों में ट्रॉमा सेन्टर सुविधा उपलब्ध करने हेतु स्वास्थ्य विभाग प्रयत्नशील है।

इसी क्रम में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पटना जिलान्तर्गत बिक्रम, कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ एवं औरंगाबाद जिला में ट्रॉमा सेन्टर के नये भवन के निर्माण हेतु कुल रु0 28.92 करोड़ (9.64 करोड़ x 3) की लागत वाली योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। औरंगाबाद में निर्माण कार्य जारी है।

मातृ एवं शिशु अस्पताल :–

राज्य में कुल **22 मातृ शिशु अस्पतालों** के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, गया एवं पटना सहित **18** जिलों में चिन्हित अस्पतालों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष अस्पतालों का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य है। साथ ही **शिवहर** में भी पुराने सदर अस्पताल परिसर में **मातृ एवं शिशु अस्पताल** के नये भवन का निर्माण कार्य जारी है।

औषधि भंडार गृह :–

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों की संख्या तथा आवश्यक दवाओं की सूची में वृद्धि के दृष्टिगत नये औषधि भंडार गृहों के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई एवं इस क्रम में राज्य के **38** जिलों में नये **जिला औषधि भंडार गृह** एवं **06 क्षेत्रीय औषधि भंडार गृहों** के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भूमि उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

क्रिटिकल केयर भवन :–

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को उच्च गुणवत्ता एवं मानकीकृत विशिष्ट गहन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के **38 क्रिटिकल केयर भवन** के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भूमि उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नर्सिंग, फार्मेसी एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

महोदय,

नर्सिंग प्रक्षेत्र को सुदृढ़ और सबल बनाने हेतु नर्सिंग से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों का भी सुदृढ़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:–

."विकसित बिहार के सात निश्चय" कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी अनुमंडलों में ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी जिलों में जी०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।

ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान :–

उक्त क्रम में **52 ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान** का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, **02** संस्थानों यथा– **पुपरी (सीतामढ़ी)** एवं **तेघड़ा (बेगूसराय)** में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

जी०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास भवन :–

"विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत ही राज्य के **23** जिलों में **जी०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास भवन** निर्माण किया जाना है, जिनमें से 19 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, **04** संस्थानों यथा– **शिवहर, बेगूसराय, समस्तीपुर** एवं **औरंगाबाद** में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण करा लेने का लक्ष्य है।

बी०एस०सी० नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास भवन :–

- "विकसित बिहार के सात निश्चय" कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में नर्सिंग शिक्षा के फैकल्टी तथा नर्सिंग सेवाओं हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के **16** चिकित्सा महाविद्यालयों में **बी०एस०सी० नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास** भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

- इस क्रम में **पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, भागलपुर, गया, पावापुरी (नालन्दा), सारण, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा** एवं **पूर्णिया** स्थित **09 चिकित्सा महाविद्यालयों** में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष **06** स्थलों यथा– **वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, भोजपुर, बेगूसराय** एवं **मधुबनी** में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- 01 अन्य **बी०एस०सी० नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास सिवान** का भी निर्माण कार्य जारी है।

पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास भवन :–

विकसित बिहार के संकल्प के अंतर्गत राज्य के **28** जिलों में **पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान–सह–छात्रावास भवन** का निर्माण किया जाना है, जिनमें से **24** जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष **04** जिलों– **शिवहर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद** एवं **बेगूसराय** में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के अस्पतालों में तकनीकी सहायकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिनमें लैब टेक्नीशियन, ओ०टी० असिस्टेंट, एक्स–रे टेक्नीशियन एवं डेंटल टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन से राज्य में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा नर्सिंग सेवाओं हेतु आवश्यक मानव बल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय :–

पाँच (5) **राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय** में **डी० फार्मा** के लिए कुल **300 सीट** स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त **राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ पटना** में **बी० फार्मा** के लिए **100 सीट**

एवं **एम० फार्मा** के लिए **21 सीट** स्वीकृत किये गये हैं। सरकार के सात निश्चय प्रथम चरण के अंतर्गत **चार (4) फार्मेसी संस्थान पूर्ण** किया जा चुका है। शेष **एक संस्थान (समस्तीपुर)** में भी **निर्माण कार्य शीघ्र** पूर्ण करने एवं पाठ्यक्रम संचालन की कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों का क्रय

महोदय,

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य के सभी स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों का क्रय कर आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है।

औषधि:–

- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क **दवाओं की उपलब्धता** सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा वर्तमान में **330 दवाओं** का **दर अनुबंध** किया गया है।
- साथ ही वर्तमान में **122 सर्जिकल सामग्रियों/कन्ज्यूमेबल्स** हेतु दर अनुबंध किया गया है जिसकी आपूर्ति की जा रही है।
- सवाईकल कैंसर के रोकथाम हेतु **HPV Vaccine** की आपूर्ति कर राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण की जा रही है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा कुल 446.32 करोड़ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कुल **461 करोड़** अर्थात् कुल **907.32 करोड़** रूपये की औषधियों की आपूर्ति सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है।

उपकरण :–

राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अधियाचना के अनुरूप उपकरणों की उपलब्धता निगम द्वारा सुनिश्चित कराई जा रही है।

- सभी **सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों** में **CT Scan मशीन** एवं **37** जिलों (जहानाबाद जिला को छोड़कर) में **CT Scan मशीन** कार्यरत है। जहानाबाद जिला में भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत सीटी स्कैन मशीन अधिष्ठापन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी।
- **एक्स–रे की सुविधा:** वर्त्तमान में कुल 493 स्वास्थ्य संस्थानों (जिला अस्पताल/अनुमण्डलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थल तक) में निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

- Diagnostic सेवा के क्षेत्र में पूर्व से ही जाँच से संबंधित उपकरण यथा **Blood Cell Counter 3 Part, Blood Cell Counter 5 Part, Fully Auto Analyzer, Semi Auto Analyzer, ABG Gas Analyzer, Coagulation Analyzer, Elisa Reader with Washer & Ultra Sound Machine** इत्यादि उपलब्ध है।

- सात निश्चय कार्यक्रम अतंर्गत **19 जी.एन.एम. स्कूल, 52 ए.एन.एम. स्कूल** एवं **10 बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज** में Turnkey Basis पर उपकरणों /प्रयोगशाला के अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था, जिसके आलोक में फर्म द्वारा **17 जी.एन.एम. स्कूल, 50 ए.एन.एम. स्कूल** एवं **08 बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज** में आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष स्वास्थ्य संस्थानों में आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत **04** जिलों (**नालन्दा, बांका, सिवान** एवं **रोहतास**) के **फार्मेसी स्वास्थ्य संस्थानों** में Turnkey Basis पर उपकरणों/प्रयोगशाला के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- सात निश्चय कार्यक्रम अतंर्गत **20** जिलों के **पारामेडिकल स्वास्थ्य संस्थानों** में Turn-key basis पर उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- **दंत चिकित्सा** के क्षेत्र में भी **Dental Chair** का अधिष्ठापन **अनुमंडलीय अस्पताल** सहित सभी **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों** के स्तर तक कराया जा चुका है।

- **श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ** तथा **दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, रहुई, नालंदा** हेतु Turnkey Basis पर उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उपकरणों की आपूर्त्ति/अधिष्ठापन की जा रही है।

- **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण)** में उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु आपूर्त्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है। साथ ही उपकरणों की आपूर्त्ति/अधिष्ठापन की जा रही है।

- **जे.एल.एन.एम.सी.एच. भागलपुर** एवं **एस.के.एम.सी.एच. मुजफ्फरपुर** में **Blood Sample Collection Centre** की स्थापना की जा चुकी है।

- **दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय** के नवनिर्मित **Surgical Block** एवं **MCH Block** में विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जा चुका है।

- **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, आरा (भोजपुर)** एवं **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सीतामढ़ी** में उपकरणों का क्रय Turnkey Basis पर करने हेतु फर्म को क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है।

- **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, महुआ (वैशाली)** एवं **राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधुबनी** में उपकरणों का क्रय Turnkey Basis पर करने हेतु फर्म को क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है।

- **लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना** में **CT Scan** एवं **MRI Machine** का अधिष्ठापन पूर्ण किया जा चुका है।

- **बिहार औषधि नियंत्रक प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना** हेतु औषधि के सैम्पल की जाँच के लिए Turnkey Basis पर **28 प्रकार के उपकरणों** की आपूर्ति/अधिष्ठापन किया जा चुका है।

सरकारी अस्पतालों को विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों से सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा 88.96 करोड़ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 24.99 करोड़ कुल 113.95 करोड़ रू0 के उपकरणों की आपूर्त्ति की गई है।

मानव संसाधन बल का विकास और विस्तार

महोदय,

अब मैं, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी पदों पर नियुक्तियों के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में की गई नियमित नियुक्तियाँ :–

- **विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी** के **1,126** (मूर्च्छक–184, चर्म रोग–23, ई.एन.टी.–46, नेत्र रोग–36, जेनरल सर्जन–234, स्त्री रोग–260, माईक्रोबायोलॉजी–15, शिशु रोग–208, पैथोलॉजी–60, मनोचिकित्सक–11 एवं रेडियोलॉजी–49) एवं **सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी** के **597** अर्थात् कुल **1,723** पदों पर नियुक्ति कर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।

- **ए0एन0एम0** के **7,468 पदों पर मई, 2025 में नियुक्ति कर** विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में **पदस्थापन किया जा चुका है।**

- **कीट संग्रहकर्ता (फाईलेरिया)** के **53** रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति की जा चुकी है।

- इस प्रकार विभिन्न तकनीकी पदों पर राज्य में **कुल 9,244 नियमित नियुक्तियाँ** एवं टेन्योर पद पर 1458 नियुक्तियाँ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में की गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रक्रियाधीन नियमित नियुक्तियाँ :–

- राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में रिक्त **1711 सहायक प्राध्यापक** के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु **बिहार लोक सेवा आयोग** के स्तर से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- आयुष प्रक्षेत्र अंतर्गत **सहायक प्राध्यापक (होम्योपैथ)** के **18**, **सहायक प्राध्यापक (यूनानी)** के **15** एवं **सहायक प्राध्यापक (आयुर्वेद)** के **88** अर्थात् आयुष प्रक्षेत्र में कुल **121** सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है, जो प्रक्रियाधीन है।
- बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत **विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन)** के **304** पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्तर से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- **सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर (टेन्योर)** के कुल–**1047 पदों पर चिकित्सकों** की नियुक्ति हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड को अधियाचना भेजी गई है। टेन्योर के पद पर पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- **जुनियर रेजिडेन्ट** के कुल **1,445 पदों पर** नियुक्ति हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड को अधियाचना भेजी गई, जो प्रक्रियाधीन है।
- इसके अतिरिक्त **दन्त चिकित्सक** के **808** पदों पर नियमित **नियुक्ति हेतु** बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्तर से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- **ट्यूटर (नर्सिंग)** के **498**, **परिचारिका श्रेणी 'ए' (स्टाफ नर्स/जी0एन0एम0)** के **11,389** तथा **8,938 ए.एन.एम.** के पदों अर्थात् कुल **20,825** पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्तर से प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में **फार्मासिस्ट** के **2473** एवं **परिघापक** के **3326**, **एक्स–रे टेक्नीशियन** के **1232**, **शल्य कक्ष सहायक** के **1683**, **ई0सी0जी0 टेक्नीशियन** के **242**, **दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 702 तथा प्रयोगशाला प्रावैधिक** के **2969 अर्थात्** कुल–**12,627** रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति हेतु **बिहार तकनीकी सेवा आयोग** के स्तर से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में **फाईलेरिया निरीक्षक** के **69** पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है, जो संबंधित आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

- इसके अतिरिक्त **खाद्य संरक्षा अधिकारी** के **105**, **खाद्य विश्लेषक** के **10**, **सहायक जीवाणुविद** के **3**, **वैज्ञानिक सहायक** के **6**, **टेक्नीशियन** के **10**, **सरकारी विश्लेषक** के **4** अर्थात् **138** पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है, जो प्रक्रियाधीन है।

- इस प्रकार विभिन्न संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न **तकनीकी पदों** पर **कुल 36,934** नियमित नियुक्तियाँ एवं कुल 2492 टेन्योर पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है।

- इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग से **प्राध्यापक** के **269** तथा **सहायक प्राध्यापक** के **655** अर्थात् कुल **927** पदों पर संविदागत नियोजन की कार्रवाई जारी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अन्तर्गत नियुक्तियाँ :–

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में **6,297** पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। इनमें **विशेषज्ञ चिकित्सक** के **228**, **सामान्य चिकित्सक** के **1104**, **आयुष चिकित्सक** के **1283** एवं **Community Health Officer** के **3,682** पद शामिल हैं।

- वर्त्तमान में **ANM** के **5,006** एवं **नेत्र सहायक** के **220** पदों पर नियोजन प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

- इस प्रकार, मानव संसाधन बल को सुदृढ़ करने की दिशा में विगत 5–6 वर्षों में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा NHM अन्तर्गत विभिन्न पदों पर कुल **27,275** अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

महोदय,

मानव बल के क्षमता विकास और दक्षता संवर्धन को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से NHM कर्मियों के मानदेय वृद्धि, निजी स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता आशा और ममता के हित को ध्यान में रखते हुए कई पहल किये गये हैं–

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के हित में **स्वास्थ्य बीमा योजना** का लाभ कर्मियों को दिया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों से राज्य के **लगभग 21,000 NHM कर्मियों** को **5 लाख रूपये** तक का **स्वास्थ्य बीमा** एवं **50 लाख रूपये** तक का **दुर्घटना बीमा** का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

- स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2025 में **149 कर्मी** लाभान्वित हो चुके हैं। लगभग **1,33,77,848/–** (कुल एक करोड़ तैतीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ अड़तालीस रू०/मात्र) का **Medical Claim** दिया गया है। **Personal Accidental Death Policy** के अंतर्गत **तीन कर्मियों** को **1,38,00,000/–** (कुल एक करोड़ अड़तीस लाख रू०/मात्र) का लाभ दिया गया है।

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक मृत्यु के कारण **दो कर्मी** को **पाँच–पाँच लाख रूपये** का Term Plan दिया गया है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का मनोबल बढ़ाने एवं प्रभावी कार्य संस्कृति को विकसित करने हेतु NHM अंतर्गत **दिनांक 01.09.2025 के प्रभाव से आहरित मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन राशि** के रूप में राज्य योजना मद से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मानदेय / पारितोषिक राशि में वृद्धि

- **ममता**, जो सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिला, प्रसूता से लेकर नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान को बढ़ावा देने इत्यादि का कार्य करती है, के मानदेय में 300/– रू0 प्रति प्रसव प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर **600/– रू0 प्रति प्रसव** की राशि दिनांक 1 जुलाई, 2025 से दी जा रही है।
- **आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता** को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनके **पारितोषिक राशि** को रूपये 1000/– से बढ़ाकर **रूपये 3000/–** कर दिया गया है।

गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में सुधार

औषधि एवं जाँच की सुविधा

स्वास्थ्य संस्थानों में औषधि की उपलब्धता :–

सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की संख्या में चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता के अनुसार वृद्धि की जाती रही है। फलस्वरूप वर्तमान में 'आवश्यक दवाओं की सूची' में 503 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाईसेज / कन्ज्यूमेबल शामिल है।

सदर अस्पताल से हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर तक दवा उपलब्धता की स्थिति :–

- स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की कड़ी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में 350 से अधिक प्रकार की दवायें, अनुमण्डलीय अस्पताल में 250 से

अधिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 240 से अधिक, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में 150 तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में 120 प्रकार की दवायें उपलब्ध है।

मुफ्त औषधि वाहन :–

जिलान्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सभी जिलों में जीपीएस से लैस 180 मुफ्त औषधि वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत सरकार के DVDMS Central Dashboard पर **औषधियों की आपूर्त्ति एवं वितरण में बिहार सितम्बर, 2024 से अर्थात् विगत 17 माह से प्रथम स्थान** को बनाये हुए है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) पर औषधि एवं जाँच की सुविधा :–

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सात निश्चय–2 के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक प्राथमिक उपचार से लेकर विभिन्न रोगों की स्क्रीनिंग व जाँच, लगभग 120 प्रकार की दवायें, लगभग 12 प्रकार के जाँच, विभिन्न प्रकार के परामर्श इत्यादि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप औसतन प्रतिमाह प्रति संस्थान लगभग 332 मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के जाँच की अद्यतन स्थिति

डायलेसिस सेवा :–

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के हित में **डायलेसिस** की सुविधा राशन कार्डधारी मरीजों को निःशुल्क तथा अन्य रोगियों को सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दर पर उपलब्ध है। दिसम्बर, 2020 से संचालित डायलिसिस सुविधा के अंतर्गत दिसम्बर, 2020 से जनवरी, 2026 तक कुल 9,25,962 डायलिसिस सेशन प्रदान किये गये हैं। वहीं अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 तक कुल 2,33,169 डायलिसिस सेशन की सुविधा मरीजों को दी गई है।

ई.सी.जी. सेवाएं (ECG):–

जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक 592 स्वास्थ्य संस्थानों (सभी 35 जिला अस्पतालों, सभी 55 अनुमंडलीय अस्पतालों, सभी 45 रेफरल अस्पतालों, 327 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 81 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 49 पोली क्लिनिक पर निःशुल्क **ई.सी.जी. सेवाएं** उपलब्ध करायी जा रही है। अप्रैल, 2025 से जनवरी, 2026 तक **2,96,602** मरीजों को ई.सी.जी. की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है।

अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा :–

मातृ एवं सामान्य रोगियों को राज्य में 186 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा देकर लाभान्वित किया जा रहा है। स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ का पदस्थापन के पश्चात् 76 अतिरिक्त संस्थानों में यथाशीघ्र अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा शीघ्र ही आरंभ कर दी जायेगी।

पैथोलॉजी सुविधायें :–

राज्य के सरकारी अस्पतालों यथा– जिला अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक पैथोलॉजी जाँच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। पैथोलॉजी जाँच की सुविधा Fully Auto Biochemistry Analyser, Semi-Auto Biochemistry Analyser, 3-Part Complete Blood Cell (CBC) Analyser, ABG Analyser, Electrolyte Analyser, Binocular LED Microscope & ELISA Machine एवं रैपिड किट के माध्यम से मरीजों को मुफ्त उपलब्ध करायी जा रही है।

एक्स–रे जाँच की सुविधा :–

वर्तमान में कुल 493 स्वास्थ्य संस्थानों (जिला अस्पताल/रेफरल अस्पताल/ अनुमंडलीय अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक) में **एक्स–रे जाँच** की सुविधा उपलब्ध है। दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2025 तक **26,51,725** एक्स–रे की सुविधा दी गई है।

इसके अतिरिक्त 19 जिलों के सदर अस्पतालों में अवस्थित SNCU में भी लोक निजी साझेदारी के तहत एक्स–रे संचालित है एवं शेष 16 में अधिष्ठापन कार्य प्रक्रियाधीन है।

रेफरल ट्रांसपोर्ट (एम्बुलेंस की सुविधा) :–

आपातकालीन एवं सरकारी अस्पतालों में मरीजों के आवागमन हेतु निःशुल्क रेफरल ट्रांसपोर्ट (एम्बुलेंस) की सुविधा है। आमजन को बीमारी, दुर्घटना या अन्य किसी आपातकालीन स्थिति में मरीज के ईलाज हेतु टॉल फ्री नं० 102 के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में 1941 एम्बुलेंस (BLSA-1268, ALSA-567 & Mortuary Van-106) संचालित है। एक माह के अंदर टॉल फ्री सेवा 102 के तहत एम्बुलेंस के बेड़े में 124 अतिरिक्त एम्बुलेंस जुड़ जाएंगे। इस प्रकार नये 124 एम्बुलेस के शामिल होने से एम्बुलेंस की कुल संख्या बढ़कर 2,065 हो जाएगी।

विगत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 14,30,373 मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी, वहीं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जनवरी, 2026 तक 15,94,220 मरीजों को यह सेवा प्रदान की गई है।

नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण :–

राज्य में प्रखंड स्तर तक 440 संस्थानों में नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण किया जा रहा है। दिसम्बर, 2025 तक 8,62,421 व्यक्तियों का नेत्र परीक्षण किया गया है, जिसके उपरांत 1,99,374 दृष्टि दोष मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरित किये गये हैं। 26 जिला अस्पतालों एवं राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल में मोतियाबिन्द ऑपरेशन कराये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित

लक्ष्य 5,55,000 के विरूद्ध दिसम्बर, 2025 तक 4,11,614 मोतियाबिन्द ऑपेरशन सम्पन्न हो चुका है, शेष लक्ष्य निर्धारित अवधि तक प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

रक्त केन्द्र तथा रक्त संग्रहण इकाई :–

- उपचार एवं आपात स्थिति में आवश्यक सहयोगी सेवा के तहत् राज्य में 06 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों (PMCH Patna, SKMCH, Muzaffarpur, JLNMCH, Bhagalpur, AIIMS, Patna, GMC, Purnea एवं ANMCH Gaya) में थैलेसीमिया एवं हिमोफीलिया के मरीजों के ईलाज हेतु 'डे केयर सेंटर' स्थापित है।

- वहीं राज्य में रक्त की उपलब्धता आमजनों तक पहुँचाने के लिए रक्त–केंद्र एवं रक्त–संग्रहण इकाई स्थापित है, जिसकी संख्या को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 129 रक्त केन्द्र तथा 86 रक्त संग्रहण इकाई क्रियाशील है।

सभी रक्त केन्द्रों में रक्त की उपलब्धता संबंधी जानकारी हेतु e-Raktkosh Portal मोबाईल एप कार्यरत है।

महोदय,

राज्य में नारी शक्ति को समाज में उभारने और आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने हेतु कई महत्वाकांक्षी पहल राज्य स्तर से किये गये हैं–

जीविका के साथ अभिसरण (Convergence) एवं महिला सशक्तिकरण :–

जीविका के साथ अभिसरण (Convergence) एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के **96** स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को गुणवत्तायुक्त आहार हेतु **'जीविका दीदी की रसोई'**, **48** स्वास्थ्य संस्थानों में **साफ–सफाई** की व्यवस्था, **45** संस्थानों में **लॉण्ड्री सेवायें तथा सभी जिला अस्पतालों** में अंदर एवं बाहर साफ–सफाई की व्यवस्था जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल का परिणाम है कि महिला आज इतनी सशक्त होकर उभरी है कि पुरूषों के सहयोग के बिना स्वयं सारी व्यवस्थाओं का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन कर रही है।

राज्य में लागू नई नीतियाँ/योजना

नई रेफरल नीति :–

राज्य के फील्ड अस्पतालों के मरीजों को पटना के अस्पतालों/अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अनावश्यक रूप से रेफर करने की आदत को दूर करने के निमित्त राज्य में **नई रेफरल नीति** बनाकर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेफर करने का कार्य किया गया है, ताकि एम्बुलेंस सेवा एवं सेकेण्डरी एवं टर्सियरी सेक्टर पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़े और मरीजों को भी परेशानी नहीं हो।

तिथिवाद औषधि निस्तारण नीति :–

आवश्यक औषधियों की संख्या एवं औषधियों की आपूर्त्ति एवं खपत में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप कालातीत एवं क्षतिग्रस्त औषधियों के निस्तारण/विनष्टीकरण हेतु Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 के तहत औषधियों एवं अपशिष्ट के निस्तारण / विनष्टीकरण हेतु तिथिवाद औषधि निस्तारण नीति लागू की गई है।

जैव चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं मरम्मति योजना (BMMP):-

राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित चिकित्सीय उपकरणों के रख–रखाव हेतु जैव चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं मरम्मति योजना क्रियान्वित है, जिससे कि राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित चिकित्सीय उपकरण निर्बाध रूप से क्रियाशील रहे। उपकरणों में खराबी आने पर शिकायत दर्ज करने हेतु केन्द्रीयकृत रूप से टॉल फ्री नं० 18001028682 पर डायल कर समाधान करने की व्यवस्था है।

देशी चिकित्सा पद्धति की प्रगति

राज्य की सबसे पौराणिक एवं पारम्परिक चिकित्सा पद्धति आयुष चिकित्सा (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथ) को बढ़ावा देने हेतु सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

- **नबाव मंजिल, पटना सिटी** में **50 शय्या का Integrated Hospital** का निर्माण कराया गया है।
- **राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल** पटना जिलान्तर्गत अगमकुआँ के नवीन परिसर में **200 शैय्या अस्पताल** तथा **150 नामांकन क्षमता** वाले **चिकित्सा महाविद्यालय के भवन एवं छात्रावास भवन** के निर्माण हेतु **रू0 248.07 करोड़** की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा** का कुल **रू0 195.63 करोड़** (एक सौ पन्चानवे करोड़ तिरसठ लाख रूपये) की लागत से निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृति प्राप्त है, उक्त संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
- **राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल–सह–चिकित्सालय बेगूसराय का** कुल **रू0 238.99 करोड़** (दो सौ अड़तीस करोड़ निन्यानवे लाख रूपये) की लागत पर निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृति प्राप्त है। उक्त निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इसे आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

- **राजकीय रायबहादुर दुन्की साह होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर** का कुल **रू0 121.01 करोड़** (रु0 एक सौ इक्कीस करोड़ एक लाख) की लागत से **120 नामांकन क्षमता** वाले **होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, 134 शैय्या का अस्पताल, 336 बेड** के **छात्रावास एवं आवासीय भवनों** के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। उक्त का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

- इसके अतिरिक्त **बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण** एवं **गया** में **50 शैय्या** वाले **आयुष अस्पताल** की योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त **10 शैय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, अररिया, बांका एवं मधुबनी** की स्थापना से राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति द्वारा जनमानस को आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने की आगामी योजना है।

- **राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना** तथा **राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर** में **स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** में सैकड़ों छात्र–छात्राओं का नामांकन हो रहा है।

- राज्य में **आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला संयुक्त औषधालय, राजकीय औषधालय** एवं **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष)** के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क पौराणिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करायी जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में **दिसम्बर, 2025** तक **18,51,379 मरीजों** को आयुष पद्धति से चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी गयी है।

कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति

- राज्य में सामान्य कैंसर (मुँह, स्तन एवं गर्भाशय का मुख) की स्क्रीनिंग, प्रारम्भिक जाँच एवं उससे बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है।

- कैंसर के Advance Stage वाले मरीजों को Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए 100 शैय्या वाले Model Palliative Care Center की स्थापना भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर में की जा रही है, जो देश का पहला सरकारी 100 शैय्या का पूर्णतः Palliative Care के लिए समर्पित केन्द्र होगा।

- राज्य में **सिर, मुँह एवं गर्दन के कैंसर** से पीड़ित मरीजों के ईलाज हेतु **100 शैय्या वाले अस्पताल का गंगवारा, दरभंगा में निर्माण** किया जा रहा है।

- स्क्रीनिंग में संदेहास्पद पाये गये मरीजों को उपचार हेतु होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (HBCH&RC), मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों (State Cancer

Institute, IGIMS, AIIMS, पटना, महावीर कैंसर संस्थान, पटना सहित राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल) में रेफर किया जा रहा है।

- मुजफ्फरपुर में **425 करोड़ रूपये** की लागत से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र के नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं क्रियाशील है।

- साथ ही, राज्य के 29 जिलों में Day Care Cancer Centre (DCCC) का भी संचालन किया जा रहा है। इन DCCC में माह जनवरी, 2026 तक कुल 3043 रोगियों का निःशुल्क Chemotherapy प्रतिवेदित है। शेष 09 जिलों में भी यथाशीघ्र DCCC क्रियाशील करने की कार्रवाई की जा रही है।

- **इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS)** में अवस्थित **स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट** द्वारा भी कैंसर से पीड़ित मरीजों को विशिष्ट चिकित्सीय उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना– 687(12), दिनांक– 23.05.2025 के तहत् राज्य में **बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाईटी** का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कैंसर रोग की रोकथाम, समुचित ईलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन एवं कैंसर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

- **लोक निजी भागीदारी (PPP) के तहत अतिविशिष्ट चिकित्सा सेवा की व्यवस्था–**

  राज्य में आमजनों को नेत्र की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **शंकरा आई फाउण्डेशन इंडिया, कोयम्बटूर, तमिलनाडु** के द्वारा अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, कंकड़बाग, पटना की स्थापना की आधारशिला रखी गयी है तथा निर्माण कार्य जारी है।

- बिहार के मरीजों को राज्य के अंदर ही प्रतिष्ठित अति विशिष्ट निजी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से उच्चस्तरीय चिकित्सीय सेवाएं सुलभ हो, के उद्देश्य की पूर्ति हेतु **जय प्रभा मेंदाता, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, कंकड़बाग, पटना** में क्रियाशील है, जहाँ रेफर किये गये गरीब मरीजों एवं आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को राज्य सरकार की लागत पर मुफ्त उपचार तथा अन्य को निर्धारित दर पर उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

- **'मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना'** अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान, **CMC वेल्लोर, तमिलनाडू** में थैलेसीमिया के चिन्हित मरीजों का निःशुल्क ईलाज सरकारी व्यय पर कराया जा रहा है।

- **बाल हृदय रोगियों** के दिल में छेद के साथ जन्में बच्चों का निःशुल्क इलाज **प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउन्डेशन, अहमदाबाद** के माध्यम से कराया जा रहा है।

नई तकनीकी युक्त आधुनिक पहल

महोदय,

स्वास्थ्य सेवा नित्य नये–नये आयामों को अपनाकर डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, जो निम्नवत् है –

'कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर':–

राज्य के स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियों को एकल मंच पर लाकर मुख्यालय में स्थापित 'कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर' के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाओं को राज्य स्तर से सीसीटीवी के माध्यम से सतत् अनुश्रवण एवं निगरानी की जा रही है और आँकड़ों को संग्रहित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मुख्यालय स्तर पर स्थापित 'स्टेट कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर' के माध्यम से मुख्यालय स्तर से स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियों का एकल मंच से अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर "District Command & Control Centre" तथा जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक "Data Analytic Centre" स्थापित किये गये हैं, जहाँ से आवश्यकतानुसार सहज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर त्वरित सूचनाओं का आदान–प्रदान एवं समय–समय पर स्वास्थ्य आपदाओं पर नियंत्रण की तैयारी एवं अनुश्रवण किया जाता है।

मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना Bihar Health Application Visionary Yojana For All (BHAVYA):–

"मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" अंतर्गत भव्या, जो भव्या एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) कॉम्पलाइन्ट HMIS सॉफ्टवेयर है, के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑनलाईन पंजीकरण से लेकर ईलाज की पूरी प्रक्रिया, जाँच इत्यादि सहित दवा वितरण तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे अभिनव तकनीक के फलस्वरूप सरकारी अस्पताल के व्यवस्थित होने से मरीजों के भीड़ प्रबंधन में सुविधा हो रही है और सेवायें सुव्यवस्थित होने से मरीजों को सहजता हो रही है। अब मरीजों के चिकित्सीय रिकॉर्ड मरीज के मोबाईल संख्या या आभा आई.डी. से किसी भी अस्पताल में देखे जा सकते हैं। इससे मरीजों को कागजों के रख–रखाव से भी छुटकारा मिल रहा है। वर्तमान में कुल ओ.पी.डी. का लगभग 95 प्रतिशत डिजिटल ओ.पी.डी. के रूप में पंजीकरण हो रहा है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) :–

- राज्य में कुल 6 करोड़ 11 लाख लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHAआई.डी. बनाया गया है।
- राज्य ने ABDM अंतर्गत स्कैन एण्ड शेयर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कुल 5 करोड़ 26 लाख टोकन का निर्माण करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर **प्रथम स्थान** प्राप्त किया है।

- इस योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA ID) दी जा रही है, जिससे उनकी संपूर्ण चिकित्सा जानकारी डिजिटल रूप से संरक्षित और सुगम हो सके। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 को **भुवनेश्वर** में **बिहार राज्य को राष्ट्रीय सम्मान** प्रदान किया गया।
- अब तक राज्य में कुल 6 करोड़ 17 लाख लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जा चुका है और इस सफल कार्य हेतु **देश में चौथा स्थान** प्राप्त किया है।
- बिहार राज्य के द्वारा कुल 37 करोड़ 60 लाख की प्रोत्साहन राशि का क्लेम किया गया है जो **देश में सर्वाधिक** है।

टेली कन्सलटेशन (Tele Consultation):–

राज्य के दूरवर्त्ती क्षेत्र के निवासियों के साथ–साथ महिला, बुजुर्ग एवं निःशक्त लोगों को कुशल चिकित्सकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने के क्रम में फरवरी, 2021 से दिसम्बर, 2025 तक लगभग 02 करोड़ 82 लाख मरीजों को टेली कन्सलटेशन के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई है। इस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन अनुमानतः 25 हजार मरीजों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

Ashwin Portal एवं m-ASHA ऐपः–

सुगमता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से आशा कार्यकर्त्ता और आशा फैसिलिटेटर को जहाँ एक ओर Ashwin Portal के माध्यम से लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा 68 प्रकार के प्रोत्साहन राशि हेतु 50 से अधिक प्रपत्रों को भरे जाने में आ रही असुविधा को देखते हुए अब आशा बहनों के द्वारा क्रियान्वित विविध कार्यों का ब्यौरा m-ASHA ऐप पर रखने का प्रयास किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

- राज्य के लगभग 1.2 करोड़ राशन कार्डधारी परिवार को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत तथा 58 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। इन परिवारों को 5 लाख रू0 तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष प्रति परिवार अनुमान्य है। अबतक कुल लगभग 1.69 करोड़ परिवारों एवं 4.14 करोड़ पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया जा चुका है।
- आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना अंतर्गत आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तारित कर 70 वर्ष और उससे अधिक अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों हेतु आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना की सुविधा प्रदान की गई है, जिन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रू0 तक का निःशुल्क उपचार अनुमान्य है। अबतक 3.88 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाया गया है।

- अब तक उक्त दोनों योजना अंतर्गत 30.11 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजनान्तर्गत निःशुल्क ईलाज प्रदान किया गया है, जिसमें सन्निहित राशि लगभग 4,402.14 करोड़ रू0 है।
- आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत राज्य में 436 सरकारी एवं 795 निजी अस्पताल अर्थात् कुल 1231 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर बनायी अपनी पहचान

महोदय,

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने सेवा एवं उत्कृष्टता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनायी है, जो निम्नवत् है :

- राज्य का शिशु मृत्यु दर (IMR) SRS 2023 के अनुसार घटकर 23 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत (25) से भी बेहतर अर्थात् 2 अंक कम है।
- नवजात शिशु (जन्म से 28 दिन) मृत्यु दर (Neo-natal Mortality Rate-NMR) Hkh SRS 2023 के अनुसार घटकर 18 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत (19) से बेहतर है।
- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर भी (Under 5 Mortality Rate) SRS 2023 के अनुसार घटकर 27 हो गया है, जो भी राष्ट्रीय औसत (29) से बेहतर अर्थात् 2 अंक कम है।
- भारत सरकार के DVDMS Central Dashboard पर औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण में बिहार सितम्बर, 2024 से अर्थात् विगत 17 माह से प्रथम स्थान पर है।
- वर्तमान में बिहार राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) अंतर्गत **स्कैन एण्ड शेयर** में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कुल **5 करोड़ 26 लाख टोकन** का निर्माण करते हुए **राष्ट्रीय स्तर** पर **प्रथम स्थान** प्राप्त किया है।
- ABDM अंतर्गत **इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड** (EHR) की दिशा में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए देश में **चौथा स्थान** प्राप्त किया है। अब तक राज्य में कुल **6 करोड़ 17 लाख लाभार्थियों का इलेक्ट्रानिक हेल्थ रिकॉर्ड** बन चुका है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा **20 जनवरी 2026** को **भुवनेश्वर** में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में **ABDM के प्रभावी क्रियान्वयन** के लिए बिहार राज्य को **राष्ट्रीय सम्मान** प्रदान किया गया।
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर पाँचवें स्थान पर है।

आगामी कार्य योजना
सात निश्चय–3
("सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन")

महोदय,

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से निम्न सुधार एवं अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा विस्तार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:

- प्रखंड स्तरीय सामान्य स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।
- जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।
- प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना।
- नए मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में बेहतर शिक्षा एवं उपचार के लिए लोक–निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना।
- सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने हेतु आवश्यक नीति का निर्माण करना।
- दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करना।

मैं, सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी नागरिकों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के लिए लगातार प्रयासरत है एवं **सात निश्चय–3** के तहत तय किये गये सभी कार्यों को एक समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दृढ़संकल्पित है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अनुदान मांग संख्या–20 के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 11,237.64 करोड़ रूपये एवं योजना मद में 10,032.77 अर्थात कुल 21,270.41 करोड़ रूपये (इक्कीस हजार दो सौ सत्तर करोड़ इकतालिस लाख रूपये) **की अनुदान मांग की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।**

*****

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान' (दिनांक 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2025) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ

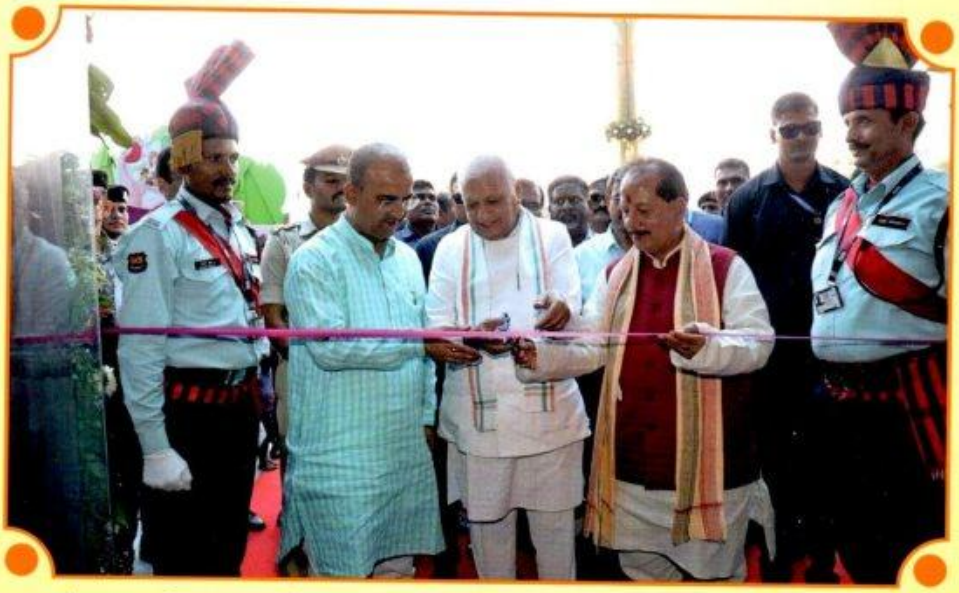

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान' (दिनांक 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2025) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा शुभारंभ के दौरान राज्य स्तर पर आई.जी.आई.एम.एस. में महामहिम राज्यपाल के द्वारा 'ओ.पी.डी. सेवा' का शुभारम्भ

सुलभ स्वास्थ्य -
सुरक्षित जीवन

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा
'झुनझुनवाला शंकरा नेत्र अस्पताल, पटना' का शिलान्यास

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

चतुर्थ एवं पंचम तल, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014
दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : shs.bihar.gov.in

• SHSBihar • BiharHealthDepartment Website shs.bihar.gov.in
• @SHSBihar • @BiharHealthDepartment

Patna Offset Press, Patna